ISSN-0971-8397

वसुधैव कुटुंबकम

आज़ादी का अमृत महोत्सव

योजना

फरवरी 2023

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

युवा एवं खेल

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

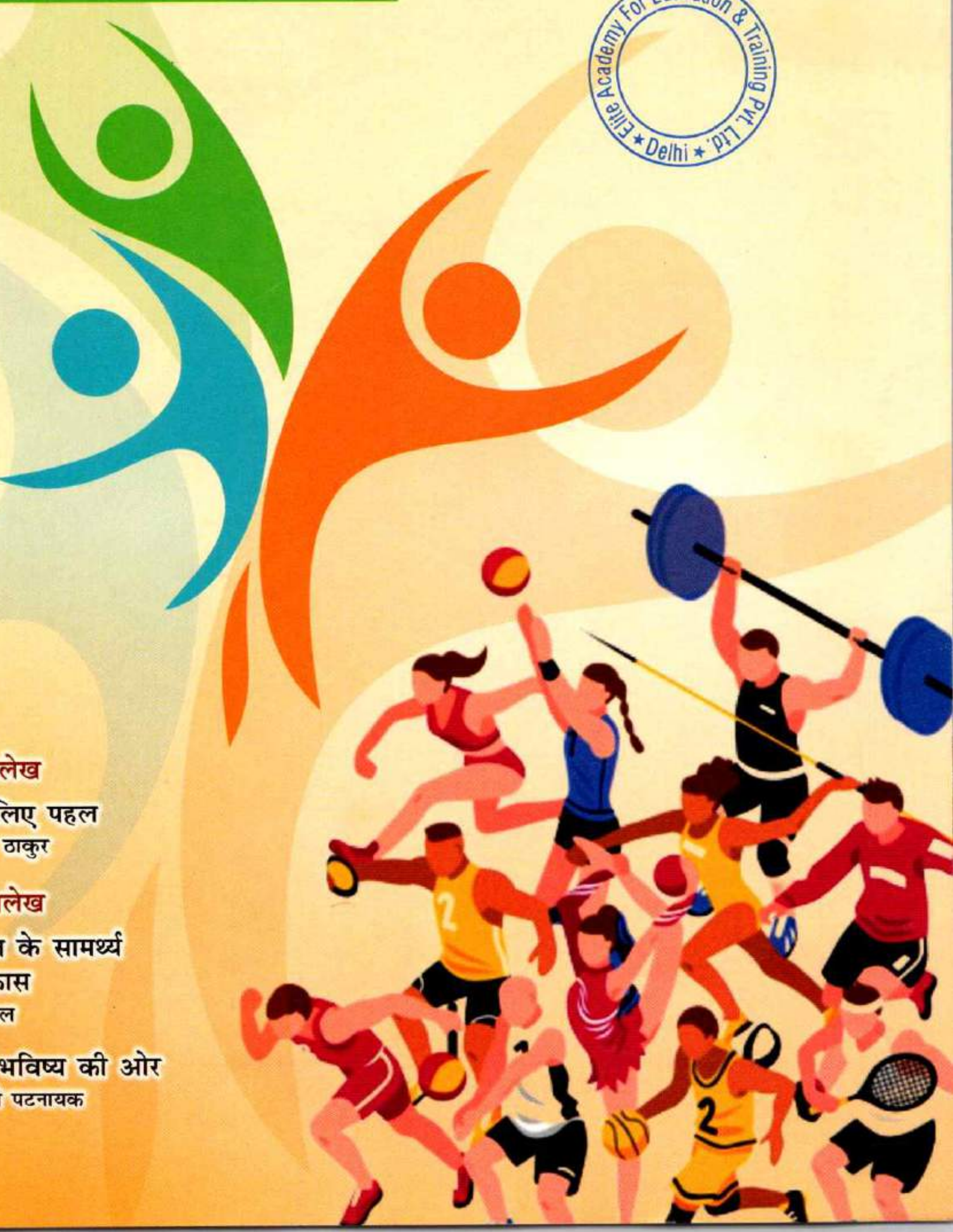

प्रमुख आलेख

नए भारत के लिए पहल
अनुराग सिंह ठाकुर

विशेष आलेख

हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य का विकास
भरत लाल

फिट इंडिया: स्वस्थ भविष्य की ओर
राशि शर्मा, पूरबी पटनायक

ELITE IAS
(A PREMIER INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES PREPARATION)

ARE YOU DREAMING TO BE AN

IAS ?

CRACK UPSC IN 1ST ATTEMPT NOW

Our Offerings

- Personal Mentorship 1:1 by Subject Expert
- GS Integrated Live Classes
- Exclusive NCERT Coverage
- Intergrated Prelims Cum Mains + Essay Test Series
- Weekly Test, Revision and Personal Guidance
- Online/Offline Sessions

TALK TO US

8410000036, 7065202020, 8899999931

BOOK FREE DEMO SESSION www.eliteias.in

ISSN-0971-8397

योजना

वर्ष : 67
अंक : 02

फरवरी 2023
माघ-फाल्गुन, शक संवत् 1944

मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 56

वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

प्रधान संपादक : राकेशरेणु
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डीकेसी हृदयनाथ
आवरण : बिन्दु वर्मा

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-54** पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com
या संपर्क करें-
दूरभाष : 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
नयी दिल्ली-110003

@DPD_India
@publicationsdivision
@dpd_india

इस अंक में

प्रमुख आलेख

नए भारत के लिए पहल
अनुराग सिंह ठाकुर 7

फोकस

युवा और स्वास्थ्य
डॉ चंद्रकांत लहरिया,
डॉ रोडनी वाज़ 21

विशेष आलेख

हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य का विकास
भरत लाल 11

फिट इंडिया: स्वस्थ भविष्य की ओर
राशि शर्मा, पूरबी पटनायक 17

युवाओं के लिये मददगार पहलकदमियां
हेमांग जानी 25

युवाशक्ति और पर्यावरण
अविनाश मिश्र, मधुबंती दत्ता 29

फुटबॉल की दुनिया
शिवेन्द्र चतुर्वेदी 33

डिजिटल अर्थव्यवस्था का नया स्वरूप
बालेंदु शर्मा दाधीच 37

भारत के युवा सितारे 41

जानकारी और संवाद का प्रभावी मंच
आकाश त्रिपाठी 46

मिसाल बनते विभिन्न राज्यों के स्पोर्ट्स आयकन
संजय श्रीवास्तव 49

नियमित स्तंभ

जी-20 अध्यक्षता : 'ऑनलाइन सुरक्षित रहें' अभियान और 'जी-20 डीआईए' का शुभारंभ 48

विकास पथ 55

आगामी अंक : केन्द्रीय बजट

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 24

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अँग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

आपकी राय

yojanahindi-dpd@gov.in

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

धरोहरों का पुनरुद्धार

वास्तुकला पर केन्द्रित योजना का वर्षान्त अंक पठनीय था जिसमें धरोहरों का पुनरुद्धार विशेष आलेख था और इसके मूल में पर्यावरण अनुकूल स्थापत्य का आग्रह था।

हमारे पूर्वज कितने कुशल थे। उनका ज्ञानशिल्प, अगण्य संरचना और निर्माण अचरज में डाल देता है। उनके अद्भुत वास्तु ज्ञान को शेष रखने के लिए हमें ऐतिहासिक शहरों का विकास करना होगा। संरक्षण और पुनरुद्धार को प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। तंजावुर का मंदिर और नंदी की उत्कृष्टता तो वर्णन से परे है।

उचित अनुपात, उपर्युक्त विन्यास और उत्कीर्ण भाव विस्मित करते हैं। आज तो शिल्प में भव्यता ही दिखती है? वे तो मात्र भाव शून्य प्रस्तर खंड है। फिर कोई भी शिल्प हो उसे प्रकाश व पवन से तो भरना ही होगा, अन्यथा वह व्यक्ति को पर्याप्त स्थान नहीं दे सकेगी।

सारांशत: निर्माण में स्वास्थ्य पर भी विचार करना होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अद्वितीय है। वैसे पूरा अंक ज्ञानोदय था, आपका आभार।

– राजू मेहता
जोधपुर, राजस्थान

मोटे अनाज की प्रासंगिकता

मोटा अनाज (मिलेट्स) पर केन्द्रित योजना का जनवरी नव वर्ष का अंक बेहद उपयोगी साबित हुआ। यह हर्ष का विषय है कि हम अब अपनी संस्कृति, परंपरा, खानपान, तौर-तरीकों को पुन: अपनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आज से 50 साल पहले हमारे खाने की परंपरा बिलकुल अलग थी। मोटा अनाज- ज्वार, बाजरा, रागी, सवां, मक्का आदि ही हमारा भोजन हुआ करता था। फिर हरित क्रांति के बाद हमने अपनी थाली में चावल और गेहूँ को ही सजा लिया था और उससे दूर हो गए।

मोटे अनाज का उपयोग उपवास के मकसद से किया जाता रहा और कई समुदायों में विवाह समारोह के दौरान वर और वधु को आशीर्वाद देने के लिए गीतों में सिमट गया था।

किन्तु कोविड महामारी के बाद से स्वस्थ भोजन में नई रुचि पैदा हुई है। लोग इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों, जलवायु के प्रभावों को झेलने का सामर्थ्य और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता के कारण भविष्य का खाद्य विकल्प बनाने के लिए इसमें रुचि दिखाने लगे हैं। मोटा अनाज मात्र रोटी तक सीमित न होकर नये-नये उत्पादों में बिकने लगा है। स्टार्टअप मोटे अनाज के उत्पादों से 'रेडी टू कुक और रेडी टू ईट' उत्पाद तैयार होने लगे हैं।

बढ़ती आबादी के लिए पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने में मोटे अनाज की वापसी एक कुशल प्रयास है। यह किसानों के लिए भी वरदान साबित होगा।

– श्रीया
नई दिल्ली

देश की प्राचीन परम्परा

योजना पत्रिका के प्रत्येक संस्करण का बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है। जनवरी 2023 का अंक मोटा अनाज (मिलेट्स) बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें हमारे देश की प्राचीन परंपरा का पता चलता है जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। मोटे अनाजों के प्रति सजगता बढ़ाना मोटे अनाजों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 के जनआन्दोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

– दीपक कुमार
अशोक विहार, दिल्ली

मोटे अनाजों की महिमा

योजना का मोटा अनाज (मिलेट्स) अंक मोटे अनाजों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आज के समय में मोटा अनाज देश की आर्थिक, सामजिक, खाद्य आपूर्ति, पोषण और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है।

आज के इस प्रगतिशील युग में अधिकतर देशवासियों को मोटे अनाजों के संबंध में जानकारी ही नहीं है। विशेष रूप से नयी पीढ़ी के लोगों को। यह जानकारी कुछ क्षेत्र विशेष के दुर्गम स्थानों तक ही सीमित होकर रह गई है।

हमारे देश की बहुत-सी समृद्ध परम्पराओं की तरह मोटे अनाजों के सेवन की परम्परा भी लुप्तप्राय सी हो गई है। ऐसे समय में योजना का मोटा अनाज अंक देश के लोगों को मोटे अनाज के संबंध में विस्तृत जानकारी देगा।

दुर्गम स्थानों के कृषिजीवियों को पुन: मोटा अनाज उगाने को प्रेरित करेगा और उनका आर्थिक स्तर सुधारेगा। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। जलवायु के प्राकृतिक संरक्षण का कार्य करेगा।

योजना के सम्पादक मंडल और विषय के विशेषज्ञ लेखकों को धन्यवाद।

– विश्वनाथ सिंघानिया
जयपुर, राजस्थान

संपादकीय

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

युवाओं के बेहतर भविष्य का निर्माण

आज विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है। उचित नीतिगत कदम उठाये जाने से आने वाले समय में भारत को विविध और स्थिर उच्च आर्थिक विकास वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की युवाओं में पूर्ण क्षमता है। इसलिए न केवल युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है बल्कि उन्हें आगे बढ़ने और विकसित होने के अवसर प्रदान करना भी उतना ही आवश्यक है।

युवाओं की सकारात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा का इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत सरकार के व्यक्तित्व-निर्माण और राष्ट्र निर्माण के दोहरे उद्देश्य हैं यानी युवाओं के व्यक्तित्व का विकास करना और उन्हें विभिन्न राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों में शामिल करना। इसके अलावा युवाओं से संबंधित अन्य मुद्दे जैसे शिक्षा, रोज़गार और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि भी युवाओं के विकास में सहायता करने और उपयोगी युवा भागीदारी को सक्षम करने के लिए सरकार का एक केन्द्र बिंदु हैं। जब युवा विशिष्ट कौशल विकसित करते हैं और आत्म- विश्वास हासिल करते हैं तो हम एक देश के रूप में कई गुना समृद्ध हो जाते हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार और विकास युवा जनसांख्यिकीय संरचना पर निर्भर है और युवाओं का योगदान उनके कौशल विकास, नौकरी बाजार के विस्तार और उनके लिए वैश्विक बाजार तक आसान पहुँच के साथ कई गुना बढ़ रहा है। अब जबकि भारत नई विश्व व्यवस्था के लिए खुद को तैयार कर रहा है तो सरकार भारत के युवाओं को कुशल बनाने और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है और उन्हें वैश्विक बाजार में रोज़गार की मांग के अनुरूप तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा स्टार्टअप्स का पोषण करने वाले मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाए जाने से युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहन मिल रहा है।

युवाओं के विकास के लिए खेलों का विशेष महत्व है। टीम वर्क, निष्पक्ष खेल, सहयोग और अनुशासन जैसे खेल के मूलभूत सिद्धांत युवाओं में सहयोग, स्वयं पहल करना, आत्म-निर्देशन, आत्म-संयम, टीम वर्क, ज़िम्मेदारी, नागरिकता आदि जैसे सॉफ्ट स्किल के विकास में योगदान करते हैं। फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लक्ष्य के साथ फिट इंडिया अभियान खेल के प्रति हमारे दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन का प्रतीक रहा है। 'खेलो इंडिया' योजना के तहत विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण, विभिन्न खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और युवाओं के सकारात्मक जुड़ाव के लिए खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है।

हम आशा करते हैं कि योजना का यह अंक हमारे देश में युवाओं की आकांक्षाओं और सरोकारों पर प्रकाश डालने में मदद करेगा और उन्हें बहुत-सी उपयोगी जानकारी से भी परिचित कराएगा जिसका उपयोग वे सफलता हासिल करने और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए कर सकते हैं। ■

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

नए भारत के लिए पहल

अनुराग सिंह ठाकुर

"दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहाँ हम स्वयं को मज़बूत बनाने के लिए आते हैं।"

\- स्वामी विवेकानंद

भारत, दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जिसमें देश की 27.2 प्रतिशत जनसंख्या 15-29 वर्ष के आयु वर्ग की है।[1] भारत की इस युवा-शक्ति में राष्ट्र के उत्थान और सबके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की क्षमता है। युवाओं की सक्रिय भागीदारी में देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को उत्प्रेरित करने की असीम क्षमता है। 21वीं शताब्दी में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है, क्योंकि भारत इस सदी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही है।

राष्ट्र के युवा विकास के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति होंगे और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास तथा तकनीकी नवाचार के लिए प्रमुख प्रेरणा शक्ति होंगे। सरकार यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि युवा वैश्विक नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह सक्षम हों। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, सेवा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था में युवा, शिक्षित, कुशल जनशक्ति को काम पर रखने की प्रचुर क्षमता है और भारत इस मांग को पूरा करने के लिए कुशल जनशक्ति का एक बड़ा पूल विकसित कर रहा है। इसके अलावा, हमने एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाया है जो स्टार्टअप्स का पोषण करता है और हमारे युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करता है।

स्वच्छ भारत अभियान

आज, हमारे देश के युवा स्वच्छ भारत कार्यक्रम के सबसे बड़े दूत और हिमायती हैं। स्वच्छ भारत पहल, एक योजना या सरकारी कार्यक्रम से अधिक, जन आंदोलन है जो आम लोगों की वास्तविक चिंताओं को संबोधित करता है और एक सामाजिक मुद्दे को सीधे संबोधित करने के लिए उनकी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा 'जन भागीदारी से जन आंदोलन' पर ज़ोर दिया है और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी अभियान अधूरा है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग के मार्गदर्शन में 2022 में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 'स्वच्छ भारत 2.0' कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 1.68 लाख गांवों में आयोजित किया गया था। इसके तहत कचरा संग्रह और स्वच्छता अभियान संबंधी 2.22 लाख गतिविधियां की गईं। यूथ क्लब के सदस्यों, युवा स्वयंसेवकों और समाज के अन्य वर्गों के सहयोग से 1.55 करोड़ किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया गया, जिसमें से 1.54 करोड़ किलोग्राम कचरे का निस्तारण किया गया। यह कार्य देश भर के जिलों में ऐतिहासिक स्थानों, सामुदायिक केन्द्रों, स्कूलों, गांवों और अन्य स्थानों पर किया गया। लोगों, विशेष रूप से युवाओं ने न केवल इस कार्यक्रम में भाग लिया बल्कि पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

युवा स्वयंसेवक

युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण के दोहरे उद्देश्य के लिए युवा स्वयंसेवकों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत जब अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे होने का समारोह मना रहा है, हमें राष्ट्र के अमृत काल के दौरान, यानी अब से लेकर इंडिया@100 तक, हासिल करने और योगदान करने की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए और इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। युवाओं पर इस देश के वर्तमान और भविष्य के निर्माण की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। मेरे युवा साथी पहले से ही देश के सतत विकास के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाओं से जुड़े हुए हैं। मैं निजी क्षेत्र के अपने भागीदारों से आग्रह करूँगा कि वे सक्रिय और महत्वपूर्ण योगदान के लिए युवाओं को शामिल करने के लिए नए अवसर पैदाकर और अनूठे

लेखक केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं।

विचारों के साथ स्वयंसेवा को बढ़ावा दें।

मंत्रालय ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन- एनवाईकेएस के 14,000 युवा स्वयंसेवकों के जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवक, पांच प्रण (पांच संकल्प) को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में उल्लेख किया था। युवा स्वयंसेवकों ने 3.70 करोड़ घरों तक सफलतापूर्वक पहुँचकर और भारत के लगभग 9.38 करोड़ नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप 13-15 अगस्त 2022 के दौरान 2 करोड़ से अधिक परिवारों ने स्वेच्छा से अपने घरों में तिरंगा फहराया।

फिट इंडिया

केन्द्र सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर खेल, शिक्षा, कौशल विकास और क्षेत्रीय भाषा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारत चूंकि विश्व का विकास वाहक बनने की राह पर है, मैं युवाओं से देश के विकास वाहक के रूप में अति सक्रिय तथा नवप्रवर्तनशील बनने, नई तकनीक को अपनाने, मज़बूत नेटवर्क बनाने और स्वयं को दक्ष बनाने, अपस्किल यानी अपना कौशल विकास करने तथा रि-स्किल यानी फिर से कुशल बनने का आह्वान करता हूं। आज, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान खेलों के अपने बुनियादी ढाँचे का उन्नयन कर रहे हैं, जिससे युवाओं को 'फिट इंडिया' अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा रहा है, जो 'फिटनेस का डोज़, आधा घंटा रोज़' के प्रेरक नारे की तर्ज़ पर फिट और स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकें।

शारीरिक फ़िटनेस तथा मज़बूती को बढ़ावा देने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 3 जून 2022 को विश्व साइकिल दिवस मनाया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था, जिसमें मैंने भी 750 युवा साइकिल चालकों तथा अन्य गणमान्य लोगों के साथ भाग लिया और 7.5 किमी की दूरी तय की। इसके अलावा, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा देश भर के 35 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के 75 प्रतिष्ठित स्थानों में साइकिल रैलियों का आयोजन किया गया, जिनमें 1,23,149 साइकिल चालकों ने 8.06 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों ने भी साइकिल रैलियों का आयोजन किया जिनमें 3,28,601 स्वयंसेवकों तथा अन्य लोगों ने भाग लिया और पूरे देश में 16,43,005 किलोमीटर की दूरी तय की।

फिट इंडिया फ्रीडम रन के उद्घाटन संस्करण का आयोजन 14 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 (महात्मा गांधी की 151वीं जयंती) तक हमारे 74वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए किया गया था। इस वर्चुअल रन में लोग अपनी पसंद की जगह और गति से दौड़ सकते थे, इसमें 7 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। दूसरा संस्करण 13 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था और इसमें 9 करोड़ से अधिक लोगों की सामूहिक भागीदारी देखी गई थी।

खेल, शिक्षा और युवा विकास

खेल बहुत एकीकृत और तुल्यकारक है जो संस्कृति, भाषा, रंग और भौगोलिक सीमाओं सहित विभिन्न विभेदकारी कारकों के बावजूद सामाजिक सामंजस्य का एक प्रमुख वाहक है। सरकार के लगातार प्रयासों और खेल पारिस्थितिकी तंत्र को दिए गए प्रोत्साहन से खेलों के प्रति लोगों की धारणा में जबरदस्त बदलाव आया है। हाल के ओलंपिक, पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में देश के प्रभावशाली प्रदर्शन से यह परिलक्षित हुआ है।

जब छोटे बच्चों, युवाओं और माता-पिता सहित समस्त समाज देश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखता है, और देश की सफलता के रूप में उनकी सफलता का जश्न मनाता है, माननीय प्रधानमंत्री भी इन खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हैं तो समाज का मनोबल बढ़ता है और अधिक माता-पिता अपने बच्चों के लिए खेल को करियर के रूप में चुनते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे सरकार के सभी प्रयासों और देश के खिलाड़ियों की सहायता करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हैं, तो समाज के लिए यह महसूस करने का सही समय होता है कि खेलों में भी आकर्षक और लाभकारी करियर बन सकता है। कम उम्र में खेल प्रतिभा की पहचान करना फायदेमंद होता है क्योंकि किसी खेल विशेष के लिए उपयुक्त बच्चों को कम उम्र से ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए, खेलो इंडिया मोबाइल ऐप का उपयोग करके स्कूल जाने वाले 5-18 वर्ष की आयु के 23 लाख से अधिक बच्चों का आकलन किया गया है। बच्चों के खेल कौशल का आकलन करने के लिए 82,000 से अधिक शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

खेलो इंडिया योजना के प्रमुख स्तंभों में से एक गुणवत्तापूर्ण खेल अवसंरचना को नागरिकों तक समान रूप से पहुँचाना है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश भर में खेल बुनियादी ढाँचे की लगभग 2,500 करोड़ रुपये की 294 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हमारा मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण मिशन मोड में खेलो इंडिया योजना के तहत विभिन्न पहल के माध्यम से खेल पारिस्थितिकी तंत्र में खिलाड़ियों और अन्य हितधारकों की सहायता कर रहे हैं। इसमें जिला स्तरीय खेलो इंडिया

केन्द्रों तथा खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना, वार्षिक खेलो इंडिया खेल (युवा खेल, विश्वविद्यालय खेल, शीतकालीन खेल आदि), सामुदायिक कोचिंग विकास कार्यक्रम (ई-खेलपाठशाला) का आयोजन, विभिन्न खेल विषयों में महिला खेल लीग के माध्यम से खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर खेल और फिट इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से फिटनेस प्रचार कार्यक्रम शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, इस योजना में प्रारंभिक चरण की प्रतिभा पहचान और विकास का एक मज़बूत तंत्र है, जिसके माध्यम से विभिन्न खेल विषयों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और उन्हें आउट ऑफ पॉकेट भत्ता तथा खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों के माध्यम से प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रतिभाओं की खोज और विकास के तहत चयनित 21 खेल विधाओं (पैरा स्पोर्ट्स सहित) में 2,745 खेल प्रतिभाओं की पहचान की गई है। उन्हें प्रति वर्ष 6.28 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमें प्रशिक्षण और यात्रा, खेल विज्ञान सहायता, आहार शुल्क, चिकित्सा व्यय और आउट ऑफ पॉकेट भत्ता शामिल है। इन नवोदित खिलाड़ियों को हमारे भावी ओलंपिक पदक विजेता बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। देश भर में खेलो इंडिया के तहत पहचाने गए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए कुल 264 खेल अकादमियों (190 गैर-साई और 74 एनसीओई और साई) को मान्यता दी गई है। चिह्नित खिलाड़ियों के लिए इन अकादमियों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

देश के उग्रवाद और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक रूप से दिशा देने के लिए, देश भर के ऐसे भूभागों में युवाओं को शामिल करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देश के खेल विकास कार्यक्रम में समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, देश की सदियों पुरानी संस्कृति और विरासत को फिर से सक्रिय करने के लिए ग्रामीण और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के अलावा खेलो इंडिया योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के युवाओं के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। इसे प्राप्त करने के लिए, प्रभावी रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाने के वास्ते कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। यहां तक कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को कारपेन्टरी, प्लम्बिंग, बिजली के सामान की मरम्मत, बागवानी, मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई जैसे कौशलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम अपने युवाओं को समग्र शिक्षा प्रदान करने और विकास के लिए महत्वपूर्ण अन्य पहलुओं- टीम भावना और मानसिक तथा शारीरिक आरोग्यता को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए के भी खेल की शक्ति का लाभ उठा रहे हैं।

खेल-एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य फिटनेस को विद्यार्थियों की जीवन शैली से एकीकृत करने, उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्यता को बढ़ावा देने और फ़िट इंडिया अभियान में परिकल्पित फ़िटनेस के स्तर के साथ संबंधित जीवन कौशल हासिल करने में सक्षम बनाना है।

फ़िट इंडिया क्विज़, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खेल और फ़िटनेस पर 3.25 करोड़ की पुरस्कार राशि वाली भारत की सबसे बड़ी क्विज़, 1 सितंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। इसमें 13,502 स्कूलों के 36,299 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

भारत की खेल सफलता को कई गुना बढ़ाने के विभिन्न तरीकों के बीच, राज्यों को 'एक राज्य एक खेल' के दृष्टिकोण की ओर प्रोत्साहित किया जा सकता है, जहां उन्हें उपलब्ध प्रतिभा पूल, स्वाभाविक रुचि, उपलब्ध बुनियादी ढांचा आदि के आधार पर किसी एक खेल को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे केंद्रित दृष्टिकोण विकसित किया जा सकेगा और राज्य में मौजूदा संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा।

राष्ट्र की खेल उत्कृष्टता के लिए एक अन्य प्रमुख वाहक सक्रिय खेल संस्कृति को स्थापित करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन करना महत्वपूर्ण है। भागीदारी बढ़ाने के लिए और युवा खिलाड़ियों को अपने कौशल को सुधारने और अंततः खेल संस्कृति तथा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए आवश्यक मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्र को विभिन्न स्तरों पर अधिक लीग और प्रतियोगिताओं के आयोजन की आवश्यकता है। हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली में बदलाव के बाद ओलंपिक उत्कृष्टता के लिए एक बड़ा प्रतिभा पूल बनाने और लम्बी अवधि में खेल में रुचि और भागीदारी के बीच की खाई को पाटने की जबरदस्त क्षमता है।

सरकार भारत की युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने, उन्हें सक्षम बनाने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन्हें विजेता बनाने पर केंद्रित है। हम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं और सर्वोत्तम प्रशिक्षण सेवाएं सुनिश्चित करेंगे। पूर्व खिलाड़ियों को उभरते खिलाड़ियों का सहयोग करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए कोचिंग के क्षेत्र में आने की जरूरत है।

निष्कर्ष

भारत के युवा, 'भारत का भविष्य' होने के साथ-साथ अधिक महत्वपूर्ण रूप से 'भारत का वर्तमान' हैं। वे एआई - 'आत्मनिर्भर नवाचार' के इस युग में विचारों और नवाचार के वाहक हैं। एक युवा दिमाग, शरीर और आत्मा स्वस्थ और फिट भारत का प्रमुख वाहक है। राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिक से अधिक युवाओं को आगे आकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चाहिए, ताकि उन्हें वास्तविक भारत और उसकी समस्याओं का आभास हो। युवा समाज के सबसे प्रगतिशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और नए भारत की परिकल्पना को साकार करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। युवाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव में श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।

भारत के इस वर्ष जी-20 राष्ट्रों की प्रतिष्ठित अध्यक्षता संभालने के साथ, यह हमारे युवाओं के लिए अपने कौशल, प्रतिभा, कला का प्रदर्शन करने और राष्ट्र को अधिक मज़बूत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास प्रदर्शित करने का एक अवसर है। ■

संदर्भ

1. यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का कर्नाटक के हुबली में आयोजन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जनवरी, 2023 को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया गया जो स्वामी विवेकानंद की जयंती दिवस पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं व योगदानों को सम्मान देने और संजो कर रखने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव का विषय 'विकसित युवा- विकसित भारत' था। यह देश के सभी भागों से विविध संस्कृतियों को एक मंच पर लाता है और प्रतिभागियों को एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ता है। हर वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हमारे प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने और राष्ट्र निर्माण की ओर उन्हें प्रेरित करने के लिए किया जाता है।

इस पांच- दिवसीय महोत्सव में युवा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें जी-20 और वाई-20 आयोजनों से जुड़े पांच विषयों पर चर्चाएं की गयी मसलन - काम, उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल का भविष्य; जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी; शांति निर्माण और सुलह; साझा भविष्य - लोकतंत्र और शासन में युवा; और स्वास्थ्य व कल्याण।

Champi Chikka

इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक तरफ जहां उमंगों से सराबोर राष्ट्रीय युवा महोत्सव है तो दूसरी ओर आज़ादी का अमृत महोत्सव है। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी के संदेश- "उठो, जागो और लक्ष्य तक मत रुको" को उद्धृत करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का यह उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में देश को आगे ले जाने के लिए हमें अपने कर्त्तव्यों को महत्व देना और समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस प्रयास में भारत के युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी से मिली प्रेरणा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "मैं इस विशेष अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ।"

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा, "राष्ट्रीय युवा महोत्सव हमारे राष्ट्र की संस्कृति और इससे जुड़ी जिज्ञासाओं, इसके समुदायों और इसके भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी जिज्ञासाओं को सामने लाता है।" स्वामी विवेकानंद के खेलों और फ़िज़िकल फ़िटनेस के महत्व पर दिए गए बल पर अपने विचार रखते हुए केन्द्रीय खेल मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा मानते थे कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है।

इस महोत्सव में कई प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों में स्थानीय पारंपरिक संस्कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए लोक नृत्यों और गीतों का आयोजन शामिल था। योगाथन जिसका उद्देश्य योग करने के लिए करीब 10 लाख लोगों को जुटाना है प्रमुख गैर-प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों मे से एक रहा। अन्य आकर्षणों में फूड फेस्टिवल, युवा कलाकार शिविर, साहसिक खेल गतिविधियां और "अपनी सेना, नौसेना और वायु सेना को जानो" के विशेष शिविर शामिल थे।

स्रोतः पत्र सूचना कार्यालय

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य का विकास

भरत लाल

"अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा"

ऋग्वेद की यह सूक्ति हमें स्मरण कराती है कि युवा ही विश्व के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत की मध्य-आयु 29 वर्ष है और हमारी युवाशक्ति पूर्ण उभार पर है। तभी तो हमारे युवा भारत की गौरवमयी परम्परा को आगे बढ़ाने और भविष्य के निर्माण की दिशा में विविध मार्गों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इंडिया@2047 अर्थात् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 के भारत के विज़न के अनुसार उन्नत भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में युवाओं का सशक्तीकरण करना अत्यंत आवश्यक है।

भारत सरकार ने जीवन स्तर सुधारने और 'ईज ऑफ लिविंग' अर्थात् जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं जिनमें सभी के लिए आवास की सुनिश्चित व्यवस्था; पीने का साफ पानी; ग्रामीण विद्युतीकरण; रसोई गैस; इंटरनेट और संचार की सुविधाएं; स्वास्थ्य बीमा; सड़क संपर्क व्यवस्था; उत्तम शिक्षा; और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना शामिल है ताकि सभी एकजुट होकर अपने भविष्य के निर्माण पर ध्यान दे सकें और अपनी पूरी क्षमता से विकास कार्यों में सहयोग कर पाएं।

इस समय देश में कामकाज करने वाले 15 से 64 आयुवर्ग के लोगों की संख्या 80 करोड़ के आसपास है जो हमारी कुल जनसंख्या का करीब 67 प्रतिशत है। वर्ष 2020 से वर्ष 2050 को भारतीय अर्थव्यवस्था का 'स्वर्णकाल' माना जा रहा है जिसमें युवाओं की भूमिका मूख्य रहेगी; और सही नीतिगत उपाय अपनाए गए तो ये युवा लोग रचनात्मक बदलाव से भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार विविधता लाकर उच्च वृद्धि दर बनाए रखने में सफल होंगे। देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में मज़बूती से पकड़ बना रहा है और नवाचारों, स्टार्टअप्स और युवा शक्ति के सहारे वह न केवल अनेक विकसित देशों के लिए कड़ी स्पर्धा पेश कर रहा है बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने भी अपने उल्लेखनीय योगदान के बल पर एक विशेष पहचान बना ली है।

'टेकेड' का युग

देश के कार्यबल में हर वर्ष 1.2 करोड़ नए युवा बढ़ रहे हैं जिससे पता चलता है कि सभी के लिए कामकाज के अवसर जुटाने के साथ ही शिक्षा; कौशल; उद्यमिता; सार्वजनिक सेवाओं में सुधार; इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी सुविधाओं); डिजिटल टेक समन्वयन; श्रमिक संरक्षण और इन सबसे अहम ऐसी टिकाऊ हाट व्यवस्था बनाने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है जो देश की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के अनुरूप हो तथा सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने में सक्षम हो।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और दुनिया के हर दस यूनिकॉर्न में से एक भारत का होता है। स्टार्टअप इंडिया योजना और कारोबार की प्रक्रिया सरल बनाने के प्रयासों से ही इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की जा सकी है। जिस देश में 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे वहीं 2022 में इनकी संख्या 100 से ज्यादा हो जाना इस क्षेत्र में हुई महती सफलता को दर्शाता है। 2014 में भारत ने लगभग 4000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया था और 2022 में भारत द्वारा 15000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया जा चुका है। भारत ने नवाचारों के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ही तेजी से प्रगति की है। इस जबरदस्त कामयाबी का पता 'वैश्विक नवाचार इंडेक्स' देखने से लगता है क्योंकि जिस नवाचार सूची में 2015 में भारत का नाम 81वें स्थान पर था वहीं 2022 में भारत इस सूची में 40वें स्थान पर पहुँच गया।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन विज्ञान, शिक्षा, व्यावसायिक (प्रोफेशनल) सेवा, कृषि, खानपान जैसे 56

लेखक भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र के महानिदेशक हैं। ईमेल: Dg.Ncgg@gov.in

विविध औद्योगिक क्षेत्रों में भारत के 656 ज़िलों में 77,000 से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप चल रहे हैं। ये नीतियां और सफलताएं भारत के स्पर्धात्मक वैश्विक मानकों के स्तर तक पहुँचने और देश के युवाओं के लिए 'अनुकूल पर्यावरण' विकसित करके ही संभव हो पाई है। उदाहरण के लिए बाज़ार तक पहुँच की व्यवस्था का अभाव स्टार्टअप्स के विकास में बहुत बड़ी बाधा थी और सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म के जरिए इसका आसानी से समाधान कर दिया। GeM पोर्टल ऑपरेटर-अनुकूल इंटरफेस बन चुका है जो उच्च क्वालिटी मानकों, बेहतर किस्म के उत्पादों, गोदाम और भंडारण सुविधाओं के नेटवर्क और माल लाने-ले जाने में लॉजिस्टिक सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराने की पूरी पक्की व्यवस्था की गारंटी देता है।

टिकाऊ स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में ऐसा ही एक और अहम पहलू है आंकड़ों, सेवाओं, बाजार सुविधाओं, उपभोक्ता तक पहुँच अर्थात् आउटरीच और कारोबार करने तथा नियमों का पालन करने की भारी लागत को कम करना। डिजिटल इंडिया देशभर के सुदूर क्षेत्रों को पहुँच में लाकर दूरी की बाधा के बावजूद सहयोग और समन्वय की क्षमता को बनाए रखने के लिए चलाया गया मिशन है। देश के आईटी और कंप्यूटर विशेषज्ञों के तालमेल से आईओटी क्रांति आई है जिससे भारतीय बाजार नए स्टार्टअप्स के लिए जोखिम का कारण बनने की जगह विश्व स्तर के आधुनिक, गतिशील और उन्नत बाजारों जैसे बन गए हैं।

2014 में भारत ने लगभग 4000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया था और 2022 में भारत द्वारा 15000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया जा चुका है। भारत ने नवाचारों के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ही तेजी से प्रगति की है। इस जबरदस्त कामयाबी का पता 'वैश्विक नवाचार इंडेक्स' देखने से लगता है क्योंकि जिस नवाचार सूची में 2015 में भारत का नाम 81वें स्थान पर था वहीं 2022 में भारत इस सूची में 40वें स्थान पर पहुँच गया।

रोज़गार के अवसर जुटाने वाले

विभिन्न दिशाओं में भारत की प्रगति का पता इस तथ्य से लग जाता है कि वह इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है; जहां 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर की थी वहीं यह 2019 में बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है और इसका लक्ष्य 2030-31 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह महत्वाकांक्षी विस्तार और वृद्धि तभी संभव होगी जब हमारी युवाशक्ति कौशल विकास, रोज़गार जुटाने की क्षमता बढ़ाने और विश्व बाज़ारों में पहुँच बनाने की दिशा में पक्के इरादे से जुट जाएगी।

सरकार ने कौशल विकास और युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं ताकि भावी कार्यबल के लिए दक्षता और बाजार-केंद्रित प्रतिभा तथा जानकारी की मज़बूत बुनियाद तैयार की जा सके। साथ ही, भारतीय युवा शक्ति की मूल प्रतिभा को नई दिशा देकर आगे बढ़ाने के काम में मदद के लिए देशभर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान, अनेक आईआईटी, आईआईएम और आईटीआई विकसित किए जा रहे हैं।

भारत जैसे सांस्कृतिक और भाषायी विविधता वाले विकासशील देश में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने वालों और रोज़गार तलाशने वालों के बीच संतुलन बनाए रखने की चिंता लंबे अर्से से चली आ रही है क्योंकि हमारे देश में 90 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के अलावा दोनों वर्गों में हुई वास्तविक वृद्धि आंकने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़े भी हैं जो दर्शाते हैं कि 2017 के बाद से 3 करोड़ से भी अधिक औपचारिक रोज़गारों के नाम जुड़े हैं। श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करने के पीछे स्पष्ट मंशा यह भी थी कि असंगठित क्षेत्र के लिए भी सुरक्षा प्रदान की जाए और बेरोज़गारी तथा पेंशन लाभ कराए जाएं। इसने अनौपचारिक क्षेत्र में रोज़गार वृद्धि मापने के लिए संख्यात्मक मानदंडों को भी समन्वित करके अधिक भरोसेमंद बनाया है।

रोज़गार उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, चाहे वे बड़े निर्माण उद्योग हों या मझौले निर्माण उद्योग, और इन दोनों उद्योगों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से लगातार लाभ मिल रहा है; रोज़गार के अवसर जुटाने की क्षमता से शुरू होकर निर्माण का आधार व्यापक बनाने, भारतीय बाजार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती निर्भरता और मांग बढ़ने और उसके आधार पर अधिक अवसर और रोज़गार बढ़ने तक यही हो रहा है। 2021-22 में सरकार ने पीएलआई योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया था

ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव से उबर सके तथा अधिक टिकाऊ और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला मॉडल विकसित किए जा सकें।

जीवन स्तर सुधारने और जीवन को सुगम बनाने के सरकार के दो लक्ष्यों का देश के युवाओं के जीवन और उनकी क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लीवरेज टेक्नोलॉजी और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि के लिए सरकार के प्रयासों के कारण बुनियादी ढांचे के विकास की गति में तेजी आई है। मेट्रो, रेलवे और सड़क संपर्कों के तेज विकास से अनेक रोज़गार योजनाओं के तहत रोज़गार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।

समावेशी शिक्षा तक पहुँच

भारत प्राचीनकाल से ही ज्ञान का केन्द्र रहा है और समाज की ऐसी धारणा है कि युवाओं की आकांक्षाओं-अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सार्थक और प्रभावी शिक्षा प्रणाली होना जरूरी है। हर भारतीय मां अपने बच्चों को उत्तम श्रेणी की शिक्षा दिलाना चाहती है। इस भावना को ध्यान में रखकर ही सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से शिक्षा सुधारों के नए युग का सूत्रपात किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नई राष्ट्रीय नीति (एनईपी) लागू करना जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया भी है। इसमें नए दौर के कौशल पर जोर दिया जा रहा है और विद्यार्थियों को अपने तरीके से पढ़ने-सीखने का मौका दिया जाता है।

2014 में देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई तथा इस प्रकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने कार्यरत और स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 'एम्स' की संख्या भी तिगुनी कर दी है। साथ ही, 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (एनएमसी) लागू हो गया और यह आयोग देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च नियामक बन गया। एनएमसी से मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही भी आई है।

इस नीति को लागू करने के लिए भारतीय युवाओं को समाधान पर मुख्य ध्यान केंद्रित रखने वाले तथा चुस्त-सतर्क और जीवन की वास्तविकताओं को झेलते हुए चुनौतीपूर्ण हालात का मुकाबला करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार बनाना होगा। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्कूलों में अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान में दक्षता अर्जित करने पर जोर देना होगा तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की संख्या पर अंकुश लगाने के प्रयास करने होंगे। उच्च शिक्षा को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए अनेक विषय पढ़ाने का विकल्प खुला रखना होगा और पाठ्यक्रम में शामिल होने या उसे छोड़कर जाने के भी कई विकल्प देने होंगे। नीति में बाल्यावस्था में विशेष देखरेख करना, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, आकलन और परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और व्यवस्था का व्यापक विस्तार करना भी शामिल है।

सभी देख पा रहे हैं कि सुधारों को कार्यरूप देने पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। 2014 में देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई तथा इस प्रकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने कार्यरत और स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 'एम्स' की संख्या भी तिगुनी कर दी है। साथ ही, 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (एनएमसी) लागू हो गया और यह आयोग देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च नियामक बन गया। एनएमसी से मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही भी आई है।

शिक्षा क्षेत्र के लक्ष्य को विस्तार दिया गया है जिससे ऐसी पक्की व्यवस्था हो सके कि 'कोई भी छूट न जाए' या 'कोई भी पिछड़ा न रह जाए।' अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभाशाली बच्चों को उत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल (ईएमआरएस) खोले गए हैं। 2004 से 2014 की अवधि में करीब 90 ईएमआरएस के लिए मंजूरी दी गई थी। 2014 के बाद से 686 ईएमआरएस मंजूर किए गए हैं जो दस वर्ष पहले की संख्या से पांच गुणा ज्यादा हैं। हर वर्ष एक आईआईटी और एक आईआईएम भी जुड़ा है और अक्तूबर, 2022 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 723 से बढ़कर 1,043 हो गई है और हम देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का सपना साकार होते देख रहे हैं। इसी प्रकार नवोदय विद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है। हर बच्चे तक उत्तम शिक्षा की सुविधा पहुँचाने के लगातार भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं।

ऐसे प्रमुख संस्थानों तक पहुँच उपलब्ध कराने में अक्सर धन की व्यवस्था बड़ी अड़चन बन जाती है। स्कूल स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए कम ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने और छात्रवृत्ति कार्यक्रम का विस्तार करने से शिक्षा तक पहुँच अब आसान हो गई है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि योग्य और प्रतिभावान विद्यार्थियों को यह फिक्र नहीं करनी होगी कि उनके परिवार वाले उनकी पढ़ाई का बोझ कैसे संभालेंगे।

जीवन में सुगमता-नई वास्तविकता

आधुनिक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के बेरोकटोक उपलब्ध होने से जीवन स्तर सुधारने की दिशा में सार्थक प्रभाव हुआ है। इससे

देश के सबसे दूरदराज वाले भागों में भी शैक्षिक, व्यावसायिक और उद्यमिता के बीच सामंजस्य लाने में बहुत मदद मिली है। सरकार ने ऐसे स्पष्ट और ठोस उपाय किए हैं जिनका करोड़ों युवाओं पर सार्थक और रचनात्मक प्रभाव हुआ है और हर विकास कार्यक्रम के मूल में जीवन की सुगमता ही मुख्य आधार है।

2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए है, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराके उनके घरों को धुएँ की समस्या से छुटकारा दिलाया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना लागू करके यह सुनिश्चित हो गया है कि देश के 99 प्रतिशत से अधिक घरों में बिजली पहुँच चुकी है और युवाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। स्वच्छता अब युवाओं की जीवनशैली का हिस्सा बन चुकी है। देश को खुले में शौच की बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के अंतर्गत 1.34 लाख से ज्यादा गांवों को 'खुले में शौच से मुक्त' यानी ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। इसका मतलब है कि इन गांवों में ठोस और तरल कचरे को उठाने, उसे उपचारित करने और फिर इस्तेमाल योग्य बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे ग्रामीण भारत का वातावरण तो सुधर ही रहा है और जनस्वास्थ्य के लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं, साथ ही हमारे युवाओं का गौरव भी बढ़ रहा है। जब जल जीवन मिशन शुरू किया गया था तो उस वक्त देश के कुल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को ही पीने के पानी के लिए नल के कनेक्शन उपलब्ध थे। आज, 10.75 करोड़ (56 प्रतिशत) से अधिक परिवारों को सीधे नल से पीने के साफ पानी की सुविधा मिल रही है। निजी स्वामित्व वाला मकान होने से आत्मविश्वास बढ़ता है और गरीबी दूर होने का संकेत भी मिलता है। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए गए हैं तथा इनके निर्माण कार्य में ही कई समुदायों ने कौशल हासिल कर लिया और युवाओं को रोज़गार भी मिले हैं । जल जीवन मिशन के अंतर्गत खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक जैसे काम सीखकर रोज़गार पाने में मदद मिली है।

उड़ान जैसी योजना से कनेक्टिविटी की पक्की व्यवस्था हो गई है जिससे विमान यात्रा किफायती हो गई है और लोग इसका फायदा पा रहे हैं। साथ ही, युवाओं को नई बातों ओर परिस्थितियों की जानकारी मिलने लगी है। राजमार्गों, रेलमार्गों और शहरी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार से भारत के युवाओं को अपनी दक्षता और उत्पादकता बढ़ाकर क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद मिली है।

स्वास्थ्य जीवनशैली पर सरकार के जोर देने से युवाओं को सीधे लाभ मिल रहा है। फिटनेस और खेलकूद स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कुंजी हैं। युवाओं में खुद को फिट और चुस्त-दुरुस्त रखने की सोच जगाने के उद्देश्य से अगस्त, 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट (स्वस्थ भारत अभियान) शुरू किया गया था। खेलों इंडिया कार्यक्रम के जरिए युवाओं में बचपन से ही खेलकूद में रुचि जगाने की पहल की गई है जिसमें बड़ी सफलता मिल रही है। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर प्रतिभावान युवाओं का चयन करके उन्हें 8 वर्ष के लिए 5 लाख रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है।

आगे का रास्ता

स्वामी विवेकानंद ने सही कहा था, "मुझे सौ ऊर्जावान युवा दे दो, मैं भारत में क्रांतिकारी बदलाव ला दूँगा।" आज भारत के युवा कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, संचार, अक्षय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, कृत्रिम मेधा और अन्य अनेकानेक क्षेत्रों में नवाचार और किफायती समाधान खोज चुके हैं।

देश के युवा ही भारत के स्वप्न को साकार करने का बीड़ा उठाकर उसे नई ऊंचाई पर पहुँचा सकते हैं। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की सौवीं वर्षगांठ मनाएगा तो देश के युवा उसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर सही अर्थों में विकसित देश बनाने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। सरकार ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने युवाओं को शिक्षा, कौशल और बढ़िया स्वास्थ्य देने के साथ भाईचारे और सर्वजन हिताय जैसे मूल्यों का भी विकास करने की कई पहल शुरू की हैं। जहां भारत अपना भाग्य बनाने में लगा है वहीं हमें अपने युवाओं के सामर्थ्य और उनकी ऊर्जा के विकास की दिशा में पूरी लगन से प्रयासरत रहना है। ■

नेहरू युवा केन्द्रों की गतिविधियां

- नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) 2018 से ही देश भर में पोषण माह कार्यक्रम को लागू करने में एक प्रमुख भागीदार रहा है। जिला नेहरू युवा केन्द्र संबंधित जिलों के प्रशासन, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से राष्ट्रीय युवा कोर-नेशनल यूथ कॉर्प्स (एनवाईसी) और युवा क्लबों को प्रेरित करते रहे हैं कि वे ग्रामीणों को कुपोषण, संतुलित आहार के महत्व और पारंपरिक भोजन के बारे में जागरूक करें।
- एनवाईकेएस ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर 947 जिला, 5661 प्रखंड और 23782 ग्राम स्तरीय योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें कुल 9.88 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया।
- संगठन ने विश्व साइकिल दिवस 2022 के मौके पर 35 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में तथा 75 प्रतिष्ठित स्थलों पर साइकिल रैलियों का आयोजन किया। कुल 8.06 लाख किलोमीटर की इन रैलियों में 123149 साइकिलिस्टों ने शिरकत की।
- एनवाईकेएस ने राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 पर रन फॉर यूनिटी से संबंधित 68364 गतिविधियां आयोजित कीं। कुल एक करोड़ किलोमीटर की इन दौड़ों में 19.71 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया।
- संगठन ने 8 से 14 अगस्त 2022 तक आइकॉनिक सप्ताह मनाया। इस दौरान उसने देश भर में आइकॉनिक स्थलों पर 7458 स्वच्छता गतिविधियां चलायीं। इन गतिविधियों के तहत 7047 तिरंगा यात्राएं आयोजित की गयीं और 57074 औषधीय पौधे लगाये गये।
- 2022 में एनवाईकेएस ने 437 जिला युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किये। युवा उत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 1.31 लाख युवाओं ने भागीदारी की। हर युवा उत्सव में छह खंड थे: युवा कलाकार शिविर- पेंटिंग, युवा लेखक शिविर- कविता, छायाचित्र प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक पर्व-सामूहिक कार्यक्रम और युवा संवाद - 2047 का भारत।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

फिट इंडियाः स्वस्थ भविष्य की ओर

राशि शर्मा
पूरबी पटनायक

दुनिया अब पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है, और खेल के वैश्विक परिदृश्य में, दीर्घकालिक विकास के प्रति एकसमान प्रतिबद्धता वाले विभिन्न भागीदारों और हितधारकों के शक्तिशाली नेटवर्क को एकजुट करने की क्षमता है। सतत विकास को खेलों से बहुत मदद मिलती है क्योंकि खेल स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाओं और युवाओं के साथ-साथ व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने में भी खेलों की भूमिका है। बच्चों और किशोरों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ बहुत अधिक हैं।

चूंकि खेल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्यता में सुधार करके समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं, साथ ही संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाते हैं, इसलिए शिक्षा में खेलों को शामिल करने की आवश्यकता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। समग्र शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और खेल को शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करती है (सतत विकास लक्ष्य 4: सभी के लिए समावेशी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना)। विद्यार्थी कक्षा के बाहर खेल और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेकर खेल के मूलभूत सिद्धांत सीखते हैं, जैसे टीमवर्क, निष्पक्षता, नियमों तथा दूसरों के लिए सम्मान, सहयोग, अनुशासन और सहिष्णुता। ये क्षमताएं समुदायों और संस्कृतियों के बीच सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देती हैं और सामूहिक गतिविधियों तथा पेशेवर जीवन में भावी जुड़ाव के लिए आवश्यक हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में खेलों के लाभ को देखते हुए इनकी पहुँच और इनमें भागीदारी बढ़ाना एक प्रमुख विकास उद्देश्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में सामाजिक शांति, उत्पादकता में वृद्धि और मानव पूंजी के विकास में खेल-समेकित शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि गणित और विज्ञान के अलावा कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस के साथ-साथ भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्यों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि विद्यार्थियों को उनके सभी कौशल और क्षमताओं को विकसित करने और उन्हें अधिक पूर्ण विकसित, व्यावहारिक और संतोषप्रद शिक्षा दी जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में खेलों को शामिल करने पर भी जोर देती है, जिससे सहयोग, स्व-पहल, स्व-निर्देशन, स्व-अनुशासन, टीमवर्क, ज़िम्मेदारी, नागरिकता आदि

राशि शर्मा डाक विभाग में उप महानिदेशक, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की पूर्व निदेशक हैं। ईमेलः rashi-edu@gov-in
पूरबी पटनायक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में प्रधान मुख्य सलाहकार हैं।

जैसे कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए शैक्षणिक पद्धतिओं में स्वदेशी खेलों सहित शारीरिक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। यह कक्षा में खेल-समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि विद्यार्थियों को आजीवन दृष्टिकोण के रूप में फिटनेस अपनाने और फिट इंडिया अभियान में कल्पना के अनुसार संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके। उपरोक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में विकसित की जा रही स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफएसई) और स्कूल पाठ्यक्रम में खेल, फिटनेस तथा अन्य पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

2022 में, 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 42,490 स्कूलों से 1,74,473 विद्यार्थियों ने खेल और फिटनेस में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए पंजीकरण कराया। फिट इंडिया क्विज ने देश भर के बच्चों को फिटनेस अभियान में शामिल होने और स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रोत्साहित करने के माध्यम के रूप में लोकप्रियता हासिल की है।

फिट इंडिया का शुभारंभ

माननीय प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किया था। यह अभियान फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लक्ष्य के साथ, खेल के प्रति हमारे दृष्टिकोण में आदर्श बदलाव का प्रतीक रहा है। नियमित व्यायाम और खेलों में भागीदारी से विभिन्न प्रकार के सकारात्मक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते हैं। यह सीधे शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है, साथ ही यह बच्चों और युवा, वयस्कों को अच्छी जीवन शैली का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उन्हें सक्रिय रहने और गैर-संचारी रोगों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कई शोधों के अनुसार, शारीरिक गतिविधि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है।

माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को फिटनेस और आरोग्यता के पथ पर आगे ले जाने के लिए 'फिट इंडिया' अभियान का आह्वान किया। यह अभियान व्यवहार में परिवर्तन लाने और शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ने के दृष्टिकोण से शुरू किया गया था। इसके लक्ष्य और उद्देश्य हैं:

- फिटनेस को आसान, आनंदमय और मुफ्त के रूप में प्रचारित करना।
- केंद्रित प्रचार के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने वाली फिटनेस और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरुकता फैलाना।
- स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करना।
- फिटनेस को हर स्कूल, कॉलेज/यूनिवर्सिटी, पंचायत/गाँव आदि तक पहुँचाना।
- भारत के नागरिकों के लिए जानकारी साझा करने, जागरुकता बढ़ाने और व्यक्तिगत फिटनेस कहानियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच तैयार करना।

इस अभियान ने देश को फिटनेस और आरोग्यता के रास्ते पर लाने का प्रयास किया। फिटनेस तनाव और जीवन शैली संबंधी विकारों के आधुनिक परिवेश में एक महत्वपूर्ण घटक है और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने, बीमारी को रोकने तथा जीवन के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस पहल से स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक विशेष और रोमांचक अवसर मिलता है। इस अभियान का समर्थन करने के लिए, व्यक्ति और

संगठन अपने स्वयं के स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती और अपने साथी भारतीयों के स्वास्थ्य तथा आरोग्यता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कर सकते हैं।

फिट इंडिया अभियान का लक्ष्य शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाना और कम उम्र से ही खेलों को शिक्षा में शामिल करने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करना है। अगर हम उच्चतम क्षमता वाले खिलाड़ी बनाना चाहते हैं जो वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकें तो ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी पर जोर देती है।

पहल

(1) समग्र शिक्षा योजना: उपरोक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ दिया गया है। योजना के तहत, सभी सरकारी स्कूलों को वार्षिक आधार पर खेल अनुदान प्रदान किया गया है। इसके अलावा, यदि किसी स्कूल के कम से कम दो विद्यार्थी खेलो इंडिया स्कूल खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं तो ऐसे स्कूल को 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त खेल अनुदान उपलब्ध कराया गया है। खेलों को अब पाठ्येतर गतिविधि के बजाय शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाता है।

एक अभियान के रूप में फिट इंडिया के प्रभाव को मज़बूत करने और जागरुकता फैलाने के लिए की गई कई नई और अभिनव पहलें नीचे दी गई हैं:

(2) फिट इंडिया स्कूल अभियान: फिट इंडिया मिशन नवंबर/दिसंबर के महीने में फिट इंडिया स्कूल सप्ताह आयोजित करने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करता है। इसने सरल और सहज मापदंडों के साथ फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन का एक सेट भी तैयार किया है।

Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

(3) फिट इंडिया स्कूल सप्ताह: बच्चों , उनके माता-पिता, शिक्षकों और स्कूल कर्मियों के बीच फिटनेस जागरुकता बढ़ाने के लिए, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह 2019 में प्रारंभ किया गया था। वाद-विवाद, क्विज, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर-मेकिंग प्रतियोगिता, योग तथा ध्यान, फिटनेस के वादे, स्वदेशी खेलों के आयोजन आदि के साथ, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, देश भर के स्कूलों को आमंत्रित किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से, पहला फिट इंडिया स्कूल सप्ताह नवंबर 2019 के तीसरे सप्ताह के दौरान मनाया गया। पहले फिट इंडिया स्कूल सप्ताह में 15,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया था। दूसरा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक था। इसे देश भर में 4.3 लाख से अधिक कक्षाओं में मनाया गया। इसमें योग, फ्री हैंड ड्राइंग, पेंटिंग, चर्चा और संगोष्ठी सहित शारीरिक फिटनेस गतिविधियां शामिल थीं। तीसरा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह नवंबर 2021 से जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। समूचे भारत के 4.5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के उत्सव में योग, नृत्य, वाद-विवाद, संगोष्ठी, व्याख्यान और बहुत कुछ शामिल था। चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह 15 नवंबर से 31 जनवरी 2023 तक होगा। इसके अतिरिक्त, इस आयोजन से शुरू होकर, यह कार्यक्रम सभी स्कूलों को अपना वार्षिक खेल दिवस आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर भारतीय खेल प्राधिकरण को विभिन्न खेल विधाओं में खोजे गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बारीकियों से अवगत कराया जा सकता है। 2 जनवरी 2022 तक विभिन्न आयोजनों में कुल 2,54,470 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

(4) फिट इंडिया क्विज : फिट इंडिया क्विज को 2021 में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के उत्सव के रूप में पेश किया गया था, जिसका लक्ष्य स्कूलों में इसकी उपस्थिति को मज़बूत करना और स्कूली बच्चों में फिट इंडिया के संदेश को फैलाना था। फिट इंडिया क्विज का उद्देश्य पूरे देश के विद्यार्थियों को शामिल करना है। खेल और फिटनेस में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, स्कूली विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई इस फिट इंडिया क्विज में भाग ले सकते हैं और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। 2022 में, 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 42,490 स्कूलों से 1,74,473 विद्यार्थियों ने खेल और फिटनेस में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए पंजीकरण कराया। फिट इंडिया क्विज ने देश भर के बच्चों को फिटनेस अभियान में शामिल होने और स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रोत्साहित करने के माध्यम के रूप में लोकप्रियता हासिल की है।

(5) फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0: युवा मामले और खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की शुरुआत की घोषणा की। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई, और 31 अक्टूबर 2022 को सम्पन्न हुई। खेल विभाग ने इसे लोगों का अभियान बनाने के लिए, फिट इंडिया स्कूलों में पेश किए गए संसाधनों के आधार पर एक रेटिंग प्रणाली बनाई है। फिट इंडिया 3 या 5 स्टार ग्रेड प्राप्त करने के लिए सभी स्कूलों से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से भाग लेने का आग्रह किया गया

है। फिट इंडिया फ्लैग 4,44,531 स्कूलों को प्रदान किया गया है, और 43,074 और 13,008 स्कूलों ने क्रमश: 3 और 5 स्टार रेटिंग के लिए आवेदन किया है।

कई अन्य ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय ने शुरू किया है। जागरुकता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने 'फिट इंडिया मोबाइल ऐप' बनाया, जिसे 5 लाख से अधिक उपयोगकर्ता डाउनलोड कर चुके हैं। फिट इंडिया मिशन प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या में कम से कम 45-60 मिनट की शारीरिक गतिविधि को शामिल करके लोगों को फिट इंडिया अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए यूथ क्लबों को भी प्रोत्साहित करता है। यूथ क्लब अपनी व्यक्तिगत और अपने साथी भारतीयों की आरोग्यता के लिए तरह-तरह के प्रयास कर सकते हैं।

स्कूलों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम को लागू करने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, शिक्षा मंत्रालय और फीफा द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत इसे देश के सभी स्कूलों में 25 मिलियन विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाया जाना है।

(6) स्कूल कार्यक्रम के लिए फुटबॉल: फीफा-यूनेस्को के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम फुटबॉल फॉर स्कूल्स (एफ4एस) का उद्देश्य दुनिया भर के 700 मिलियन विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में मदद करना है। इसका उद्देश्य आवश्यक प्राधिकारियों और हितधारकों के सहयोग से, फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को शैक्षिक प्रणाली में शामिल करके, दुनिया भर में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए फुटबॉल की पहुँच बढ़ाना है। यह पहल फुटबॉल के माध्यम से विशिष्ट जीवन कौशल और दक्षताओं को बढ़ावा देते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और संयुक्त राष्ट्र की अन्य प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए की गई है। एफ4एस कार्यक्रम निम्नलिखित चार प्रमुख परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास है:

- मूल्यवान जीवन कौशल और दक्षताओं के साथ शिक्षार्थियों (लड़कों और लड़कियों) को सशक्त बनाना।
- कोच-शिक्षकों को खेल और जीवन-कौशल गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना।
- फुटबॉल के माध्यम से जीवन कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए हितधारकों (स्कूलों, सदस्य संघों और सार्वजनिक प्राधिकरणों) की क्षमता का निर्माण करना।
- साझेदारी, गठजोड़ और अंतरक्षेत्रीय सहयोग को सक्षम करने के लिए सरकारों, सदस्य संघों और भाग लेने वाले स्कूलों के बीच सहयोग को मज़बूत करना।

बच्चों को खेलों में शामिल करने के लिए स्कूल सबसे व्यावहारिक और प्रभावी माध्यम बने हुए हैं। एफ4एस कार्यक्रम यह गारंटी देने का प्रयास है कि फुटबॉल खेल सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जो कोई भी फुटबॉल खेलना चाहता है उसे पता होना चाहिए कि वे अपने स्कूल या समुदाय के माध्यम से देश के संसाधनों का उपयोग करके ऐसा कर सकता है। स्कूलों को फुटबॉल कोचिंग और उपकरण के प्रावधान में सहायता करना इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य है, फीफा अपने सदस्य संघों और देश के भागीदारों को उन युवाओं के साथ बातचीत करने के महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है जो स्कूल में नामांकित नहीं हैं।

फीफा अपने सदस्य संघों के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षण मंच और एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपकरण (फुटबॉल) प्रदान करेगा जो प्रशिक्षण सत्रों के लिए उपयोग में आसान सामग्री प्रदान करता है, क्योंकि कई स्कूलों में फुटबॉल गतिविधियों के लिए उपकरण और कुशल कर्मियों की कमी है। एप्लिकेशन का उद्देश्य शिक्षकों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों के लिए स्कूलों और समुदायों में एफ4एस कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से सुगम बनाना, कार्यान्वित करना और प्रशासित करना है।

एफ4एस कार्यक्रम प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों को समान रूप से प्रेरित करने के लिए एक आकर्षक मंच प्रदान करते हुए स्कूलों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है। एफ4एस कार्यक्रम को निर्देश या कक्षा के समय को प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है बल्कि, यह शिक्षकों के प्रयासों का समर्थन करने, शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार करने और सरकारों का समर्थन करने के लिए है। फुटबॉल में शैक्षिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने और 'जीवन के स्कूल' के रूप में काम करने की क्षमता है।

स्कूलों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम को लागू करने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, शिक्षा मंत्रालय और फीफा द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत इसे देश के सभी स्कूलों में 25 मिलियन विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाया जाना है।

निष्कर्ष

भारत में खेल परिदृश्य हाल के वर्षों में काफी बदल गया है। आज खेल देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रहा है। भारत प्रतिभा का भंडार है, खासकर खेल के क्षेत्र में। हाल में की गई इन सभी पहल ने खेल के संबंध में बहुत आवश्यक प्रणालीगत उपाय और मानसिकता में बदलाव किया है। सरकार देश में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खेल के प्रति सरकार का समग्र दृष्टिकोण और फिटनेस पर जोर भारत के खेल क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रहा है। खेल और फिटनेस भविष्य की यात्रा अभी शुरू हुई है। बच्चे जब सीखते हैं और खेलते हैं, समुदाय आगे बढ़ते हैं और राष्ट्र फलते-फूलते हैं। खेल हमारे देश के भविष्य के निर्माता छोटे बच्चों में आजीवन सीखने और उनमें चरित्र तथा नेतृत्व के गुणों को विकसित करने को बढ़ावा देने का एक माध्यम हैं। ■

संदर्भ

1. शिक्षा मंत्रालय, (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf से प्राप्त की गई है।
2. फिट इंडिया से संबंधित जानकारी https://fitindia.gov.in से प्राप्त की गई।
3. स्कूल कार्यक्रम के लिए फुटबॉल से संबंधित सूचना https://footballforschools.fifa.com/en से प्राप्त किया गया है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

युवा और स्वास्थ्य

डॉ चंद्रकांत लहरिया
डॉ रोडनी वाज़

युवाओं की परिभाषाएं भिन्न-भिन्न होती हैं पर सामान्यतया 15 से 44 वर्ष की आयु वाले युवा माने जाते हैं। इस प्रकार परिपक्व किशोर अवस्था (15 से 19 वर्ष) और प्रारंभिक वयस्क आयु (20 से 44 वर्ष) वालों को युवा माना जाता है। इस आयु वर्ग वालों में रोग और मृत्यु की आशंका कम से कम रहती है। हालांकि इस आयु वर्ग वालों के लिए सड़क यातायात में चोटिल होने जैसे कुछेक पहलू अक्सर जोखिम भरे रहते हैं। साथ ही, यह भी सही है कि इस आयु वर्ग में स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनाया जाने वाला शारीरिक व्यायाम और अनुशासन आगे चलकर व्यक्ति के स्वास्थ्य को सही बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में युवाओं की संख्या कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत के आसपास है। देश की आर्थिक प्रगति में युवाओं का बड़ा योगदान रहता है क्योंकि इस आयुवर्ग के लोग सभी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं और युवाओं की कार्यक्षमता और उत्पादकता भी अधिक होती है। भारत में आर्थिक वृद्धि की मुख्य क्षमता देश के गतिशील और उच्च कौशल वाले युवाओं से ही बनी हुई है। युवाओं को अपनी शारीरिक स्थिति, व्यवहार, आचरण, खानपान, कार्यशैली और अन्य पहलुओं के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं हैं:

मानसिक स्वास्थ्य : इस आयुवर्ग के लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कई कारणों से बड़ी चुनौती बना रहता है क्योंकि अव्वल तो हमारे यहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है और दूसरी वजह यह है कि हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में डॉक्टरों की सलाह लेने में लापरवाही बरतते हैं। युवा वयस्कों और किशोरों में मानसिक अवसाद और निराशा-हताशा का भाव आना भी मानसिक रोग या विकलांगता का बड़ा कारण बन जाता है। स्थिति गंभीर हो जाने पर तो आत्महत्या तक बात पहुँच सकती है। इसके पीछे अनेक कारण हैं जैसे पढ़ाई-लिखाई में या कार्यालय अथवा कार्यस्थल में अपेक्षित सफलता प्राप्त न कर पाना; हिंसा, गरीबी और बेरोज़गारी के कारण तनाव में रहना; किसी प्रकार के लांछन, अलगाव या भेदभाव; मानवीय संकट या कोविड-19 जैसी विकट स्थिति में फंसना, आदि।

शराब या ड्रग (नशीले पदार्थों) की लत: शराब या ड्रग (नशीले पदार्थ) और विशेषकर इंट्राविनस ड्रग (इंजेक्शन से नशीले पदार्थ शरीर में पहुँचाने) की लत से तो बेहद खतरनाक हालात बन सकते हैं और इनके शिकार होने वाले युवा एचआईवी/एड्स, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसे अनेक संचारी और गैर संचारी रोगों की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे मामलों में आर्थिक बोझ बढ़ जाने के कारण इन युवाओं और इनके परिवार के लोगों को मानसिक तनाव की स्थिति झेलते रहने को मजबूर होना पड़ जाता है।

तंबाकू सेवन : तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन, चाहे सिगरेट-बीड़ी पीने या गुटखा वगैरह खाने के जरिये हो पर इस लत

डॉ चंद्रकांत लहरिया जन-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली प्रतिष्ठान के वरिष्ठ कसंल्टेंट डॉक्टर और निदेशक हैं। उन्होंने करीब 15 वर्ष तक विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम किया है। ईमेल: c.lahariya@gmail.com
डॉ वाज़ नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिकल डॉक्टर और जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं।

की शुरूआत आमतौर पर किशोर अवस्था में ही लगती है। इसके साथ शराब पीने की आदत भी लग सकती है और इन नशों के मेल से अनेक घातक बीमारियों का खतरा मंडराने लग जाता है। तंबाकू सेवन से मुंह, गले, भोजन की नली या ग्रास-नली और फेफड़ों के कैंसर की आशंका और अनेक रोग होने का खतरा बन जाता है। फिर, तंबाकू खाने से उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ मेलेटस यानी मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक (लकवा), धमनियों में खून के थक्के जमने जैसी वैस्क्यूलर बीमारियां घेर सकती हैं।

शारीरिक निष्क्रियता : अनुमान लगाया गया है कि केवल 20 प्रतिशत युवा वयस्क ही दिन में 30 मिनट और सप्ताह में पांच दिन नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते हैं अथवा खेलकूद में हिस्सा लेते हैं। महिलाएं और लड़कियां तो खासतौर से व्यायाम और खेलकूद में हिस्सा नहीं ले पातीं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पर, शारीरिक हिलजुल कम होने से मोटापा, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, हृदय रोग और अन्य पुरानी बीमारियां होने की बहुत आशंका रहती है। शारीरिक निष्क्रियता से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।

डायबिटीज़ और उच्च रक्तचाप : डायबिटीज़ धीरे-धीरे महामारी का रूप लेती जा रही है और देश में 10 वयस्कों में से 1 तो अवश्य डायबिटीज़ का मरीज है। भारत के 5 वयस्कों में से 1 को उच्च रक्तचाप की शिकायत भी है। दोनों मामलों में खास परेशानी की बात यह है कि अधिकांश युवाओं को पता भी नहीं कि उन्हें यह तकलीफ है। हाल के वर्षों में पहले के मुकाबले कम आयु वाले युवा बड़ी संख्या में डायबिटीज़ के रोगी बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण शारीरिक व्यायाम न करना, अस्वास्थ्यकर भोजन खाना, वंशानुगत रोग जैसे पहलू हैं। इन दोनों खतरनाक बीमारियों से ही देश में हार्ट अटैक, या हृदयरोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

अन्य स्वास्थ्य समस्याएं : इन समस्याओं में दुर्घटनाएं, स्वयं से क्षतिग्रस्त हो जाना, कार्यस्थल में दुर्घटना होना आदि शामिल हैं। परस्पर मारपीट के रूप में हिंसा, घरेलू झगड़ों में हिंसा, कार्यस्थल में हिंसा, दबंगई/रैगिंग और यौन हिंसा जैसी घटनाएं भी होती रहती हैं।

युवावस्था के शुरू में ही इन समस्याओं के घेरे में आ जाने से बुढ़ापे में और खासकर पुरानी (क्रोनिक) बीमारियों के रूप में कठिनाई बढ़ जाती है। कम उम्र में ही इन परेशानियों की चपेट में आ जाने से आयु लंबी नहीं रह पाती, जीवन में सुख और चैन नहीं मिल पाता, खर्चे बेतहाशा बढ़ते जाते हैं और कम आयु में ही स्वास्थ्य से जुड़ी उलझनें बढ़ती चली जाती हैं, यहां तक कि मौत भी हो सकती है।

कॉलेज के विद्यार्थियों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। इस आयुवर्ग में ही युवाओं की अनेक शंकाएं और चिंताएं ऐसी होती हैं जिनका उन्हें समाधान नहीं मिल पाता, इन समस्याओं में मानसिक स्वास्थ्य, यौन स्वास्थ्य, नशे की लत और निजी स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं।

युवाओं का स्वास्थ्य सुधारना

स्वस्थ जीवन के तीन भेद हैं: संतुलित आहार, नियमित शारीरिक व्यायाम और पर्याप्त निद्रा। युवा अक्सर इनमें से एक या अधिक पहलुओं की अनदेखी करते चले जाते हैं। सरकार ने स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अनेक पहलें की हैं परंतु अभी युवाओं को इन सभी पर पूरा-पूरा ध्यान देना होगा। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में हेल्थ और वेलनेस सेंटर धारणा के अंतर्गत 'निरोगी' अर्थात् स्वस्थ जीवनचर्या अपनाकर रोगों को होने से रोकने पर बल दिया गया है। 'फिट इंडिया' पहल का उद्देश्य भी युवाओं सहित सभी लोगों में व्यायाम की आदत डालना है (बॉक्स 1)। इन सभी पहलों को युवाओं और सभी की दिनचर्या में शामिल करना होगा।

बॉक्स 1 : युवाओं को अधिक स्वस्थ बनाने की सरकारी पहल

क्र.	कार्यक्रम/पहल	विशेषताएं
1.	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके)	इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों पर जोर देना है। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्यान क्लिनिक-आधारित न होकर समुदाय, परिवार या स्कूल में किशोरों तक पहुँचने पर दिया जा रहा है।
2.	किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (एएफएचसी)	इसमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से चोट, हिंसा, नशीले पदार्थों के सेवन, पोषाहार, गैर संचारी रोग आदि सभी आते हैं। एएफएचसी के सभी भाग स्वीकार्य, समानता पर आधारित, पहुँच में, उपयुक्त और व्यापक हैं।
3.	पीयर (समवयस्क) शिक्षा कार्यक्रम	चुने हुए समवयस्क शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि किशोरों को आरकेएसके कार्यक्रम का लाभ प्राप्त हो। इन समवयस्क शिक्षकों को 'साथिया' कहते हैं। किशोरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से हर गांव/1000 की आबादी/आशा बस्ती में चार समवयस्क शिक्षक चुने जाते हैं जिनमें दो लड़के और दो लड़कियां रहती हैं।
4.	मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता पर ध्यान देने की योजना	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रखने का महत्व समझाने की योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें सेनेटरी नेपकिन के इस्तेमाल के बारे में जागरूक बनाया जाता है और इन नेपकिन्स के सुरक्षित निपटान की जानकारी दी जाती है।
5.	आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और वेलनेस केन्द्र	हेल्थ और वेलनेस केन्द्र निवारक और सुधारात्मक उपायों के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।
6.	फ़िट इंडिया	इस पहल से युवाओं में खेलकूद और शारीरिक व्यायाम के जरिये स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की रुचि पैदा की जाती है।
7.	अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम	युवाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से राष्ट्रीय कैंसर, डायबिटीज़, हृदय रोग, स्ट्रोक (लकवा) निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम जैसे कई स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रजनन, मातृत्व, नवजात देखभाल, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य (आरएमएनसीएचए) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे अनेक अन्य कार्यक्रम (एनएचएचपी) भी चलाए जा रहे हैं।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

युवाओं के स्वास्थ्य को जनआंदोलन का रूप देना

इस आयुवर्ग के लोगों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए हर संभावित उपाय का भरपूर लाभ लेने की जरूरत है। इसके लिए अन्य बातों के साथ ही स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों में भी प्रयास करने जरूरी हैं। स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत बनाना होगा ताकि मौजूदा दौर में फैल रहे विभिन्न रोगों के प्रकोप से बचाव हो सके। कॉलेज के विद्यार्थियों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। इस आयुवर्ग में ही युवाओं की अनेक शंकाएं और चिंताएं ऐसी होती हैं जिनका उन्हें समाधान नहीं मिल पाता, इन समस्याओं में मानसिक स्वास्थ्य, यौन स्वास्थ्य, नशे की लत और निजी स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं।

कार्यस्थल में स्वास्थ्य पर ध्यान देने के उद्देश्य से सभी बड़े कार्यालयों में भार मापने की मशीन बाथरूम में रखी जा सकती है, व्यायाम के लिए समय और उपकरण भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं तथा कैंटीन या कैफेटेरिया के मेन्यू में स्वास्थ्यप्रद खानपान की व्यवस्था भी आवश्यक है। कार्य करते समय अस्वस्थ महसूस होने पर या तनाव दूर करने के लिए कार्यस्थल में देखभाल की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। अक्सर खुद ही दवा या उपचार लेने वाले युवाओं को स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त तरीके और व्यवहार अपनाने का महत्व समझाना होगा। देश के युवाओं का स्वास्थ्य सुधारने की प्रक्रिया में परिवार और समुदाय का योगदान भी जरूरी है।

स्वस्थ जीवन शैली

आइए, मानसिक स्वास्थ्य और युवा से शुरूआत करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत भ्रामक और हीन भावनाएं फैली हुई हैं। इसी कारण से लोग डॉक्टरों से सलाह नहीं ले पाते। पर, असल में मानसिक रोग भी अन्य शारीरिक रोगों जैसे ही होते हैं। प्रशिक्षित डॉक्टरों की सही सलाह और उचित दवाओं के सेवन से शारीरिक और मानसिक, दोनों प्रकार के रोगों का उपचार हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि मानसिक रोगों पर चर्चा की जाए और इनसे जुड़ी हीनता की भावना को दूर किया जाए। मानसिक रोग होने पर चिकित्सक से मिलें। डरें या झिझकें नहीं। हमें मानसिक रोग के प्रति हीनतापूर्ण दृष्टिकोण त्यागना होगा।

नियमित शारीरिक व्यायाम पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता और इससे स्वास्थ्य सुधार में निश्चित लाभ मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों के अनुसार सप्ताह में कम से कम 150 मिनट सभी को मद्धम गति वाले एरोबिक व्यायाम करने चाहिए या फिर 75 से 150 मिनट तक तेज गति के एरोबिक व्यायाम अवश्य करने चाहिए। सबसे कम शारीरिक व्यायाम करने वाले देशों की सूची में भारत का नाम नीचे से आठवें स्थान पर है। रिपोर्टों के आधार पर 4 में से 3 किशोर और युवा सुझाई गई मात्रा से बहुत कम शारीरिक व्यायाम करते हैं। अध्ययन से पता चला है कि शारीरिक व्यायाम और हिलजुल कम रहने के कारणों में निजी स्तर पर लापरवाही, नकारात्मक परिणामों की गलत चिंता या भ्रम, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, समय का अभाव आदि प्रमुख हैं। इन भ्रामक धारणाओं को मिटाने और इन बाधाओं को समाप्त करने के प्रयास जरूरी हैं।

नियमित और कम से कम छह से आठ घंटे की नींद से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव दूर हो जाता है और हम स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्याओं और परेशानियों से बचे रहते हैं। इसलिए नींद का समय नियमित रखने और रोज पर्याप्त नींद लेने तथा सप्ताह भर इस दिनचर्या को बनाए रखने पर सभी को पूरा ध्यान देना चाहिए।

खेलकूद, स्वास्थ्य और युवा

स्वास्थ्य क्षेत्र की अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्था 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' ने खेल समुदाय के सहयोग से लोगों को खेलकूद की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से उनकी क्षमताओं को भरपूर बढ़ावा देने का खेलकूद और स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया है। यह तो भलीभांति सिद्ध हो चुका है कि विभिन्न खेलों में भाग लेकर शारीरिक व्यायाम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक जीवन का विस्तार होता है, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत विकास होता है तथा नशे की लत से बचे रहने में भरपूर मदद मिलती है।

निष्कर्ष

युवाओं की संख्या देश की कुल जनसंख्या की करीब 50 प्रतिशत है और हमारे युवा ही आर्थिक प्रगति और विकास के मूल आधार हैं। वैसे स्वस्थ जनसंख्या होने के बावजूद युवा अपनी आयु, व्यवहार और अन्य कारणों से अनेक समस्याओं का सामना करते हैं जिनसे वृद्धावस्था में उन्हें लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य-समस्याओं से जूझना पड़ता है। युवावस्था में स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले व्यवहार और दिनचर्या से बचे रहने से व्यक्तिगत, पारिवारिक और राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घावधि लाभ प्राप्त किया जा सकता है। युवाओं को लक्षित करके बनाई गई नीतियों में अधिक स्वास्थ्यर्द्धक दिनचर्या, नियमित शारीरिक व्यायाम और निवारक तथा उपचारात्मक उपायों पर और जोर दिया जाना चाहिए। आज का युवा स्वस्थ रहेगा तो देश का कल भी स्वस्थ ही होगा। ■

यह भी पढ़ें

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन शारीरिक व्यायाम और स्वास्थ्य https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
2. चंद्रकांत लहरिया. 'आयुष्मान भारत' कार्यक्रम और भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज. इंडियन पीडिएट्रिक्स 2018; 55:496-506
3. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ न्यूट्रिशन/डाइट्री गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। https://www.nin.res.in/downloaosQ/DietaryGuidelinesforNINwebsite.pdf
4. नेशनल यूथपॉलिसी, 2014. खेल और युवा मामलों का मंत्रालय। https://www.rgniyd.gov.in/sites/default/files/pdfs/scheme/nyp_2014.pdf पर उपलब्ध
5. चंद्रकांत लहरिया. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स टु स्ट्रेंग्थन प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया: कांसेप्ट, प्रोग्रेस एंड वेज़ फॉर्वर्ड. इंडियन जर्नल ऑफ़ पीडिएट्रिक्स 2020; 87: 916-29.

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंज़िल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

युवाओं के लिये मददगार पहलकदमियां

हेमांग जानी

"हमारे कर्मयोगियों के प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकारी विभागों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है"
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के नागरिकों की औसत आयु 29 वर्ष है। दरअसल, विश्व की युवा आबादी का पांचवां भाग भारत में ही निवास करता है। हम 'अमृत काल' में कदम रख चुके हैं। अब से 25 वर्ष बाद स्वतंत्र भारत 100 साल का हो जायेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत को 2025 तक 50 खरब यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये कटिबद्ध है। वह भारत को 2047 तक विकसित देशों की कतार में पहुँचाने के लिये प्रयासरत है। सरकार, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों के बीच तालमेल से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिये अनेक पहलकदमियां की जा रही हैं।

युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा जारी किया। इसमें संवहनीय विकास लक्ष्यों-सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) के अनुरूप युवाओं की प्रगति के लिये 10 वर्षों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इस नीति में शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता, युवा नेतृत्व और विकास, स्वास्थ्य, फिटनेस और खेलकूद तथा सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर-नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना-नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस) और नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) जैसी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान-राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट (आरजीएनआईवाईडी) शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम चलाता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन यह संस्थान भारत में युवाओं के विकास के लिये उत्कृष्टता केन्द्र के तौर पर काम करता है।

2020 में कोविड-19 की वैश्विक महामारी की वजह से भारत समेत समूचे विश्व को व्यापक सामाजिक-आर्थिक अवरोधों का सामना करना पड़ा। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी। यह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद-ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) का लगभग 10 प्रतिशत है। वैश्विक महामारी के दौरान घोषित इस पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों

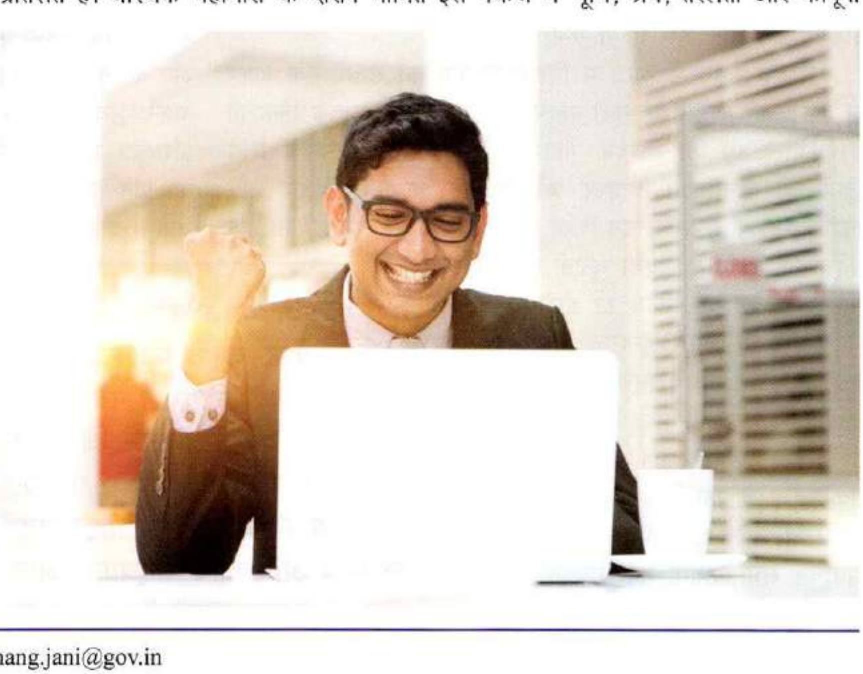

लेखक क्षमता विकास आयोग के सचिव हैं। ईमेल: hemang.jani@gov.in

DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING GOVERNMENT OF INDIA

12 महीनों में 10 लाख नौकरियां
पहली खेप में 75 हजार नियुक्तियां

रोज़गार मेला

नियुक्ति सुधारों की मिसाल

- रोज़गार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता
- रिक्तियों की मिशन के तौर पर पूर्ति
- नियुक्ति की सर्वोच्च स्तर पर निगरानी

पर विशेष जोर दिया गया। उस मुश्किल समय में युवाओं को शैक्षिक तनाव, सामाजिक दबाव, चिंता, अवसाद, आहार विकार और अध्ययन में कठिनाई जैसी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिये तनाव मुक्त माहौल बनाने के उद्देश्य से 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के जरिये उनसे संवाद किया। इस संवादात्मक कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक मंच पर लाया गया। नागरिकों के व्यवहार को प्रभावित कर उन्हें शारीरिक तौर पर सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने के मकसद से 2019 में 'फिट इंडिया' अभियान शुरू किया गया।

मौजूदा समय में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या एक हजार से अधिक है जिनसे हर साल लगभग 85 लाख नये स्नातक निकलते हैं। कोविड-19 की वैश्विक महामारी और इससे निपटने के लिये किये गये लॉकडाउन ने छात्रों को प्रभावित किया। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा शुरू की गयी मगर प्रौद्योगिकी तक पहुँच का अभाव एक बड़ी चुनौती था। सरकार का 'स्वयं प्रभा' कार्यक्रम 22 डीटीएच चैनलों के समूह के जरिये दूरदराज के विद्यार्थियों को हर वक्त गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तक पहुँच बनाने में मदद कर रहा है। 'पीएम ई-विद्या' के जरिये 25 करोड़ स्कूली छात्रों तक पहुँचा जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और ऑनएयर शिक्षण से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट कर शिक्षा तक बहुविध पहुँच सुनिश्चित करना है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी के लिये राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन-नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी (एनईएटी) का गठन किया है। इसका क्रियान्वयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद-ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के माध्यम से किया जा रहा है। यह गठबंधन शिक्षा प्रौद्योगिकी व्यवसायों, शैक्षिक संस्थानों और छात्रों के बीच सेतु का काम करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किफायती बनाने के उद्देश्य से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिये अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गयी हैं। सरकार ने भारत को शिक्षा का वैश्विक केन्द्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 2020 में नयी शिक्षा नीति लागू की। डिजिटल विभाजन मिटाने में मददगार 'स्वयं' पोर्टल पर नौवीं से स्नातकोत्तर कक्षा तक के छात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल पर पंजीकरण मुफ्त है और छात्र विशेष पाठ्यक्रमों के लिये क्रेडिट प्राप्त कर उन्हें अपने शैक्षिक रिकॉर्ड में जोड़ सकते हैं।

सरकार ने भारत को शिक्षा का वैश्विक केन्द्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 2020 में नयी शिक्षा नीति लागू की। डिजिटल विभाजन मिटाने में मददगार 'स्वयं' पोर्टल पर नौवीं से स्नातकोत्तर कक्षा तक के छात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने 'रोज़गार मेला' के जरिये 10 लाख कर्मियों की नियुक्ति का अभियान शुरू किया है ताकि युवाओं के लिये कॅरियर के अवसरों में इजाफा हो। इसके तहत पिछले साल अक्टूबर में 75000 और नवंबर में 71000 नियुक्तिपत्र सौंपे गये। माननीय प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम में 'कर्मयोगी भारत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म' और 'कर्मयोगी प्रारंभ' का शुभारंभ किया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 'कर्मयोगी भारत' को सभी सरकारी कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिये विशेष उपाय के तौर पर शुरू किया गया है। यह समेकित शासकीय ऑनलाइन प्रशिक्षण-इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (आईगॉट) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म संचालित करता है। 'कर्मयोगी प्रारंभ' विभिन्न सरकारी विभागों के सभी नवनियुक्त कर्मियों के लिये ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिये आचार संहिता, कार्यस्थल आचरण और सत्यनिष्ठा, मानव संसाधन नीतियों तथा अन्य लाभों और भत्तों को शामिल किया गया है जिनसे उन्हें नीतियों को समझ कर अपनी नयी भूमिका को सहजता से अपनाने में मदद मिलेगी। वे आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर अन्य पाठ्यक्रमों के जरिये अपने ज्ञान, कौशल और दक्षता को बढ़ा सकते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अपने 'स्किल इंडिया मिशन' के तहत देश भर में 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला' आयोजित कर रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षुता के लगभग 10 लाख अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 2026 के अंत तक ऐसे लगभग 60 लाख अवसर उपलब्ध होंगे। इस मेले का लक्ष्य हर साल 10 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिये प्रशिक्षित करना है। सरकार ने सुधार के जो उपाय किये हैं उनमें सशस्त्र बलों में युवाओं की नियुक्ति के लिये 'अग्निपथ योजना' शामिल है। इस योजना के अंतर्गत 46 हजार युवाओं को चार वर्षों के कार्यकाल के लिये 'अग्निवीर' नियुक्त किया जायेगा। इस पहल का मकसद भविष्य की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने के लिये सशस्त्र बलों के स्वरूप को ज्यादा युवा, फिट और वैविध्यपूर्ण बनाना है।

नवोन्मेष और उद्यमिता के रहनुमा के रूप में भारत अपनी युवा आबादी को अन्वेषण और प्रगति के असंख्य अवसर मुहैया कराता है। विश्व बैंक की 2022 की व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में भारत का स्थान 190 अर्थव्यवस्थाओं में 63वां है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग-डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने दिसंबर 2022 तक 'स्टार्टअप इंडिया' के तहत 86227 स्टार्टअप संस्थाओं को मान्यता दी है। वह युवा उद्यमियों की वित्त प्रबंध, नियामक समर्थन और बाजार तक पहुँच के माध्यम से सहायता कर रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) और अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) के हाल के एक आकलन के अनुसार आर्थिक विकास और सुधारों पर सरकार के बल के परिणामस्वरूप भारत अगले पांच वर्षों में 475 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में सक्षम है। भारत में 10 लाख बच्चों को नवोन्मेषक के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 722 जिलों में लगभग 10 हजार अटल परिवर्तन प्रयोगशालाएं- अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) चलायी जा रही हैं। इन प्रयोगशालाओं में 7.5 करोड़ से अधिक छात्र 5800 से ज्यादा परिवर्तन दूतों के साथ सक्रियता से हिस्सा ले रहे हैं। भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के प्रभावशाली निर्यात और अन्य कारकों की बदौलत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन-वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गनाइजेशन (डब्ल्यूआईपीओ) के 2022 के वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में 132 देशों में 40वें स्थान पर रहा। वर्ष 2014 में 'मेक इन इंडिया' की शुरुआत की गयी और यह नवोन्मेष, विश्वस्तरीय अवसंरचना के निर्माण तथा भारत को मैनुफैक्चरिंग और डिजाइन का केन्द्र बनाने में मददगार है। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में की गयी और यह इंटरनेट की पहुँच बढ़ा कर देश की ऑनलाइन अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार करते हुए प्रौद्योगिकी के जरिये इसका सशक्तीकरण कर रहा है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बाद वित्त-प्रौद्योगिकी, ई-स्वास्थ्य और ई-शिक्षा के बढ़ते उपयोग के कारण भारत में 2026 तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या एक अरब हो जायेगी। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी संचार नेटवर्क को मज़बूत करने के लिये अक्टूबर 2022 में समूचे देश में 5जी सेवाओं का शुभारंभ किया।

भारत के युवा देश की प्रशासनिक सेवा की प्रमुख संचालन शक्ति हैं। प्रशासनिक कर्मचारी सरकारी सेवाओं को समाज के आखिरी छोर तक प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार के क्षमता विकास आयोग-कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन (सीबीसी) की स्थापना 01 अप्रैल 2021 को की गयी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिये अत्याधुनिक अवसंरचना के माध्यम से सरकार की मानव संसाधन प्रबंधन पद्धतियों में आमूल सुधार करना है। इस पहल को राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम-नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग (एनपीसीएससीबी) - मिशन कर्मयोगी नाम दिया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा क्षमता विकास कार्यक्रम है जिसके दायरे में केन्द्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के सरकारी कर्मचारी आयेंगे। सीबीसी अमृत काल में इक्कीसवीं सदी के प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित और भविष्य के लिये तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उसका लक्ष्य भारतीय परंपराओं में रची एक ऐसी सक्षम प्रशासनिक सेवा का निर्माण है जिसे भारत की प्राथमिकताओं की समझ हो और जो सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावशाली और कुशल डिलीवरी के लिये काम कर सकें। क्षमता विकास में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, उभरती प्रौद्योगिकियों और नागरिक केन्द्रीयता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सीबीसी ने देश भर में 14000 एनवाईकेएस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये संयुक्तराष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान-यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च (यूएनआईटीएआर) के साथ मिल कर ऑनलाइन क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है। इस कार्यक्रम में नेतृत्व, संचार कौशल और स्वयंसेवा जैसे पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। सीबीसी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में क्रियान्वयन के लिये इसी तरह के कार्यक्रमों और वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं का संयोजन कर रहा है।

राष्ट्र निर्माण हेतु कर्मयोगी
स्रोत : www.cbc.gov.in

भारतीय युवाओं के सामने मौजूद चुनौतियों से सरकार मिशन के तौर पर निपट रही है। लेकिन अकेले सरकार के पास सभी चुनौतियों का हल नहीं है। इस मुहिम में निजी और धर्मादा क्षेत्रों की समान भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन में कोविड-19 के मामलों में हाल की वृद्धि, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और वर्तमान की भू-राजनीतिक चुनौतियां विश्व के लिये चिंता के बड़े कारण हैं। भारत की 2023 की जी-20 की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। विश्वास है कि भारत की इस ध्येय के साथ जी-20 की अध्यक्षता विश्व के नेताओं को एकजुट कर वैश्विक नागरिकों को शांति और संपन्नता प्रदान करने में सहायक होगी। वाई-20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय संवाद और चर्चाओं से खास तौर से युवा वर्ग नीति-निर्माण को प्रभावित करने में सक्षम होगा। कामकाज के भविष्य, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम को घटाने के उपायों, शांति और सुलह तथा लोकतंत्र में युवा जैसे विषयों पर केंद्रित वाई-20 का आयोजन जी-20 शिखर सम्मेलन के साथ ही किया जायेगा। ■

संदर्भ

1. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार
2. विश्व बैंक की रिपोर्ट
3. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार
4. क्षमता संवर्द्धन आयोग अभिलेखागार

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

युवाशक्ति और पर्यावरण

अविनाश मिश्र
मधुबंती दत्ता

समृद्ध और रहने योग्य नगरों के विकास के लिए हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटाने की जरूरत है। इसलिए जब बात पर्यावरण की हो तो युवा लोगों की विशिष्ट जरूरतें एवं जिम्मेदारियां बनती हैं। उनमें विश्व में सबसे असरकारी परिवर्तन लाने की क्षमता निहित है। युवाओं को पर्यावरण संरक्षण कार्य से जोड़ने का सीधा सकारात्मक असर उनके विचार और व्यवहार के अलावा, उनके परिवारों और संभवतः अभिभावकों पर भी पड़ता है।

हमारी पृथ्वी हमारा घर है और हमें जीवित रखने के स्रोत उपलब्ध कराती है और इसीलिए जरूरी हो जाता है हम प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें। नृजातीय गतिविधियों के कारण कार्बन उत्सर्जन, वन कटाई और भूक्षरण से हमारे पारिस्थितिक-तंत्र तथा पर्यावरण जैवविविधता को नुकसान पहुँचता है। मिल्टन फ्राइडमैन (1962) के कथन के विपरीत, पारिस्थितिक मूल्य प्रचलित मानकों में अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं, जिस कारण उनके अवमूल्यन और शोषण का पता चलता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 को 'जैवविविधता का दशक' घोषित किया था। विभिन्न सामरिक योजनाओं और प्रयासों के जरिए लोगों को एकजुट करने और निर्णायक समय के अंत तक पहुँचने पर भी हम निर्धारित लक्ष्यों से अच्छे-खासे दूर हैं। इसलिए हमें निरंतर क्षरित हो रही जैवविविधता से लड़ने और पर्यावरण संरक्षण के मार्ग को दुरुस्त बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी।

जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट संभाषण (2022-23) में कहा था कि भारत के विकास में जलवायु परिवर्तन की समस्या सबसे नकारात्मक बाहरी समस्या है। 'पंचाम्रत' की कम कार्बन विकास नीति सही मायनों में संधारणीय विकास के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस संबंध में वानिकी और कार्बन पृथक्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कृषि और वन भूमि तथा जल विकास एवं भंडारण जैसे दो तरीके बेहद किफायती साबित हो सकते हैं।

इसके साथ ही, हमें कम कार्बन फुटप्रिंट वाले समृद्ध तथा रहने योग्य शहरों का निर्माण भी करना होगा। इसके लिए प्राथमिकता होगी ग्रीन स्पेस की, ऊर्जा मामले में किफायती इमारतें, जलापूर्ति में सुधार और अपशिष्ट एवं शहरी यातायात से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना।

युवा : भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शक

युवाओं द्वारा प्रेरित जलवायु संरक्षण कार्य इस संबंध में समग्र गुणकारी शिक्षा को बढ़ावा देने में कारगर रहेगा; जिसके मार्फत हम 2030 तक पृथ्वी पर जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने तथा भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवनशैली सुनिश्चित कर पाएंगे। साथ ही, कभी-कभार 'अर्बन यूथ बल्ज' कहलाने वाली बढ़ती युवा आबादी के समग्र असर की पृष्ठभूमि में शहरी युवाओं से जुड़े विभिन्न पक्षों पर ध्यान देना भी जरूरी हो जाता है। युवा ही समाज के सबसे कीमती और सक्रिय मानव संसाधन स्रोत हैं, जिन्हें भावी पीढ़ियों का 'मार्गदर्शक' भी कहा जाता है। जब बात आती है पर्यावरण की तो युवाओं की विशिष्ट जरूरतें एवं ज़िम्मेदारियां होती हैं। उन्हें निरंतर क्षरित हो रहे पर्यावरण में अधिक लंबा समय गुज़ारना होगा; इसीलिए उन्हें पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के असरकारी हल खोजने के लिए अधिक सक्रिय होना होगा। ग्रीनहाउस उत्सर्जन, बदलती जलवायु से उठने वाली स्वास्थ्य चिंताएं, जलवायु परिवर्तन के असर और ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए पूर्णतया केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। इस संबंध में निकट भविष्य में सामरिक रूपरेखा वाले ढांचे, नीतियां एवं पद्धतियां; व्यावहारिक ज़मीनी शोध; जैवविविधता संरक्षण एवं भूमि प्रबंधन, संकट एवं आपदा प्रबंधन तथा अन्य तरीके अपनाने होंगे।

असरकारी परिचालन के लिए एसडीजी (संधारणीय विकास लक्ष्य) पर हमें तुरंत ध्यान देना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, शासन प्रणाली और निर्णय लेने में युवाओं का वास्तविक तथा

अविनाश मिश्र (प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग), नीति आयोग के सलाहकार हैं। मधुबंती दत्ता, नीति आयोग से संबद्ध युवा प्रोफेशनल हैं।
ईमेल: amishra-pc@gov.in

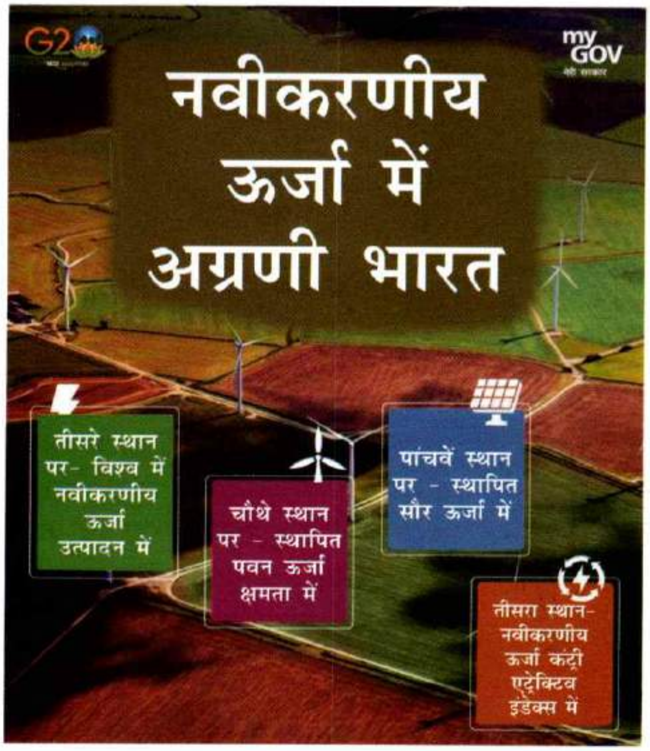

समुचित इस्तेमाल एक तरीका हो सकता है। किसी भी देश की शांति एवं सुरक्षा तथा प्रगति एवं विकास का प्रमुख कर्णधार बनने की क्षमता युवाशक्ति में होती है। युवाओं के पास दुनिया में सबसे असरकारी परिवर्तन लाने की ताकत भी होती है, ताकि वह राजनीतिक उत्सर्ग और उचित स्रोत उपभोग को बेहतर स्थान बन सके। इस समय विश्व में 10 से 24 आयुवर्ग के 1.8 अरब लोग हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत विकासशील देशों में रह रहे हैं, जहां उनका आबादी प्रतिशत भी अच्छा-खासा है। संधारणीय शहरों एवं बेहतर जीवनशैली के लिए, हमें युवाओं की महत्वाकांक्षाओं, रचनात्मकता तथा क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। 2030 के निकट पहुँचते हुए, संधारणीय विकास परियोजनाओं को बनाने और अमल में लाने के लिए युवाओं का नजरिया भी ध्यान में रखना होगा। जिस आधार पर हम युवाओं को हमारे साझा भविष्य, नई चुनौतियों से निपटने और अवसरों को आकार देते हुए देखेंगे।

युवा और एसडीजी की भूमिकाएं

चिंतक - युवा मौजूदा शासन तंत्र, परिवर्तन में रुकावटों एवं असंगति तथा पूर्वाग्रहों को पहचानने और उससे जूझने की क्षमता रखते हैं।

परिवर्तनशीलता - युवा दूसरों को प्रेरित कर कार्रवाई कर सकते हैं। वैश्विक तौर पर सोशल मीडिया की पहुँच और संपर्क के माध्यम से युवा सक्रियता में बढ़ोतरी हो रही है।

प्रवर्तक - युवाओं के पास ऐसे विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान एवं गहरी समझ होती है, जो अन्य वयस्कों के पास नहीं होती। साथ ही, वह उन मुद्दों पर नए विचार भी दे सकते हैं। अपने समक्ष मुद्दों से सीधे तौर पर जुड़े होने के कारण वह उन पर नया नज़रिया और अभिनव हल भी दे सकते हैं।

संचारक - युवा शक्ति एकजुट होकर स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय तौर पर अपने साथियों एवं सामुदायिक स्तर पर विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती है।

अगुआ - अपने अधिकारों एवं नेतृत्व क्षमताओं के प्रति जागरूक होकर युवाशक्ति अपने समुदाय एवं राष्ट्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो सकती है। इसलिए युवा नेतृत्व वाले संगठनों एवं नेटवर्कों को सशक्त करने की जरूरत है क्योंकि वे हाशिये पर पड़े बच्चों में चेतना का संचार कर उनमें नागरी नेतृत्व क्षमता का विकास कर सकते हैं।

पर्यावरण के पक्ष में अभ्यास और नियामकों को अपनाने के लिए एकजुट युवा आवाज़ उठाते हुए, इस दिशा में पहल की अगुवाई भी कर रहे हैं। युवा शक्तियों की ये पहल स्थानीय परियोजनाओं से वैश्विक अभियानों तक फैली हैं और इनमें से कुछ की पहुँच तो निर्णायक ताकतों तथा राष्ट्रीय नेतृत्व तक हैं। अधिकाधिक तौर पर एकजुट होते युवा दूसरों को शिक्षित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से भी अपनी पहुँच में इज़ाफा कर रहे हैं। युवा एसडीजी के और विशेषकर एसडीजी 15 के 'लाइफ ऑन लैंड' प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो पृथ्वी पर स्थलीय पारिस्थितिकी-तंत्र, वनों एवं जैवविविधता के संरक्षण एवं उद्धार का कार्य करता है।

एजेंडा की सफलता के महत्वपूर्ण पक्षों में, स्थानीय एवं राष्ट्रीय सरकारों के साथ मिलकर ज़मीनी स्तर पर योजनाओं और कार्यक्रमों को अमल में लाना, 2030 के एजेंडा को मूर्तरूप देने के लिए सरकारी-निजी सहभागिता की भूमिका, और डेटा एकत्रण के लिए तकनीक को वित्तीय सहयोग एवं उसका लाभ उठाना तथा योजना के न्यायोचित एवं विविध डिजाइन, अमलीकरण, निरीक्षण एवं आकलन में युवा सहभागिता शामिल हैं।

नीतिगत कार्रवाइयां

युवावर्ग राष्ट्र की रीढ़ होता है। पर्यावरण संरक्षण और सुधार में युवाशक्ति सक्रिय भूमिका निभा सकती है। वह अपनी जीवनशैली में बदलाव कर, पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके विपरीत असर को कम कर सकती है। पर्यावरण हितैषी अभ्यासों को अमल में लाकर, विभिन्न वस्तुओं का पुनर्चक्रण और जल एवं ऊर्जा जैसे स्रोतों के संरक्षण के माध्यम से वह अपने घरों, स्कूलों और युवा संगठनों को अधिक पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं। युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के कार्य से जोड़ने का उनके परिवारों और संभवत: उनके अभिभावकों के साथ-साथ खुद उनके अपने विचार और व्यवहार पर भी सकारात्मक असर पड़ता है।

युवावर्ग राष्ट्र की रीढ़ होता है। पर्यावरण संरक्षण और सुधार में युवाशक्ति सक्रिय भूमिका निभा सकती है। वह अपनी जीवनशैली में बदलाव कर, पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके विपरीत असर को कम कर सकती है।

सरकारी नीतियों से उम्मीद की जाती है कि वह सीधे युवा रोज़गार की सुविधाएं मुहैया कराएं और शहरों में पूर्ण एवं समुचित रोज़गार उपलब्ध हों। राष्ट्रीय नागरी योजना के हिस्से के तौर पर शहरी अधिकरण को रोज़गार विकास के लिए अनुकूल नीतियों को बनाने और अमल में लाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पर्यावरणीय रख-रखाव

और शहरी जीवन, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण परिवर्तन के साथ-साथ मौजूदा समय में चल रही जैवविविधता तथा पारिस्थितिक-तंत्र की देखरेख तथा शहरों में प्रत्येक स्तर पर उनकी पैठ को जानने के लिए उक्त सभी विषयों की गहरी समझ की जरूरत होती है, ताकि प्राकृतिक तौर पर सौहार्दपूर्ण आर्थिक मॉडल स्थापित किया जा सके। अवसंरचना पर खर्च का शहरी आर्थिक विकास, समृद्धि, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संधारणीयता एवं स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण सकारात्मक असर पड़ सकता है।

'लाइफ' अभियान में लोगों को कम उपभोग के साथ प्रतिदिन संयुक्त प्रयास से संधारणीय भविष्य की ओर कदम बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की सहभागिता को सशक्त करने से सरकारी संस्थानों, स्थापित गैर-सरकारी संगठनों एवं बहाली परियोजनाओं में अवसरों की आंशिक रूप से वृद्धि हो सकती है; जैसा कि नवीकृत सक्रियतावाद के पिछले उदाहरणों से पता चलता है इस दिशा में नवीन कार्रवाई आंशिक रूप से खुद युवाओं का ही कार्य है; और आंशिक रूप से यह मीडिया द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रेषण और असरकारी पर्यावरणीय शिक्षा का सवाल है। पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने हेतु, पर्यावरण की शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। समाज को पर्यावरण की चिंता के समक्ष लाने और संभालने में उसका ज्ञानाधार बेहद महत्वपूर्ण कारक है। और इस ज्ञानाधार के विकास में पहला कदम पर्यावरण की शिक्षा से जुड़ा है।

युवाओं में पर्यावरण के प्रति गहरी ज़िम्मेदारी और चिंता का भाव दिखता है। दीर्घकालिक जीवन की उम्मीद में उन्हें अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियों द्वारा लंबे समय से विरासत में दिए जा रहे खराब पर्यावरण के असर से लड़ना होगा। परंतु सौभाग्यवश युवाओं में नवाचार की असाधारण क्षमता, और सक्रियता बढ़ाने की नवीन विधियां मिलती हैं तथा वह पर्यावरण की समस्याओं के असरकारी तरीके तलाश सकते हैं। हालांकि, मौजूदा नीति-निर्माण ढांचे में भावी पीढ़ियों की समस्याओं को उठाना चुनौतीपूर्ण कार्य है(फिर भी, अंततः समयावधि को बढ़ाना ही ठीक रहेगा, परंतु सुदूर भविष्य तक नहीं, केवल मौजूदा निर्णय प्रक्रिया के सीमित नज़रिए से कुछ आगे बढ़कर।

युवाओं ने हाल में संधारणीय विकास की वैश्विक बैठक में दिखाया कि वह सामाजिक आदर्शों और न्यायिक विचारों को केंद्र में ला सकते हैं। शायद किसी भी अन्य वर्ग के मुकाबले युवा सबसे अधिक इस विचार से अवगत हैं कि दुनिया शून्य-संचय के सिद्धांत या पर्यावरण बनाम अर्थव्यवस्था आधार पर नहीं चलती। इसलिए असरकारी पर्यावरणीय शिक्षा ही पर्यावरण के मुद्दों से जूझने के लिए युवाओं को तैयार कर सकती है। युवाओं के लिए पर्यावरणीय मुद्दों पर मीडिया सूचना का प्रमुख स्रोत है। इसलिए, पर्यावरणीय शिक्षकों एवं मीडिया द्वारा संधारणीय विकास के लिए सामाजिक शिक्षा प्रक्रिया हेतु ज्यादा एकजुट प्रयास करने की जरूरत है।

पर्यावरण का सम्मान करने वाली संधारणीय जीवनशैली सम्मान योग्य है। अपने स्रोत के इस्तेमाल और पुनः उपयोग के लिए हमें निर्णयात्मक कदम उठाना ही होगा। मौजूदा दौर में विश्व को जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता हनन और प्रदूषण एवं अपशिष्ट के तिहरे संकट से जूझना पड़ रहा है। इन समस्याओं के लिए दशकों से चला आ रहा कठोर और असंधारणीय उत्पादन एवं उपभोग जिम्मेदार है। इसलिए हमारे जीने और उपभोग का तरीका महत्वपूर्ण ही नहीं, बेहद महत्वपूर्ण है। गत वर्ष ग्लासगो में पार्टीज़ टू द यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (सीओपी26) के 26वें सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री ने 'लाइफ' की अवधारणा सबके सामने रखी थी। इस विचार के अंतर्गत, 'बेतरतीब और व्यर्थ उपभोग' की बजाय 'सचेत और सतर्क इस्तेमाल' से जुड़ी पर्यावरणीय तौर पर चेतन जीवनशैली के विचार को बढ़ावा था। 'लाइफ' अभियान में लोगों को कम उपभोग के साथ प्रतिदिन संयुक्त प्रयास से संधारणीय भविष्य की ओर कदम बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही, सोशल नेटवर्कों की मदद से लाइफ अभियान जलवायु परिवर्तन के संबंध में सामाजिक मानकों पर भी असर डालने का प्रयास करता है। इस मिशन के तहत 'प्रो-प्लेनेट पीपल' (पी3) नामक ग्लोबल नेटवर्क का गठन और उसके प्रोत्साहन की योजना है, जिसमें पर्यावरणीय हितैषी जीवनशैलियों के प्रति साझा प्रतिबद्धता देखने को मिलेगी। पी3 समुदाय के माध्यम से, मिशन ऐसा पारिस्थितिकी-तंत्र तैयार करना चाहता है जिसमें पर्यावरण समर्थित आत्मस्थायी व्यवहार मज़बूत हो। मिशन के तहत 'इस्तेमाल-और-फेंकने' की मौजूदा सोचहीन तथा घातक सोच के स्थान पर, सचेत और सुविचारित उपभोग पक्ष वाली अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। इसलिए, हमारे देश के संधारणीय भविष्य के लिए युवाओं को 'लाइफ' के विचार को गंभीरता से मानना चाहिए।

समर्थन, जागरुकता-बढ़ाना और क्षमता-विकास

राष्ट्रीय संधारणीय विकास विमर्श के मामले में वर्कशॉप्स और अभियानों के माध्यम से युवा पक्ष को अर्थपूर्ण रूप से जोड़ने में युवा संगठन अग्रणी रहते हैं। सहभागी इस लक्ष्य को अपने बराबर के लोगों के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता विकास से प्राप्त करते हैं। फिर भी, जहां एक ओर यह युवा संगठन जन-योजना प्रक्रिया निर्माण में लगातार नीति-निर्माताओं एवं सरकारी प्रतिनिधियों की मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, यह संगठन निरंतर वित्त, स्रोत एवं पहचान आदि के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए इन युवा-नेतृत्व संगठनों की वित्तीय एवं नियामक सहयोग के जरिए विकास गतिविधियों से जुड़ी क्षमता और जागरुकता बढ़ाई जा सकती है। इसके अंतर्गत, शैक्षिक अनुभव हेतु दुनिया भर से युवाओं को जोड़ने तथा उनमें वैश्विक मुद्दों के प्रति रुचि पैदा करने एवं कार्रवाई करने के लिए एनालॉग एवं डिजिटल शिक्षण स्रोत का रोचक तरीके से इस्तेमाल हो सकता है।

सरकारें भी स्थानीय, राज्यीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर, 2030 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, पारिस्थितिकी-तंत्र की संधारणीयता में तेजी लाने के लिए युवा पहल और गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रति जागरूक हो रही हैं।

भविष्य की राह

युवा उद्यमशीलता ऐसे परिवेश में सबसे अधिक सफलता प्राप्त करती है जिनमें उसे समग्र व्यापार-सहिष्णु माहौल के साथ-साथ

शिक्षा, वित्त, नेटवर्किंग और मार्केट डेवलपमेंट और लक्ष्य केंद्रित तकनीकी सहयोग प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, युवा उद्यमियों को सहयोग करने वाले माहौल में सशक्त वाणिज्यिक परिवेश सम्मिलित होना चाहिए। इसका अर्थ यह कि व्यापारिक माहौल को बढ़ावा देना जरूरी तो है, परंतु केवल इतना भर ही नाकाफी होता है। दरअसल, युवाओं की क्षमता विकास के लिए सामाजिक उद्यमशीलता वाले पारिस्थितिकी-तंत्र में समग्र एवं लक्ष्य-केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत होती है। हालांकि, आमतौर पर यह माना जाता है कि युवा उद्यमी आर्थिक, सामाजिक विकास एवं समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, परंतु मौजूदा पारिस्थितिकी-तंत्र यदा-कदा ही उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करता है। इसलिए, सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी-तंत्र अमल में लाने पर ही युवा विकास एवं सकारात्मक सामाजिक असर से जुड़ी पूर्ण क्षमता को मूर्तरूप दिया जा सकता है।

युवा उद्यमियों को सहयोगपूर्ण परिवेश की जरूरत होती है। सामाजिक उद्यम आरंभ करने वाले युवाओं को सहयोगपूर्ण परिवेश मिलने से वह रचनात्मकता, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा, युवाओं में बेरोज़गारी दूर करने और अल्प रोज़गार के साथ संधारणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। नए उद्यमों का परिवेश ऐसी साक्ष्य-आधारित नीति पर स्थित हो, जिसमें युवाओं सहित भिन्न सहभागी शामिल रहें और उसमें उस तंत्र-विशेष के सभी अवयवों के बीच सहयोगपूर्ण माहौल हो।

हरित करियरों के लिए रोज़गार प्रणाली और शैक्षिक कार्यक्रमों को मज़बूत करने की जरूरत होती है। राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों हेतु न्यायसंगत एवं समावेशी भविष्य तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम, शोध, करियर काउंसलिंग और रोज़गार की मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी पाठ्यक्रमों में पर्यावरणीय एवं संधारणीय सामाजिक विकास सूचना एवं कौशल को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी शिक्षित कर्मी या नियोक्ता, उपभोक्ता, सामुदायिक सदस्य एवं निवेशक बन सकें। हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना एसडीजी पेशेवरों, हरित नियोक्ताओं और शैक्षिक संस्थानों के बीच संबंधों को भी मज़बूत करेगी। ■

संदर्भ

1. State of the Urban Youth Report 2012-2013
2. Beyond 2030: Youth Taking Charge of the Environment, Department of Economic and Social Affairs Capacity Building, UN
3. Youth and the Environment, World YOUTH Report, 2003
4. Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development UN, 2018
5. UCN's EU Programme Manager for Nature-Based Solutions. 2018. 'In the Spirit of Nature'. The Nature of Cities. 21 January 2018.
6. World Programme of Action for Youth, Department of Economic and Social AffairsYouth, UN.
7. Green Jobs for Youth, UNEP, https://www.unep.org/explore-topics/education-environment/what-we-do/green-jobs-youth

एन्डनोट्स

1. Budget Highlight - Key Features of Budget 2022-2023, Ministry of Finance, Budget Speech by Finance Minister
2. State of the Urban Youth Report 2012-2013
3. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1831364
4. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1831364

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

फुटबॉल की दुनिया

शिवेन्द्र चतुर्वेदी

दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय खेलों में शामिल फुटबॉल भारत में भी लोकप्रियता के ऊँचे पायदान पर रहा है। भारत, दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां फुटबॉल की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी। देश में पेशेवर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग, 2007 में आई लीग और 2014 में इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई।

पिछले वर्ष के आखिरी माह यानी दिसंबर 2022 में कतर में फीफा विश्व कप सम्पन्न हुआ। फुटबॉल को दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में माना जाता है। 1930 के पहले फीफा विश्वकप से लेकर हाल ही में कतर में आयोजित हुए 22वे फीफा विश्व कप तक, इस महाआयोजन ने लंबा रास्ता तय किया है।

विश्व फुटबॉल संघ (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन) की स्थापना

विश्व स्तर पर फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा यानी इसका फ्रेंच भाषा में बोले जाने वाला पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसके संस्थापक देशों में स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डैनमार्क, स्वीडन और स्विटजरलैंड शामिल थे और फ्रांस के रॉबर्ट गुएरिन को विश्व फुटबॉल संघ अर्थात् फीफा का पहला अध्यक्ष चुना गया था।

इंग्लैंड को आधुनिक फुटबॉल का जनक कहा जाता है, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि यह देश, विश्व फुटबॉल की प्रतिनिधि संस्था फीफा के संस्थापक देशों में शामिल नहीं था। दरअसल फुटबॉल का प्रचार-प्रसार खास तौर पर इंग्लैंड में, फीफा के गठन के काफी पहले 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच हो चुका था। वर्ष 1815 में ईटन बर्ग में सबसे पहले फुटबॉल के नियम बनाए गए और 24 अक्टूबर 1854 को दुनिया के प्रथम फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई जिसे शेफील्ड फुटबॉल क्लब के नाम से जाना जाता है। फीफा ने सारी दुनिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने और इसे पेशेवर अंदाज में आगे बढ़ाने के प्रयासों के तहत 1930 में पहले विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन किया। लैटिन अमरीकी देश उरुग्वे में आयोजित पहले फीफा विश्व कप में 13 देशों ने भाग लिया और फाइनल में मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहला विश्व कप फुटबॉल विजेता बनने का गौरव हासिल किया।

ओलंपिक खेलों में पहली बार फुटबॉल

फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में पहली बार 1908 के लंदन ओलंपिक में एक पदक स्पर्धा के तौर पर शामिल किया गया था और उरुग्वे ने 1924 और 1928 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर, विशिष्ट उपलब्धि अर्जित की थी। 1930 का वर्ष, उरुग्वे की स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष था और इन्हीं कुछ कारणों से, पहले फीफा विश्व कप के आयोजन स्थल के रूप में उरुग्वे को चुना गया था। वर्ष 1930 से 1970 तक विश्व कप विजेता देश को जूल्स रिमे ट्रॉफी प्रदान की जाती थी और 1970 में प्रतियोगिता के लिए फीफा विश्व कप नामक एक नई ट्रॉफी शुरू की गई। दरअसल शुरुआती वर्षों में फुटबॉल विश्व कप की ट्रॉफी का नामकरण फ्रांस के जाने माने फुटबॉल प्रशासक और फीफा के तीसरे अध्यक्ष जूल्स रिमे के नाम पर हुआ था जो न केवल फीफा के 33 वर्ष तक अध्यक्ष रहे, बल्कि 1919 से 1942 तक उन्होंने फ्रेंच फुटबॉल संघ के अध्यक्ष का दायित्व भी निभाया। 1950 में भारत, स्कॉटलैंड और तुर्की ने प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया और 13 टीमों के बीच विश्व कप खिताब के लिए संघर्ष में एक बार फिर बाज़ी

लेखक सीनियर कमेंटेटर हैं। ईमेल: shivendra68@gmail.com

मारी उरुग्वे ने। 1930 में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराया था तो 1950 में उसने मेजबान ब्राजील को हराकर दूसरी बार विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 1930 से 2022 तक, फीफा विश्व कप के 92 वर्ष के इतिहास में यूरोप और लैटिन अमेरीकी टीमों का ही दबदबा रहा है। 1994, 1998, 2006 और 2018 में क्वार्टर फाइनल खेलने वाली सभी टीमें या तो यूरोप से थी अथवा लैटिन अमेरीका से। और अब तक खेले गए 22 विश्व कप के फाइनल में हर बार, इन दोनों महाद्वीपों की टीमों के बीच ही खिताबी मुकाबला हुआ है।

क़तर फीफा विश्व कप

पिछले वर्ष क़तर में आयोजित हुआ फीफा विश्व कप, कई मायनों में अनोखा साबित हुआ था, जहां फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में हराकर तीसरा विश्व खिताब हासिल किया। परम्परागत तौर पर फीफा विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन जून-जुलाई के महीने में किया जाता था, परन्तु क़तर के मौसम और खास तौर पर गर्मी को ध्यान में रखते हुए टूर्नामेंट को वर्ष के आखिर में आयोजित करने का फैसला लिया गया।

प्रीक्वार्टर फाइनल मुकाबले 3 से 7 दिसंबर तक खेले गए, जहाँ ग्रुप ए की शीर्ष टीम नीदरलैंड ने सयुंक्त राज्य अमेरीका को, अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को, 2018 की विश्व चैंपियन फ्रांस ने पोलैंड को और इंग्लैंड ने सेनेगल को हराकर अंतिम आठ में जगह पक्की की। अन्य मुकाबलों में क्रोएशिया ने जापान को, ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को, मोरक्को ने स्पेन को और पुर्तगाल ने स्विटजरलैंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। खास बात ये कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जगह टीम में शामिल किए गए युवा खिलाड़ी गोंकालो रामोस ने प्रीक्वार्टर फाइनल में शानदार हैट्रिक जमाकर विश्व कप के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवा दिया। 9 और 10 दिसम्बर को खेले गए क्वार्टर फाइनल्स, कुछ टीमों के लिए खुशी, तो कुछ के लिए गम का मौका साबित हुए। 2018 के विश्व कप में तीसरे स्थान पर रही लूका मोड्रिच की क्रोएशियाई टीम ने, खिताब की दावेदार मांगी जा रही ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। पेनल्टी शूटआउट तक खिचे एक अन्य क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 4-3 से पराजित किया। फ्रांस ने परम्परागत प्रतिद्वंदी इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

रोमांचक फाइनल

22वें फीफा विश्व कप का फाइनल, मेजबान क़तर के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 18 दिसम्बर को ऐतिहासिक लुजैल स्टेडियम पर खेला गया। फ्रांस की टीम 1998 और 2018 की विजेता थी और उनके पास केलियन एमबाजे जैसा सुपरस्टार मौजूद था, तो दूसरी ओर 1978 और 1986 की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, फुटबॉल इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल लियोनेल मेसी की नुमाइंदगी में बेहद मज़बूत नज़र आ रही थी। अंततः मुकाबला पेनल्टी शूट आउट तक पहुँचा जहां अर्जेंटीना ने 4-2 से जीत दर्ज करके, 36 साल बाद, विश्व फुटबॉल का सिरमौर बनने का गौरव हासिल किया। केलियन एम्बापे फ्रांस को तीसरा खिताब जरूर नहीं जिता सके, लेकिन अपने शानदार और दर्शनीय खेल से उन्होंने करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों का दिल जरूर जीत लिया।

विश्व कप में खेलना कितना कठिन होता है इसका अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 बार की चैंपियन इटली की टीम क़तर के लिए क्वालीफाई भी नहीं कर पायी थी। वहीं वेल्स की टीम 58 साल बाद विश्व कप में खेलों की पात्रता हासिल कर सकी थी।

क़तर विश्व कप में यूँ तो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय फुटबॉल टीम मौजूद नहीं थी लेकिन देश और दुनिया में हजारों-लाखों भारतीय फुटबॉल प्रेमी, फीफा विश्व कप में खेल रही टीमों के साथ अपना जुड़ाव अलग-अलग माध्यम से व्यक्त करते नज़र आये। फीफा विश्व कप जैसे महाआयोजन की कामयाबी में परदे के पीछे काम करने वाली तकनीकी टीम की भी अहम भूमिका थी। दरअसल यह पहला विश्व कप टूर्नामेंट था जिसमें पूरा नेटवर्क 5जी सपोर्ट पर आधारित था। 5जी के बृहद जाल को फैलाने, दुनिया के कोने-कोने से क़तर पहुँचे 250 इंजीनियर्स में से लगभग 160 भारतीय शामिल थे।

वहीं मुकाबलों के दौरान भारतीय दर्शक, फुटबॉल के रोमांचक अंदाज का आनंद लेते देखें गए। यह सब बाते विश्व रूप से किसी न किसी रूप में भारतीय जुड़ाव की ओर संकेत देती है। 1950-60 के दशक में भारतीय टीम का अंतराष्ट्रीय मुकाबलों में प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। 1950 के विश्व रूप में भारतीय टीम को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी। बाद के वर्षों में किसी न किसी वजह से टीम के रैंकिंग में गिरावट आई। हालांकि देश में पेशेवर फुटबॉल को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है और इसी क्रम में आई लीग तथा आई एस एल का आयोजन नियमित रूप से हो रहा है। इस प्रतियोगिताओं में भारतीय युवाओं के साथ विदेशी खिलाड़ी भी खेलते नज़र आते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में घोषित राष्ट्रीय युवा नीति में भी खेलों का पर्याप्त बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है।

फुटबॉल और भारत

दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय खेलों में शामिल फुटबॉल भारत में लोकप्रियता के पायदान पर हमेशा ही पहले 3-4 स्थान पर रहा है। भारत, दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां फुटबॉल की शुरुआत 19 वी शताब्दी में ही हो चुकी थी। यह लगभग वही समय था, जब यूरोप में और विशेष तौर पर इंग्लैंड में शेफिल्ड एफ सी, नरिंघम फोरेस्ट और स्टोक सिर्य एप.सी. जैसे प्रसिद्ध क्लब अस्तित्व

में आ चुके थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश सैनिकों ने मनोरंजन के लिए फुटबॉल को अपनी पसंदीदा गतिविधि शामिल किया था और धीरे-धीरे यह खेल, देश में हजारों लाखों प्रशंसकों का चहेता बन गया। 27 अगस्त 1869 को कोलकाता में जन्मे नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी को भारतीय फुटबॉल का जनक कहा जाता है, जिनके प्रयासों से 1877 में ब्याएज़ क्लब के नाम से देश के पहले संगठित फुटबॉल क्लब की शुरुआत हुई। 1884 में नागेंद्र ने कोलकाता में ही वेलिंगटन क्लब की स्थापना की और 1887 में उन्हीं की देख रेख में सवोबाज़ार क्लब अस्तिव में आया। भारत में पहले ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट के तौर पर माने जाने वाले ट्रेड्स कप (Trades Cup) में भी 1889 में सवाबाज़ार क्लब में भाग लिया और तीन साल बाद, 1892 में ईस्ट सरे रेजीमेंट टीक को 2-1 से हराकर न केवल ट्रेड्स कप का खिताब जीता, बल्कि किसी ब्रिटिश टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी हासिल करने वाली पहली टीम बनी, जिसमें सभी खिलाड़ी भारतीय थे। 1893 नागेंद्र सर्वाधिकारी ने इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी आई. एफ. ए के गठन में भी अहम भूमिका निभाई। 1888 में दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में गिने जाने वाले ड्यूरंड कप की शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है कि ड्यूरंट कप के विजेता को तीन ट्रॉफीज़ प्रदान की जाती है, जिसमें शिमला कप और ड्यूरंड कप रोलिंग ट्रॉफी है। तीसरी ट्रॉफी है प्रेसीडेंट्स कप, जो सर्वप्रथम देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान की गई थी और यह ट्रॉफी, ड्यूरंड कप की विजेता टीम को हमेशा के लिए दी जाती है। 1889 में ही भारत के दिग्गज फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना हुई। पूर्वी भारत की तरह दक्षिण भारत में भी फुटबॉल के चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। 20 फरवरी, 1899 को केरल के त्रिशूर में दक्षिण भारत के पहले फुटबॉल क्लब आर.बी. फर्ग्युसन एफ. सी. की स्थापना हुई, जिसे यंग मेंस एफ. सी. के नाम से भी जाना जाता था। 1911 में मोहन बागान ने आई.एफ.ए.शील्ड जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनने का गौरव हासिल किया। 1924 में जाने माने फुटबॉलर गोष्ठा पाल के नेतृत्व में भारतीय फुटबॉल टीम ने पहले विदेशी दौरे के तौर पर श्रीलंका में मुकाबले खेले। 1937 में शिमला में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना हुई, जिसकी देखरेख में आज भी भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

27 अगस्त 1869 को कोलकाता में जन्मे नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी को भारतीय फुटबॉल का जनक कहा जाता है, जिनके प्रयासों से 1877 में ब्याएज़ क्लब के नाम से देश के पहले संगठित फुटबॉल क्लब की शुरुआत हुई।

1940 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने ड्यूरंड कप के फाइनल में रॉयल वारविक शायर रेजीमेंट को 2-1 से हराया और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी। इस जीत को भारतीय फुटबॉल इतिहास के एक निर्णायक मोड़ के तौर पर जाना गया। 1948 में लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम ने भाग लिया और फ्रांस से 1-2 की हार के साथ ही टीम का अभियान जल्दी ही खत्म हो गया। ये अलग बात है कि नंगे पैर मुकाबलों में उतरने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के खेल की खासी तारिफ हुई। दो साल बाद, यानी 1950 में भारतीय टीम को ब्राजील में आयोजित विश्व कप में भाग लेने का निमंत्रण मिला, पर कुछ कारणों से टीम वहां नहीं पहुँच सकी। 1950 में ही सैयद अब्दुल रहीम ने भारतीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षक का दायित्व संभाला, जिसे उन्होंने 1963 में अपनी मृत्यु तक निभाया। उनकी देख रेख में भारत ने 1951 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। नेवाइल डिसूजा ओलंपिक्स में हैट्रिक जमाने वाले पहले एशियाई फुटबॉलर बने और 4 गोल करके टूर्नामेंट के ज्वाइंट टाप स्कोर रहे। 1964 में भारतीय फुटबॉल टीम मर्डेका कप में उपविजेता बनी तथा, 1955, 1966 और 1970 में उसे, मर्डेका कप में तीसरा स्थान हासिल हुआ। 1970 के बैंकाक एशियाई में सैयद नईमुद्दीन के नेतृत्व में भारत, कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहा। 1982 में नौवें एशियाई खेल भारत में आयोजित हुए और साथ ही नेहरू कप के रूप में एक नए अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। 2007, 2009 और 2012 में भारतीय युवा टीम ने नेहरू कप खिताब जीतकर फुटबॉल इतिहास में सुनहरे पन्ने जोड़ दिए। इसी दौरान देश में पेशेवर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग, 2007 में आई लीग और 2014 में इंडियन, सुपर लीग यानी आईएसएल फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई। हाल के वर्षों में बाइचुंग भूटिया और सुनील देवी जैसे खिलाड़ी, भारतीय युवा फुटबॉल कौशल की तस्वीर बन कर उभरे हैं और अपने करिश्माई खेल से उन्होंने हजारों युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया है।

राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे में खेल

2022 में जारी राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे में युवा विकास के लिए 10 वर्षीय विजन की परिकल्पना की गई है, जिसमें एक बार फिर खेल, प्राथमिकता सूची में शामिल है। देश में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में 'खेलो इंडिया' जैसी राष्ट्रीय योजना की शुरुआत हुई है जिससे युवाओं को नियमित रूप से फुटबॉल जैसे खेल से जुड़ने और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है। हमारे देश के युवा फुटबॉल खिलाड़ी भी एक दिन, फीफा विश्व कप में खेलने की तमन्ना रखते हैं, पर सच्चाई यही है कि विश्व कप तक पहुँचने का रास्ता लंबा और काफी कठिन है। उसके बावजूद अगर ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, जीवट और कौशल के संयोजना से प्रयास किए जाएँ तो शायद कुछ भी असंभव नहीं है। विश्व कप फुटबॉल में खेलने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में मोरक्को जैसी टीम के हर खिलाड़ी को याद किया जा सकता है, जिन्होंने क़तर में 20 नवंबर से 18 दिसम्बर तक 22 वे फीफा विश्व रूप को अपने कालजई प्रदर्शन से यादगार बना दिया। एशियाई फुटबॉल रैंकिंग में भारतीय टीम फिलहाल 19 वें पायदान पर मौजूद है। कड़ी मेहनत, प्रतिभाओं की सही पहचान एवं प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधाएं देने की नीति, भारतीय फुटबॉल को अपना गौरव वापस दिलाने और अंतत: फीफा विश्व रूप में खेलने की पात्रता हासिल करने में निर्णायक साबित हो सकती है। ■

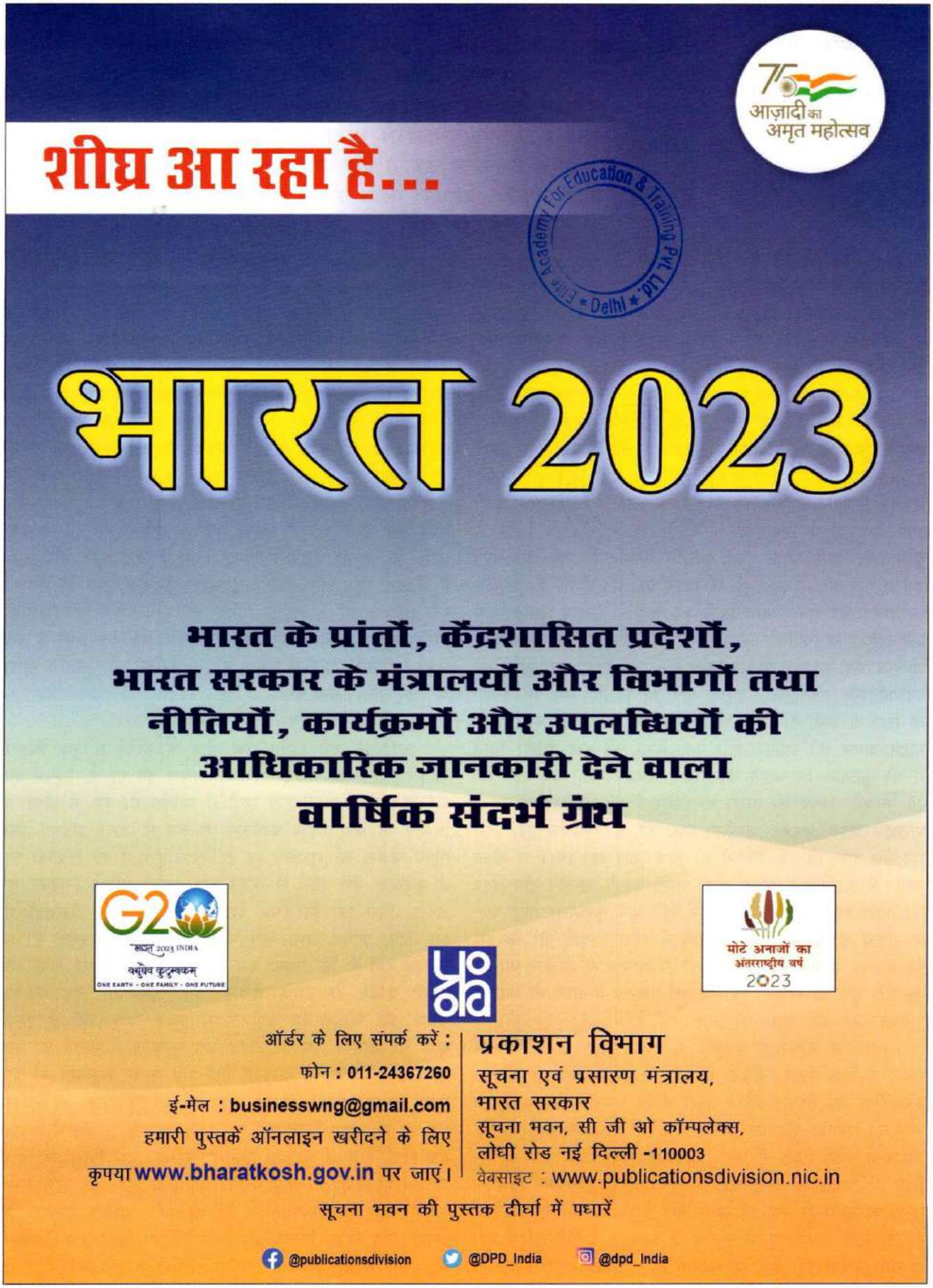

शीघ्र आ रहा है...
आज़ादी का अमृत महोत्सव
भारत 2023
भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE
मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023
ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें
@publicationsdivision
@DPD_India
@dpd_india

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

डिजिटल अर्थव्यवस्था का नया स्वरूप

बालेंदु शर्मा दाधीच

भारत डिजिटल तकनीकों के विभिन्न अनुप्रयोगों के चमत्कारी विकास और विस्तार के दौर से गुजर रहा है जिसे अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड की शक्ति से मज़बूती मिली है। ऐसे अनुप्रयोगों के एक बड़े भाग का श्रेय युवाओं को दिया जा सकता है जो न केवल डिजिटल खपत बल्कि डिजिटल नवाचार और विकास को भी प्रेरित कर रहे हैं। वे प्रौद्योगिकी के भविष्य को परिभाषित कर रहे हैं। हालांकि यह एक विश्वव्यापी घटना है लेकिन भारत के मामले में भी यह उतना ही सत्य है जहां आज 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है।

1980 और 2000 के बीच पैदा हुए लोगों को 'मिलेनियल्स' कहा जाता है और यह सर्वविदित है कि इस युवा आबादी का प्रौद्योगिकी के साथ बेहद जुड़ाव हैं। तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में पले-बढ़े होने के कारण उन्हें अक्सर 'डिजिटल नेटिव' कहा जाता है और प्रौद्योगिकी के साथ यह संबंध उनकी लगभग दूसरी प्रकृति जैसा है। वे स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, डिजिटल वियरेबल्स, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट शब्दावली से घिरे हुए परिवेश में बड़े हुए हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि डिजिटल तकनीक उनके जीवन का एक स्वाभाविक भाग है और वे इसका उपयोग अति सुगमता से करते हैं। यह वह उम्र है जब लोग अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं और इसलिए हम इन युवाओं द्वारा नए नवाचारों का सृजन होते हुए देखते हैं क्योंकि वे उन चीजों की परिकल्पना कर सकते हैं जिनमें प्रौद्योगिकी एक सहज भाग होती है।

परिणामस्वरूप कुछ युवाजन संभवतः अपने संचार के तरीकों में प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं। फोन कॉल, ईमेल और आमने-सामने बातचीत की जगह टेक्स्टिंग और ट्वीटिंग द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जुड़े रहना कायदा बन गया है। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण लग सकता है पर मिलेनियल्स ने स्वयं को उसके अनुसार ढालने के साथ-साथ लचीला रुख अपना लिया है। जिस तरह से मिलेनियल्स अपने जीवन जीते हैं वह भी अलग है। वे अपने माता-पिता की पीढ़ी के विपरीत अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन हासिल करने पर काफी जोर देते हैं। वित्तीय स्थिरता के अलावा वे अपने कैरियर में पूर्णता और लगन भी चाहते हैं। नतीजतन वे उद्देश्य और प्रेरणा की भावना से प्रेरित होते हैं।

भारतीय युवाओं की सफलता

युवाओं की महत्वाकांक्षाएं, आदतें, काम के तरीके, कौशल, अभिलाषाएं और क्षमताएं ये सभी आज प्रौद्योगिकी जगत पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। 35 वर्ष से कम आयु के महत्वाकांक्षी लोगों द्वारा अभूतपूर्व संख्या में इंटरनेट-युग की कंपनियों की स्थापना की गयी है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में भारतीय युवा कई प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों में शीर्ष पदों पर काबिज हो गए हैं।

लेखक डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विशेषज्ञ हैं। ईमेल: balendu@gmail.com

"यह दशक भारत का टेकेड है। युवाओं ने हैकॉथॉन्स के माध्यम अभूतपूर्व तेजी से से काम करते हुए देश के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया"

प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात' से
30 अक्टूबर 2022

इस महीने 23 आईआईटी अपने नवाचारों और अनुसंधान परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक साथ आए

आईआईटी भुवनेश्वर की टीम ने एक ऐसा पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है जिसका उपयोग दूर-दराज के इलाकों में तय समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं के जीवन बचाने के लिए किया जा सकता है

आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर ने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित 5जी टेस्टबेड को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है

भारत और अन्य जगहों पर स्टार्टअप क्रांति को ज्यादातर उसी पीढ़ी ने ही बढ़ावा दिया है जो न केवल नए विचारों के प्रति खुला दिमाग रखती है बल्कि कड़ी मेहनत करने और सफलता हासिल करने के लिए जोखिम उठाने को तैयार है। हाल ही में मीडिया में एक खबर आई थी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्नातकों की बढ़ती तादाद ने सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने या अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए प्लेसमेंट प्रक्रिया से बाहर होने का विकल्प चुना है। कई लोग कॉरपोरेट्स द्वारा पेश किए जाने वाले मोटे सैलरी पैकेज को ठुकराने और स्टार्टअप्स में नौकरी करने को तैयार हैं ताकि वे एक या दो साल के भीतर स्टार्टअप की दुनिया में खुद को उतारने के लिए तैयार हो सकें। उनमें से कुछ आईआईटी में डेफर्ड प्लेसमेंट सुविधा(बाद में प्लेसमेंट में बैठने की सुविधा) का विकल्प भी चुनते हैं ताकि वे उच्च अध्ययन कर सकें या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। आईआईटी उन्हें डेफर्ड प्लेसमेंट विकल्प का लाभ उठाने के बाद 2 साल के भीतर एक बार प्लेसमेंट राउंड में शामिल होने का मौका देते हैं।

ऐसा आज के युवा की सोच है। युवाओं की मानसिकता में बदलाव को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत वर्तमान में +274 बिलियन के संयुक्त मूल्यांकन के साथ 81 यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दावा करता है। इसके अलावा, 500 अमेरिकी यूनिकॉर्न के संस्थापकों में से 90 व्यक्तियों का जन्म भारत में हुआ था। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप हैं जिनका मूल्यांकन एक अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपये है। यदि भारत की स्टार्टअप क्रांति अभी भी आपको आश्चर्यचकित नहीं करती है, तो इस तथ्य पर विचार करें कि जेप्टो की स्थापना करने वाले 19 वर्षीय कैवल्य वोहरा 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे कम उम्र के स्टार्टअप संस्थापक हैं। दस साल पहले इतनी ही संपत्ति वाले सबसे कम उम्र के स्टार्टअप संस्थापक की उम्र 37 वर्ष थी।

युवाओं की मानसिकता में बदलाव को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत वर्तमान में +274 बिलियन के संयुक्त मूल्यांकन के साथ 81 यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दावा करता है। इसके अलावा, 500 अमेरिकी यूनिकॉर्न के संस्थापकों में से 90 व्यक्तियों का जन्म भारत में हुआ था।

मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में 19 साल की उम्र में हार्वर्ड में फेसबुक की शुरुआत की थी और गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और 25 साल के सर्गेई ब्रिन ने की थी जब वे कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएच.डी. छात्र थे। एलोन मस्क भी 20-22 वर्ष के थे जब उन्होंने 1995 में अपना पहला उद्यम स्थापित किया था। आज प्रौद्योगिकी उद्योग में ये कुछ नामचीन लोग हैं जिनके नाम शक्ति और धन-संपत्ति के पर्याय हैं। भारत में भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 या 30 की उम्र में कुछ महानतम भारतीय स्टार्टअप की स्थापना की थी। इनमें से कुछ उद्यम हैं जोमाटो, फ्लिपकार्ट, इनमोबी, रेडबस ,जेरोधा, अपस्टॉक्स, ओयोरूम्स, लेंसकार्ट, योअरस्टोरी, ओला कैब्स, फिजिक्सवाला और मामाअर्थ जो आज घरेलू नाम बन गए हैं। 2022 की 'फोर्ब्स 30 अंडर 30' सूची को देख कर भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में आने वाली अप्रत्याशित तेजी को आसानी से समझा जा सकता है। सूची में शामिल होने वाले 22 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत 61 प्रविष्टियों के साथ सूची में शीर्ष पर है।

कंटेंट क्रिएशन के अग्रणी

कंटेंट क्रिएशन यानी किसी विषय पर सामग्री तैयार करना एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां आप बड़ी संख्या में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देख सकते हैं। फोर्ब्स ने हाल ही में भारत के शीर्ष 100 डिजिटल सामग्री स्टार्टअप की एक सूची जारी की थी और आश्चर्यजनक रूप से इस सूची में युवाओं का दबदबा है। इनमें से कई आज प्रसिद्ध हैं जिनमें कैरीमिनाती, निखिल शर्मा, अभिषेक उपमन्यु, कोमल पांडे, अनमोल जायसवाल, निर्मल पिल्लई, श्लोक श्रीवास्तव, कृतिका खुराना, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, कुशा कपिला, प्राजक्ता कोली और तन्मय भट शामिल हैं। इनमें से कुछ अपने आप में संस्थान बन गए हैं जबकि कई ने रोज़गार के अवसर सृजित किए हैं और बड़ी संख्या में युवाओं को अपना खुद का कुछ शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म हैं जिनका आज के युवा खुद को अभिव्यक्त करने, स्तरीय कंटेंट देने और धन अर्जित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

युवाओं के बीच भारी रुचि के कारण शॉर्ट-फॉर्म वीडियो के उपयोग में आई तेजी से रचनाकार (क्रियेटर) अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। परिणामस्वरूप, भारत में कम से कम 8 करोड़ क्रिएटर्स और नॉलेज प्रोफेशनल हैं। यह एक विकसित होता हुआ क्षेत्र है और इनमें से केवल एक छोटा अंश यानी लगभग 1.5 लाख लोग अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से मुद्रीकृत करने में सफल रहे हैं। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक

इन पेशेवर कंटेंट क्रिएटर्स के पास विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुँच और जुड़ाव के आधार पर 15,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये प्रति माह तक कमाने की क्षमता है। भारत में 8 करोड़ क्रिएटर्स में वीडियो स्ट्रीमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स और वास्तविक उत्पाद बनाने वाले जैसे लोगों का एक विविध समूह शामिल है जो सभी अपने विशिष्ट स्थान के इर्दगिर्द समुदायों की सृजना कर रहे हैं। ये अवसरों के बिल्कुल नए क्षेत्र हैं जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान युवाओं के लिए खुले हैं।

युवाओं द्वारा गिग नौकरियों को अपनाने में तेजी आ रही है क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के अवसरों की खोज के लिए खुली सोच रखते हैं। ऐसी कुछ नौकरियों में ऑनलाइन ट्यूटर, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, टेली कॉलर, फील्ड सेल्स वर्कर, डिजिटल मार्केटर्स, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, एसईओ विशेषज्ञ, ब्रांड प्रमोटर, वीडियो एडिटर आदि शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पारंपरिक प्रोग्रामिंग नौकरियों के अलावा गेमिंग और गेम डेवलपमेंट जैसे नए अवसर भी आज के युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) उद्योग सहित आईटी सेवा उद्योग में युवा कार्यबल का वर्चस्व है। इन क्षेत्रों में न केवल महानगरों और बड़े शहरों में बल्कि पुणे और इंदौर जैसे टियर-2 शहरों में भी अवसर उपलब्ध हैं।

द गिग जॉब्स (गैर स्थायी नौकरियां)

जब भारत में युवाओं द्वारा खोजे जा रही नए युग की नौकरियों की बात आती है तो गिग अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। गिग कर्मचारी स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, ठेका फर्म के कर्मचारी, कॉल पर काम के लिए उपलब्ध कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी हैं। गिग कर्मचारी कंपनी के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑन-डिमांड कंपनियों के साथ औपचारिक समझौते करते हैं। यह क्षेत्र भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं। गिग अर्थव्यवस्था देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि एक शोध ने सुझाया है 16 से 18 वर्ष के बीच के युवाओं में गिग नौकरियों में रुचि 750 प्रतिशत बढ़ गई है।

नीति आयोग का कहना है कि साल 2020-2021 में गिग अर्थव्यवस्था में अनुमानित 77 लाख लोग कार्यरत थे। ऐसा पूर्वानुमान है कि यह गिग कार्यबल 2029-2030 तक बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएगा। वर्तमान में 47 प्रतिशत गिग कार्य को मध्यम कौशल, 22 प्रतिशत को उच्च कौशल और 31 प्रतिशत को निम्न कौशल कार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस रुख से यह पता चलता है कि मध्यम कौशल में श्रमिकों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है और कम कौशल और उच्च कौशल में बढ़ रही है। यह संभावना है कि 2030 में जहां मध्यम कौशल कार्य मौजूद रहेगा वहीं अन्य कौशल सेटों के साथ गिग कार्य और अधिक प्रमुखता हासिल कर लेगा।

युवाओं द्वारा गिग नौकरियों को अपनाने में तेजी आ रही है क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के अवसरों की खोज के लिए खुली सोच रखते हैं। ऐसी कुछ नौकरियों में ऑनलाइन ट्यूटर, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, टेली कॉलर, फील्ड सेल्स वर्कर, डिजिटल मार्केटर्स, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, एसईओ विशेषज्ञ, ब्रांड प्रमोटर, वीडियो एडिटर आदि शामिल हैं। ये सुविधाजनक हैं, अपने घरों में आराम से किए जा सकते हैं और कोई भी इन नौकरियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने दैनिक दिनचर्या के साथ उपयुक्त तालमेल बिठा सकता है। इंटरनेट ने नौकरी के बाजार में क्रांति ला दी है क्योंकि इस तरह के कई अवसरों का लाभ भौगोलिक सीमाओं के आड़े आये बगैर उठाया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है आज का युवा इंटरनेट सहित विभिन्न प्रकार की डिजिटल तकनीकों के उपयोग में सहज है।

मांग सृजन और विज्ञान शिक्षा

युवा आबादी अवसरों के सृजन, उत्पादों के निर्माण और सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही यह डिजिटल उत्पादों और सेवाओं की खपत को भी बढ़ा रही है जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। एक विशाल युवा आबादी वाला देश डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के लिए एक घरेलू बाजार का दावा कर सकता है। यह कल्पना करना आसान है कि भारत में डिजिटल सामग्री और संबंधित सेवाओं के लिए 1 अरब से अधिक दूरसंचार ग्राहक कितनी मांग पैदा कर रहे होंगे। इसमें यह भी जोड़िए कि एक भारतीय युवा स्मार्टफोन ग्राहक की खपत की अवधि प्रतिदिन औसत 4.7 घंटे है जैसा कि एक शोध संस्थान ने बताया है। ये 2021 के आंकड़े हैं जबकि 2020 में औसत खपत अवधि 4.5 घंटे और 2019 में 3.7 घंटे थी। कहने की जरूरत नहीं कि इसका ज्यादातर समय संचार, मनोरंजन और सोशल नेटवर्किंग में बीतता है। यह प्रौद्योगिकी उद्योग में रुझानों को बढ़ावा दे रहा है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

देश और इसके युवाओं के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है और यह सुखद अनुभूति है कि भारतीय छात्र विज्ञान और इंजीनियरिंग की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हर साल 15 लाख से अधिक प्रौद्योगिकी स्नातक तैयार करते हैं। सरकार कुशल प्रौद्योगिकी कार्यबल का एक बड़ा आधार बनाने के लिए छात्रों के बीच एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को लोकप्रिय बनाना जारी रख रही है जिससे देश में और विदेशों में आजीविका अर्जित करने के अवसर मिल सकते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्राप्त होगी।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के दशक को प्रौद्योगिकी का दशक (द टेकेड) के रूप में पहचान दी है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए देश अपने युवाओं पर भरोसा कर रहा है। प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक, प्रौद्योगिकी में कौशल प्राप्त और प्रौद्योगिकी के प्रति आत्मविश्वास से भरी युवा आबादी उस जनसांख्यिकीय लाभांश को सुनिश्चित करेगी जिसकी भारत को तलाश है ताकि दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में वह अपना स्थान हासिल कर सके। ■

UPSC सिविल सेवा

Learn from the best
& walk with confidence
Your success partner to excel in
UPSC Civil Services exam

Legendary Indian Cricketer &
Former Captain
SOURAV GANGULY

भारत का भूगोल 8वाँ संस्करण

(मानचित्रों में)

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

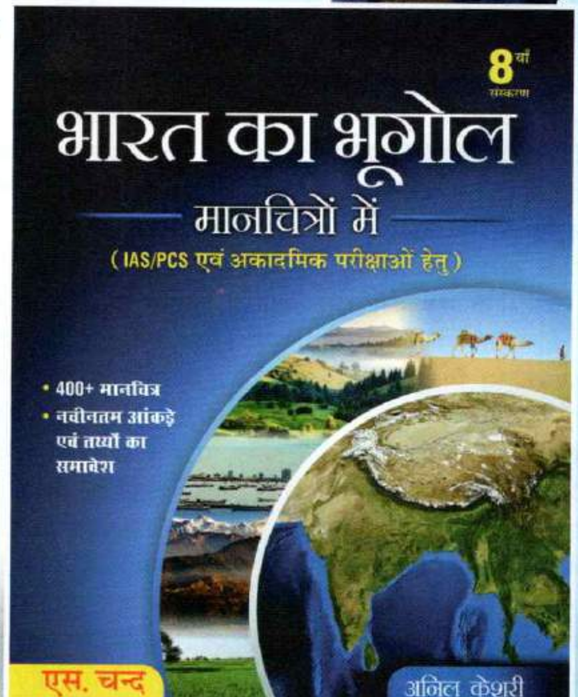

ISBN: 9789355016898 | PRICE: ₹450
SIZE: 8"x10.5" | PAGES: 320

पुस्तक की विशेषताएँ

- 400+ मानचित्र
- नवीनतम आंकड़ों का समावेश
- सरकारी आंकड़ों से लिए गए तथ्य
- मानचित्र एवं उससे संबधित तथ्य एक साथ
- प्रसंगों में नवीनतम् संकल्पनाएँ

विषय सूची

1. सामान्य परिचय 2. भौतिक 3. जल-शक्ति, संकट एवं प्रबंधन 4. पर्यावरण 5. संसाधन 6. कृषि 7. उद्योग 8. परिवहन 9. जनसंख्या 10. नगरीकरण 11. प्राकृतिक आपदाऐं एवं आपद प्रबंधन 12. पर्यटन एवं धर्म 13. राजनीतिक 14. संदर्भ ग्रंथ और स्रोत

लेखक परिचय

अनिल केशरी वर्तमान में 'दृष्टि IAS' दिल्ली में फैकल्टी के तौर पर कार्यरत हैं एवं विगत् 20 वर्षों से IAS/PCS की परीक्षा की तैयारी कराने में संलग्न रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हजारों अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है।

S.CHAND PUBLISHING
S. CHAND PUBLISHING
A Division of S Chand And Company Ltd.
(ISO 9001 Certified Company)
Customer Care (toll free) No.: 1800-103-1926

https://twitter.com/SchandHigher
https://www.facebook.com/Schandpublishinghighereducation/
https://www.instagram.com/schandhigher/

https://www.linkedin.com/company/schand-higher
+91-7291975264
info@schandpublishing.com
www.schandpublishing.com

Buy books online @ www.schandpublishing.com amazon Flipkart

YH-2194/2023

भारत के युवा सितारे
(प्रौद्योगिकी, स्पेसटेक और खेल)

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

"समूची दुनिया भारत के युवाओं को उम्मीद की निगाह से देख रही है। क्योंकि आप देश के विकास वाहक हैं और भारत, दुनिया का विकास वाहक है। यह आप सभी के लिए बहुत बड़ा सम्मान और ज़िम्मेदारी है।"

-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

हाल के समय में, दुनिया ने युवाओं को एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी और परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंट के रूप में देखना शुरू किया है। इनके पास नीति को आकार देने, बाजारों को प्रभावित करने और सामाजिक संरचनाओं की पुनर्कल्पना करने की शक्ति है। युवा सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने में सबसे आगे हैं और आत्मनिर्भर भारत के व्यापक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करते हैं।[1]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई[2] को व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अमरीका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने सन फ्रांसिस्को में पिचाई को पुरस्कार सौंपते हुए कहा- उनकी 'प्रेरणादायक यात्रा वैश्विक नवाचार में भारतीय प्रतिभा के योगदान की पुष्टि करती है।' 9 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदर पिचाई से मुलाकात की और नवाचार, प्रौद्योगिकी और अन्य

Image Source : Freepik

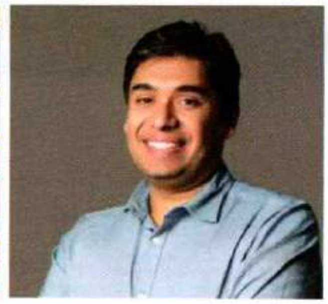

विषयों पर चर्चा की।[3]

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को भी व्यापार और उद्योगों में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्यदूत डॉ. टीवी नागेंद्र प्रसाद से पुरस्कार प्राप्त किया। सत्य नडेला ने पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह और अधिक हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करने के लिए पूरे भारत में लोगों के साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं।[4]

नवीन तिवारी ने 2019 में ग्लांस की स्थापना की। ग्लांस एक उपभोक्ता इंटरनेट कंपनी है जिसने ग्लांस और रोपोसो सहित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए हैं। सिंगापुर में मुख्यालय वाली ग्लांस, इनमोबी समूह की एक असमेकित सहायक कंपनी है और इसे जियो प्लेटफॉर्म्स, गूगल और मिथरिल कैपिटल द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ग्लांस एशिया के सबसे बड़े लॉक स्क्रीन प्लेटफॉर्म में से एक है। 400 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन अब ग्लांस के अगली पीढ़ी के इंटरनेट से जुड़े हैं। ग्लांस का एआई-पॉवर्ड पर्सनलाइज़ेशन, उपभोक्ताओं को उनकी पसंद की सामग्री, उत्पादों और सेवाओं का आनंद लेने में सक्षम बनाता है, जो सभी उनके स्मार्टफोन की लॉक स्क्रीन पर सहज और आकर्षक प्रारूप में पहुँचाए जाते हैं। लॉक स्क्रीन पर इंटरनेट की खपत के तरीके को फिर से परिभाषित करने, ऐप्स को खोजने और डाउनलोड करने की आवश्यकता को दूर करने का श्रेय ग्लांस को दिया जा सकता है।

निखिल कामथ और नितिन कामथ ने फुल-सर्विस डिस्काउंट ब्रोकरेज व्यवसाय बनाया है, जिसने पिछले साल 4,300 करोड़ रुपये के राजस्व पर 1,800 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था। केनरा बैंक के एक मध्यवर्गीय कर्मचारी के बेटे, कामथ बंधु, एक दशक से भी कम समय में, शून्य बाहरी पूंजी के साथ 'जेरोधा' का निर्माण करने के बाद, भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक ताकत के रूप में उभरे हैं।

रवि रामू पटेल ने एक अनुवादक रोबोट विकसित किया जो 14 विभिन्न भाषाओं का अनुवाद कर सकता है। उन्होंने ऐसा आईआईओटी-आधारित होम ऑटोमेशन मॉडल के लिए एक जिला-स्तरीय प्रतियोगिता जीतने के बाद किया, जो वॉयस कमांड के साथ स्मार्ट घरेलू उपकरणों को सिंक करता है। एक पूल क्लीनर के बेटे, रवि ने सलाम बॉम्बे फाउंडेशन कार्यक्रम में जाने के बाद पहली बार आठवीं कक्षा में रोबोटिक्स के बारे में सीखा। रवि ने कार्डबोर्ड और एलईडी मॉडल हाउस से लेकर कई स्मार्टफोन-आधारित गेम तक कई तरह की परियोजनाओं पर स्वतंत्र रूप से काम किया। उनका सबसे हालिया आविष्कार 'टोरो' नाम का रोबोट अनुवादक है। इस अनुवादक की अनूठी विशेषता यह है कि आपको अनुवाद के लिए भाषा का चयन नहीं करना पड़ता है - यह आपकी आवाज से लक्षित भाषा को पहचान सकता है और उसमें प्रतिक्रिया दे सकता है।[5]

स्पेसटेक

23 जून 2017 को, भारत ने केवल 64 ग्राम वज़न के दुनिया के सबसे हल्के उपग्रह 'कलामसैट' को प्रक्षेपित करके वैश्विक अंतरिक्ष रिकॉर्ड बनाया। इसे पेशेवर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने डिजाइन और विकसित नहीं किया था, बल्कि तमिलनाडु के एक 18 वर्षीय छात्र और उसकी टीम ने डिजाइन और विकसित किया था। इस छोटे उपग्रह का नाम ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। इसे साउंडिंग रॉकेट द्वारा उड़ाया गया था और दोपहर 3 बजे (आईएसटी) के आसपास अंतरिक्ष एजेंसी की वॉलॉप द्वीप सुविधा से इसका प्रक्षेपण किया गया था। महज 64 ग्राम वजन के इस उपग्रह को रिफत शारूक ने छह अन्य साथियों के साथ डिजाइन किया था। यह उपग्रह, स्मार्टफोन की तुलना में हल्का है और प्रबलित कार्बन फाइबर पॉलिमर से बना है, जो उड़ान के बाद अंतरिक्ष के सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण वातावरण में 12 मिनट तक संचालित होता है।

1 जुलाई 2022 को, 17 वर्षीय स्नेहदीप कुमार को अमरीका की सरकार द्वारा केंटकी के राष्ट्रमंडल के सौजन्य से केंटकी कर्नल से

सम्मानित किया गया। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले कुछेक भारतीयों में से हैं, जो मोहम्मद अली, बॉब डायलन, एंसेल एडम्स, जॉर्ज क्लूनी और जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश जैसे आइकन को दिया गया है। 2021 में, इस महत्वाकांक्षी युवा खगोल वैज्ञानिक ने नेबुला अंतरिक्ष संगठन की स्थापना की, जो छात्रों द्वारा संचालित अपनी तरह की पहल है।

26 वर्षीय उद्यमी, निखिथा सी, ने भारत और विदेश में अंतरिक्ष शिक्षा और आउटरीच के क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने की दृष्टि से बेहद लोकप्रिय गैर-सरकारी संगठन सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एसएसईआरडी) - और स्टार्टअप-जेनेक्सस्पेस की सह-स्थापना की है। निखिथा ने बैंगलोर में एलायंस यूनिवर्सिटी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री की पढ़ाई के दौरान 2016 में अपने कॉलेज में एक अंतरिक्ष क्लब शुरू किया, जिसमें छात्रों को मॉडल रॉकेटरी जैसे विषय पढ़ाए गए।

खेल

राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।[6] भारतीय दल ने खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करते हुए लॉन बाउल्स, जूडो और एथलेटिक्स जैसे खेलों में अप्रत्याशित पदक जीते। भारत ने कुश्ती में सबसे अधिक छह स्वर्ण सहित 12 पदक और भारोत्तोलन में 10 पदक जीते। पुरुषों की हॉकी टीम ने रजत पदक जीता, जो इस संस्करण में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आखिरी पदक था। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 30 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किए।[7]

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरथ कमल अचंता[8] (जुलाई, 1982 में जन्मे) को प्रदान किया गया। वह देश के सबसे उत्कृष्ट टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में तीन स्वर्ण पदक (व्यक्तिगत, मिक्स डबल्स और टीम) और एक रजत पदक जीता है। इससे पहले, उन्होंने 2018 के एशियाई खेलों, में दो कांस्य पदक (मिक्स डबल्स और टीम) और एक स्वर्ण पदक (टीम), एक रजत पदक (मिक्स डबल्स) और एक कांस्य पदक (व्यक्तिगत) जीता था।

इस साल ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों और डैफलंपिक्स खेलों के 25 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार मिला है।[9]

सुश्री सीमा पुनिया (जुलाई, 1983 में जन्मी) को एथलेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। उन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों, में रजत पदक और 2019 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। उन्हें दिए गए अन्य पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार और खेलों में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और साथ ही तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार शामिल हैं।

नीरज चोपड़ा ने महज 23 वर्ष की आयु में टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों के भाला फेंक में भारत का पहला एथलेटिक्स गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए 87.58 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो दिया। इसके साथ, वह एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं और बीजिंग 2008 में स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं। नीरज ने इस शानदार प्रदर्शन के साथ 2012 में लंदन खेलों में जीते गए छह पदकों की संख्या को पछाड़ते हुए देश की टोक्यो ओलंपिक में पहले की तुलना में प्राप्त पदकों की संख्या को सर्वाधिक कर दिया। भारतीय किशोर रमेशबाबू प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे के विख्यात विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया। मैच 23 फरवरी 2022 को एयरथिंग्स मास्टर्स (2022 में आयोजित होने वाले मेल्टवाटर चैंपियंस चैस टूर इवेंट्स) के हिस्से

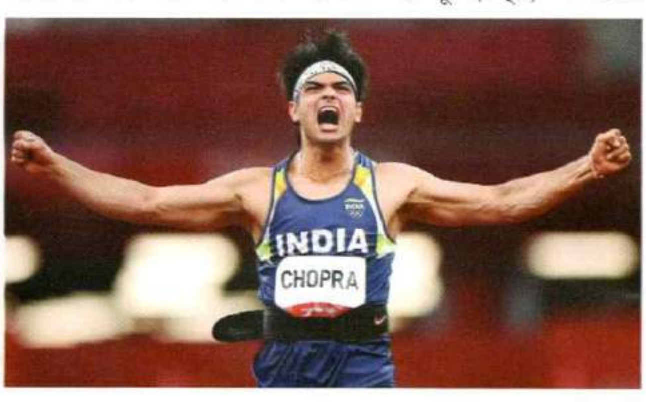

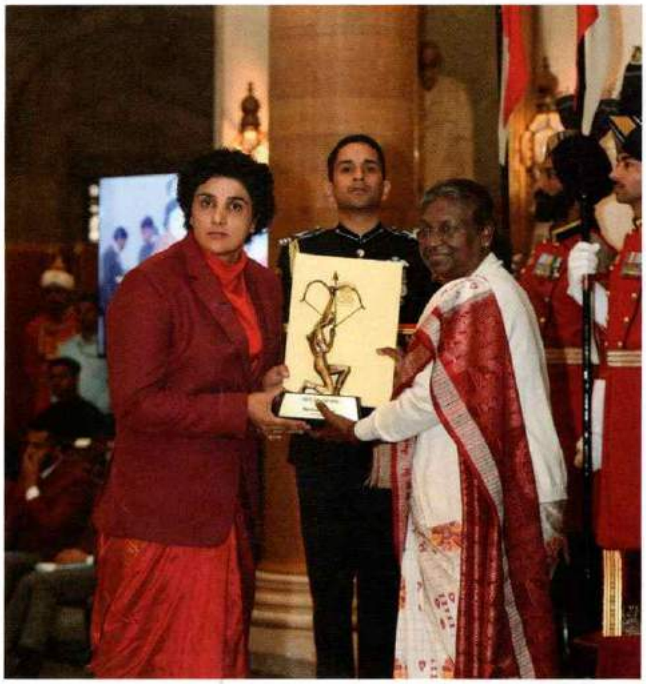

के रूप में एक ऑनलाइन सेटिंग में आयोजित किया गया था। 16 साल की छोटी उम्र में, आर प्रज्ञानानंदा ने 39 चालों में यह कारनामा किया। विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा के अलावा वह मैग्नस कार्लसन को हराने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं।[11] प्रज्ञानानंदा के पास तीन विश्व युवा खिताब हैं: 2013 में यू8, 2015 में यू10 और 2019 में यू18; इस 13 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने अपराजित 8.5/10 अंकों के के साथ एक्स्ट्राकॉन चैस ओपन जीता। अप्रैल 2021 में, उन्होंने पोलगर चैलेंज जीता और चैंपियंस शतरंज टूर में अगले चरण के लिए क्वालीफाई किया। उन्होंने 2022 अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (एफआईडीई) ओलंपियाड में भारतीय टीम के साथ कांस्य पदक जीता, 2767 की प्रदर्शन रेटिंग के लिए तीसरे बोर्ड पर 6.5/9 स्कोर किया। बाद में 2022 में, उन्होंने एशियाई कॉन्टीनेंटल चैस चैंपियनशिप जीती। ■

(पसूका अनुसंधान इकाई)

एंडनोट्स

1. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/may/doc20225553401.pdf
2. https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1792640
3. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1884948
4. https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1792640
5. https://amritmahotsav.nic.in/stories-of-change-detail.htm?323
6. https://newsonair.com/2022/08/09/curtains-come-down-on-22nd-commonwealth-games-india-finish-fourth-overall-with-61-medals-including-22-gold/
7. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1880090
8. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/file/SportsandadventureawarosQ2022GFXF.pdf
9. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1880090
10. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1743629
11. https://ddnews.gov.in/sports/16-yrs-old-indian-chess-player-r-praggnanandhaa-stuns-world-no1-magnus-carlsen

संदर्भ

1. PIB Press Release on Year End Review: Department of Sports dated 20 December 2022.
2. PIB Press Release on Year End Review 2022: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) dated 15 December 2022.
3. PIB Press Release on Ministry of CivilAviation notifies liberalised Drone Rules, 2021 dated 26August 2021.
4. PIB Press Release on PM inaugurates India"s biggest Drone Festival-Bharat Drone Mahotsav 2022 dated 27 May 2022.
5. PIB Press Release on The Government has prepared a new draft of National Youth Policy dated 19 July 2022.
6. PIB Press Release on Introduction of National Youth Policy-2014 dated 09 January 2014.
7. PIB Press Release on Year End Review: Department of YouthAffairs dated 28 December 2021.
8. PIB Press Release on Ministry of YouthAffairs & Sports announces National SportsAwarosQ 2022 dated 14 November 2022.
9. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jan/doc202212810601.pdf
10. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/nov/doc20221125136001.

हमारी पत्रिकाएं

योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती

में विज्ञापन देने हेतु

संपर्क करें :
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक
प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-24367453
ई मेल : pdjucir@gmail.com

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

जानकारी और संवाद का प्रभावी मंच

आकाश त्रिपाठी

विश्व का विशालतम लोकतन्त्र भारत सर्वोदय और अंत्योदय के जीवन-मूल्यों से सम्पन्न है। 'सर्वोदय' शब्द 'सर्व' और 'उदय' शब्दों से बना है जिसका तात्पर्य है हर नागरिक का उत्थान/कल्याण। 'अंत्योदय' का अर्थ विकास और कल्याण की बाट जोह रहे सबसे विपन्न-वंचित व्यक्ति का उत्थान है। ये जीवन-मूल्य किसी एक संगठन, कंपनी, व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा हासिल नहीं किए जा सकते। ये मूल्य तो तभी हासिल हो सकते हैं जब देश का हर जन सभी के कल्याण के लिए एकजुट हो कर कार्य करे। सर्वोदय और अंत्योदय शासन-प्रशासन में सभी की सहभागिता से ही हासिल हो सकते हैं और यही लोकतन्त्र का आधार है।

सहभागी शासन-प्रशासन नागरिकों के जीवन से जुड़े और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों से सम्बन्धित नीति-निर्धारण, क्रियान्वयन और प्रशासन में उन सभी नागरिकों की भागीदारी तथा उनके विचारों को स्थान दिए जाने पर आधारित है। जिले से राष्ट्रीय स्तर तक नागरिकों की भागीदारी से उनकी प्रतिक्रिया अर्थात् फीडबैक मिलती है जिनके आधार पर सरकारें समुचित कार्य-योजनाओं को बनाने और उनमें आवश्यक सुधार कर पाने में समर्थ होती हैं। जन-भागीदारी होने से सरकार ज्यादा कारगर तरीके से काम कर पाती है और बेहतर फैसले ले पाती है; दूसरी ओर, समाज में सरकारी कामकाज की व्यापक जानकारी होने से नागरिकों को भी फायदा होता है।

भारत विश्व में विशालतम युवा जनसंख्या वाले देशों में एक है। देश की करीब 66 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है। युवा जनसंख्या की इस शक्ति की देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में प्रभावी भूमिका है। जन-प्रतिभागी शासन-प्रशासन में युवाओं को शामिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जो युवा जनसंख्या का एक अंश हैं, कल वे देश का शत-प्रतिशत भविष्य होंगे। नागरिक क्षमता के निर्माण और समाज के दीर्घकालीन स्थायित्व के लिए जन-प्रतिभागी शासन-प्रशासन में युवाओं को शामिल करना आवश्यक है। युवाओं के विविध कौशल-सम्पन्न और आत्म-विश्वासी होने से देश में बहुमुखी संपन्नता आएगी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि "मात्र सुशासन पर्याप्त नहीं है। इसे जन-मुखी और सक्रिय होना होगा। सुशासन का उद्देश्य आम जन को विकास-प्रक्रिया के केन्द्र में रखना है।"

आम जन को विकास-प्रक्रिया के केन्द्र में रखने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई 2014 को myGov प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह भारत सरकार का आम जन को शामिल करने का ऐसा मंच (प्लेटफॉर्म) है जो अनेक सरकारी संगठनों और मंत्रालयों से जुड़ा है। यह प्लेटफॉर्म नीति-निर्धारण प्रक्रिया में नागरिकों को भागीदार बनाता है और आम जन के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय हासिल करता है। myGov ने आम लोगों तक पहुँचने के लिए टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया ही है, इसके साथ ही इसने ऐसे साधन भी विकसित किए हैं जिनके जरिए डिजिटल युग की सुविधाओं से कम परिचित लोग भी इस सहभागी मंच का हिस्सा बन सकते हैं। myGov ने लोगों की हिस्सेदारी के अनेक मंच अपनाए हैं, जैसे- चर्चा, कार्य, मत-संग्रह, सर्वेक्षण, ब्लॉग, वार्ताएं, शपथ, क्विज़ और ऑन-ग्राउंड गतिविधियां। इंटरनेट, मोबाइल एप्स, आईवीआरएस, एसएमएस और आउटबाउंड डायलिंग जैसी प्रौद्योगिक तकनीकों के नए-नए तरीकों के इस्तेमाल से उक्त मंचों का उपयोग किया जा सकता है ताकि जन-जन तक पहुँच कर उनकी राय जानी जा सके। myGov ने 19 राज्यों को भी सहभागी बनाया है और इस समय इस प्लेटफॉर्म के 2.9 करोड़ 'साथी' हैं। युवा जन myGov के जनता तक पहुँचाने के कार्यक्रम का आधार हैं। myGov निम्न तरीकों से जन भागीदारी सुनिश्चित करता है-

जानकारियाँ पहुँचाना: नीतियों के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा सर्वाधिक वंचित लाभार्थी तक नहीं पहुँच पाना है। कारगर तरीके से जानकारियाँ नहीं पहुँचा पाने से अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती और लोग भ्रमित हो जाते हैं। myGov लाभार्थियों तक पहुँच पाने और नागरिकों को एक ही स्थान पर किसी योजना या नीति से जुड़ी जानकारियां जुटा पाने में मदद करता है। नई-नई जानकारियों को कारगर तरीके से लोगों को पहुँचाने के अलावा myGov लोगों की जागरुकता भी बढ़ाता है और नीतियों-कार्यक्रमों के प्रति उनका सहयोग बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर, कोविड-हेल्पडेस्क ने सही जानकारियाँ

लेखक myGov के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। ईमेल: ceo@mygov.in

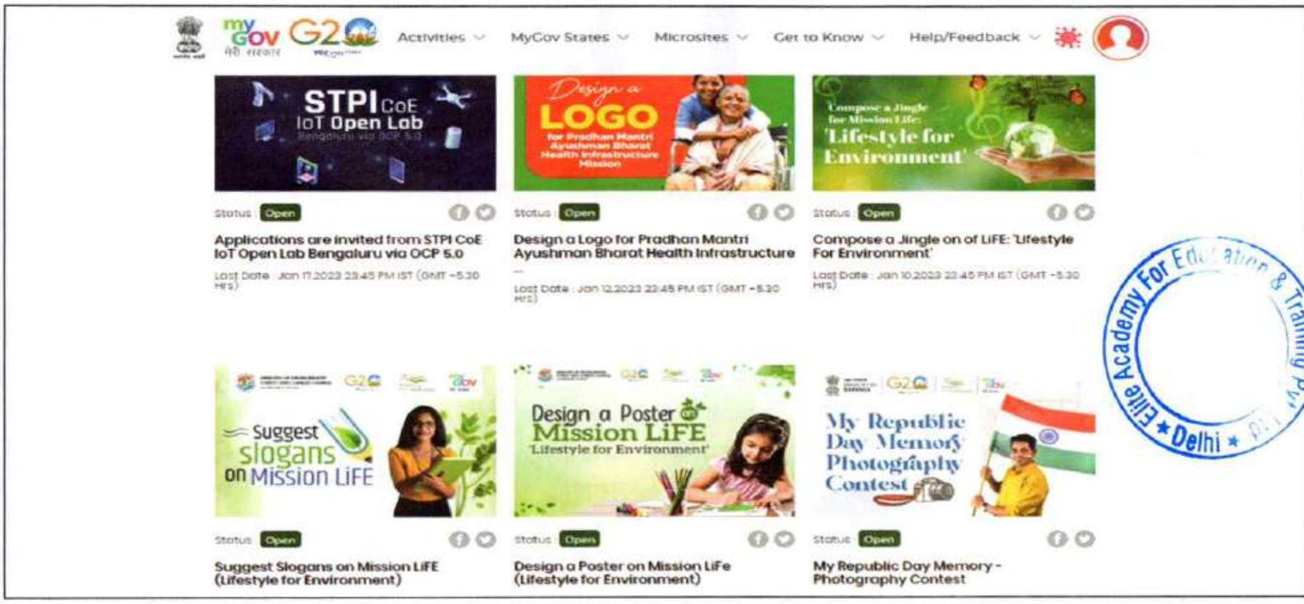

हासिल करने, ताजा-तरीन विवरणों के साथ उन्हें अद्यतन करने और टीकाकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड करने में लाखों-करोड़ों नागरिकों की मदद की।

दु-तरफा संवाद: भागीदार शासन-प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष जनता और प्रशासन के बीच संवाद बनाए रखना है। myGov का मंच सोशल मीडिया और नए-नए प्लेटफॉर्मों के जरिए ऐसा संवाद संभव बनाता है। लोगों से संवाद संभव होने से सरकार का कामकाज ज्यादा प्रभावी होता है और उसके निर्णय बेहतर हो पाते हैं। केन्द्रीय बजट, राष्ट्रीय युवा नीति तथा शिक्षा नीति के मसौदों और ऐसे ही अनेक नीतिगत मुद्दों पर नागरिकों से सुझाव हासिल करने से ये नीतियाँ ज्यादा समग्र और पुख्ता बन पाती हैं। आपसी संवाद और चर्चा से नागरिक और सरकार एक-दूसरे के करीब आते हैं। सरकार द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न निर्णयों और नीतियों के लिए ऐसे संवाद से फीडबैक मिल जाता है।

पारदर्शिता: पहले सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा पुरस्कारों के लिए चयन आदि की प्रक्रियाएँ जटिल होती थीं और इनके बारे में लोगों को पता भी नहीं चल पाता था। myGov प्लेटफॉर्म पर ऐसी छन-प्रक्रियाओं के लिए एक ही स्थान पर तत्काल डिजिटल तरीके से नामांकन भरे जा सकते हैं। इससे नागरिकों का शासन-प्रशासन प्रणालियों के प्रति विश्वास मज़बूत होता है। पारदर्शिता से जवाबदेही भी बढ़ती है और सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में जनता को पता भी चलता है। सरकारी आंकड़े और जानकारियों को जन-सुलभ बनाने से नागरिकों का सशक्तीकरण होता है जिससे नागरिकों और सरकार के बीच आपसी विश्वास मज़बूत होता है।

तथ्यों की जांच: दुष्प्रचार और सूचनाओं के घटाटोप के वर्तमान दौर में, myGov नागरिकों को सही तथ्य और सरकारी घोषणाओं के बारे में सही बातें समझने में मदद करता है। लाखों-करोड़ों लोग तुरंत और आसानी से ये जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। वास्तव में,झूठी खबरों के तेजी से फैलने की आशंका रहती है जिनका समाज और व्यक्ति पर खतरनाक असर पड़ सकता है।

सहयोग में वृद्धि: myGov नागरिकों तथा सरकार और नागरिकों के बीच आपसी सहयोग का मंच प्रदान करता है। समान सोच वाले नागरिक अपने विचारों पर 'चर्चा' कर सकते हैं। myGov सार्थक परिवर्तन लाने के इच्छुक लोगों को नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है। चर्चाओं,ब्लॉग तथा अन्य गतिविधियों के जरिए नागरिक अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे लीक से हट कर नए-नए रचनात्मक विचार सामने आते हैं।

हमारे युवाओं ने सहभागी शासन-प्रशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न अभियानों-कार्यक्रमों से जुड़ी टैगलाइन, जिंगल और स्लोगन सुझाने और लोगो डिजाइन करने के साथ-साथ, युवा जन सहभागी शासन-प्रशासन को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं के प्रयासों की वजह से myGov जन-जन तक पहुँच रहा है और महत्वपूर्ण जानकारी आम लोगों तक पहुँचा रहा है।

युवाओं को अपने आदर्शों को समझना चाहिए और राष्ट्र-निर्माण में अपनी भूमिका को जानना चाहिए। जानकारियों का आदान-प्रदान, क्षमता-निर्माण, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, परिवर्तनों का वाहक बनना और आम जन के उत्थान के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिल कर काम करना - ये सभी युवा जनों के अनिवार्य कर्त्तव्य हैं। हमारे युवाओं के कौशल, ज्ञान और क्षमताओं से देश आगे बढ़ेगा। सार्वजनिक निकायों के काम-काज में पारदर्शिता से मज़बूत और समावेशी सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण होगा। सहभागी शासन- प्रशासन न्यायपूर्ण तथा टिकाऊ विकास की कुंजी है।

युवाओं की आकांक्षाओं पर ध्यान देना उनकी भागीदारी और ऊर्जा के जरिए स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। myGov सभी युवाओं का आह्वान करता है कि वे अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा को समर्पित करते हुए सहभागी शासन-प्रशासन तथा राष्ट्र-निर्माण के लिए कार्य करें।

हमारे पूर्व-राष्ट्रपति भारतरत्न ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था, "मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं के तेजस्वी मानस इस धरती के सबसे शक्तिशाली संसाधन हैं। मेरा विश्वास है कि युवा शक्ति अगर सुनिर्देशित और सुनियंत्रित हो तो मानव-जाति के सम्पूर्ण बदलाव वाले परिवर्तन ला सकेगी, मानवता के समक्ष चुनौतियों का सामना कर सकेगी और शांति तथा समृद्धि ला सकेगी।'' ■

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

'ऑनलाइन सुरक्षित रहें' अभियान और 'जी-20 डीआईए' का शुभारंभ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की जी-20 की अध्यक्षता के अवसर पर 28 दिसंबर 2022 को एक कार्यक्रम में 'ऑनलाइन सुरक्षित रहें' अभियान और 'जी-20 डिजिटल नवोन्मेष गठबंधन-डिजिटल इनोवेशन एलायंस (डीआईए)' का शुभारंभ किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यसमूह-डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (डीईडब्ल्यूजी) के लिये केंद्रिक मंत्रालय है। उसने पिछली अध्यक्षताओं के दौरान अनेक कार्य समूहों और मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान एमईआईटीवाई 'ऑनलाइन सुरक्षित रहें' अभियान और डीईडब्ल्यूजी के अंतर्गत डीआईए कार्यक्रम के साथ ही प्राथमिकता के जिन तीन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा वे हैं - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना-डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल विकास।

'ऑनलाइन सुरक्षित रहें' अभियान

'ऑनलाइन सुरक्षित रहें' अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के व्यापक प्रसार और डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए नागरिकों के बीच इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षित रहने के प्रति जागरुकता बढ़ाना है। भारत में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि और तेजी से बदलते प्रौद्योगिकीय परिदृश्य ने विशेष तरह की चुनौतियां पैदा की हैं। इस अभियान के तहत खास तौर से बच्चों, छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, शिक्षकों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों समेत सभी उम्र वर्गों के नागरिकों को इंटरनेट के जोखिम और इससे निपटने के उपायों के प्रति जागरूक बनाया जायेगा।

इस अभियान में जागरुकता फैलाने के लिये इंफोग्राफिक्स, कार्टून कथाओं, पहेलियों और लघु वीडियो जैसी बहुभाषी प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जायेगा। इस काम में माईगॉव वेबसाइट (https://www.mygov.in/staysafeonline) और प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी सहारा लिया जायेगा। इसके अलावा 'ऑनलाइन सुरक्षित रहें' के संदेश के प्रसार के लिये प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से समूचे साल प्रचार और प्रसार की गतिविधियां संचालित की जायेंगी।

जी-20 डीआईए

जी-20 डीआईए का मकसद इस समूह के देशों और आमंत्रित गैर-सदस्य राष्ट्रों की स्टार्टअप संस्थाओं में विकसित नवोन्मेषी और प्रभावशाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों की पहचान कर उन्हें मान्यता देना और उनका अभिग्रहण है। इन डिजिटल प्रौद्योगिकियों को कृषि-प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी, शिक्षा-प्रौद्योगिकी, वित्त-प्रौद्योगिकी, सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना और चक्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानवता की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार होना चाहिये। इन छह क्षेत्रों में समर्थित स्टार्टअप उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप डिजिटल विभाजन घटेगा तथा संवहनीय और समावेशी प्रौद्योगिकीय-सामाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

नवोन्मेषकों, उद्यमियों, स्टार्टअप संस्थाओं, निगमों, निवेशकों, परामर्शदाताओं और अन्य हितधारकों की भागीदारी से उस प्लेटफॉर्म की तेजी से स्वीकार्यता बनेगी जिसे भारत जी-20 डीआईए के जरिये सामने लाना चाहता है। जी-20 डीआईए शिखर सम्मेलन इस समूह के सदस्य देशों और आमंत्रित गैर-सदस्य राष्ट्रों से नवोन्मेष तंत्र के महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच पर लायेगा। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल विभाजन पाटने और विश्व अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने वाले छह क्षेत्रों में अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों का सृजन करने वाली स्टार्टअप संस्थाओं की पहचान कर उनकी सहायता करना है।

कार्यक्रम में जी-20 शेरपा अमिताभ कांत, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी, दूतावासों और महावाणिज्य दूतावासों के प्रतिनिधि तथा सरकार, उद्योग संगठनों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, स्टार्टअप संस्थाओं और सिविल सोसायटी संगठनों के आमंत्रित अतिथि मौजूद थे। ■

स्रोतः पसूका

मिसाल बनते विभिन्न राज्यों के स्पोर्ट्स आयकन

संजय श्रीवास्तव

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

वैसे देश के हर राज्य के खेलों की अपनी खासियतें हैं, अपने तरीके हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर खेल के अपने आयकन हैं, जिन्होंने अपने तरीके के खेलों को पहचान दी। क्रिकेट आमतौर पर सारे देश में खेला जाता है। पंजाब, झारखंड, यूपी, ओडिशा और दक्षिण के कुछ हिस्से हॉकी की मज़बूत बेल्ट हैं। नार्थ ईस्ट ने महिला खेलों में बॉक्सिंग से लेकर भारोत्तोलन और तीरंदाजी में पहनान बनाई तो पंजाब, हरियाणा और दक्षिणी भारत दमदार एथलीट पैदा करते रहे हैं।

खेलों में भारत का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धीरे-धीरे बेहतर हो रहा है। हमारे कुछ खेल सितारों ने विश्वव्यापी तौर पर पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। कहना चाहिए सुविधाओं और तकनीक के साथ भारतीय खेलों का रंग भी गहरा हो रहा है। एक खास खेल-संस्कृति विकसित हो रही है। कुछ खास खेल आयकन अब पेरेंट्स के साथ बच्चों को खेल मैदान या कोर्ट में जाने और उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करने लगे हैं।

वैसे देश के हर राज्य के खेलों की अपनी खासियतें हैं, अपने तरीके हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर खेल के अपने आयकन हैं, जिन्होंने अपने तरीके के खेलों को पहचान दी। क्रिकेट आमतौर पर सारे देश में खेला जाता है। पंजाब, झारखंड, यूपी, ओडिशा और दक्षिण के कुछ हिस्से हॉकी की मज़बूत बेल्ट हैं। नार्थ ईस्ट ने महिला खेलों में बॉक्सिंग से लेकर भारोत्तोलन और तीरंदाजी में पहचान बनाई तो पंजाब, हरियाणा और दक्षिणी भारत दमदार एथलीट पैदा करते रहे हैं।

यकीनन अगर देश के दिग्गज खिलाड़ियों की बात करेंगे तो सबसे पहले दो नाम आएंगे जो आज़ादी के आसपास हमारे सबसे बड़े आयकन थे। यूपी के ध्यानचंद और पंजाब के मिल्खा सिंह। 60 के दशक के आखिर से मिल्खा यूरोप की तमाम दौड़ प्रतियोगिताओं में परचम लहराने लगे थे। उन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। मिल्खा ने खेल प्रशासन में भी गजब की छाप छोड़ी। उनकी कहानी एक ऐसे युवक की कहानी थी जो सबकुछ खोकर बंटवारे के बाद पाकिस्तान से पंजाब आया था। फिर उसने ऊंचाइयां छुईं। 91 साल की उम्र तक जीने वाले मिल्खा पर एक मूवी भी बनी 'भाग मिल्खा भाग', जो सुपरहिट रही।

पंजाब में और भी खेल सितारे हुए। हॉकी के तो एक से एक खिलाड़ी पंजाब ने दिए। हॉकी कप्तानों की श्रृंखला यहां से निकली, उसी में परगट सिंह, बलबीर सिंह और अजितपाल सिंह जैसे नाम आते हैं। मौजूदा नेशनल हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से हैं। कहा जाता है कि पंजाब के बच्चे जब आंखें खोलते हैं तो अपने आसपास हॉकी को ज्यादा देखते हैं। ओलंपिक रायफल शूटिंग में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले अभिनव बिंद्रा पंजाब के जीरकपुर से हैं, जिन्होंने जब बीजिंग में वर्ष 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो पूरे देश का सीना गर्व से फूल उठा था। हरभजन सिंह, योगराज सिंह और युवराज सिंह जैसे

लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। ईमेल: sanjayratan@gmail.com

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd ★ Delhi ★

क्रिकेट स्टार्स ने यहां से पहचान बनाई। अचूक स्पिनर बिशन सिंह बेदी का नाम भी कोई कैसे भूल सकता है। मदन लाल जैसा शानदार ऑलराउंडर पंजाब से निकला।

खूबसूरत हिमाचल लंबे समय से विंटर स्पोर्ट्स का केन्द्र रहा है। लेकिन वहां के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आयकन विजय कुमार हैं, जिन्होंने लंदन ओलंपिक में वर्ष 2012 में निशानेबाजी में रजत पदक जीता। विजय हिमाचल में पैदा हुए। हालांकि निशानेबाजी के दांवपेच उन्होंने सेना में जाने के बाद सीखे। उनकी लगन और मेहनत प्रेरणा देती है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले युवक खेलों के जरिए वो काम करता है जो सोचा भी नहीं गया।

वैसे निशानबाजी ऐसा खेल रहा है, जो एक समय तक ओलंपिक में 90 के दशक के बाद हमारे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरा। शुरुआत राजस्थान के रजवाड़े से आने वाले और सैन्य अधिकारी राज्यवर्द्धन राठौर ने वर्ष 2004 के बार्सिलोना ओलंपिक में रजत पदक जीतते हुए की। इसके बाद वह देश के केन्द्रीय मंत्री और अब भी राजनीति में सक्रिय हैं।

चाहे एशियाई खेल हों या फिर ओलंपिक या फिर कोई और खेल-हर जगह हरियाणा के जुझारू एथलीटों का दम नज़र आता है। खेल के क्षेत्र में हरियाणा का मुकाबला करने वाला देश में कोई और राज्य नहीं। हर खेल में यहां के खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। देश की कुल आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी महज दो फीसदी है। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के 31 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह देश से टोक्यो पहुँचने वाले कुल खिलाड़ियों का 25 फीसदी हिस्सा है। ये ऐसा राज्य बन गया है जो एशियाई खेलों से लेकर ओलंपिक तक में पदकों और सफलता की गारंटी देता है। यकीनन इस राज्य में दो खिलाड़ी सबसे बड़े खेल आयकन हैं, ये हैं महान क्रिकेट कप्तान और ऑलराउंडर कपिलदेव और हरियाणा के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। कपिलदेव की अगुवाई में देश ने पहली बार 1983 का वर्ल्ड कप जीता । इसी जीत ने देश में क्रिकेट को ऐसा लोकप्रिय बनाया कि हर जगह बच्चे क्रिकेट खेलते दिखने लगे और क्रिकेटर बनने का सपना देखने लगे। इस राज्य ने देश को एक से एक क्रिकेटर दिए तो दिग्गज ओलंपियन पहलवान, एथलीट और बॉक्सर भी दिए। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैवलीन थ्रो में नया रिकॉर्ड रचते हुए स्वर्ण पदक जीता तो कुश्ती में इसी राज्य के रवि दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में ही जब भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य जीता तो उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी रही। टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में आए कुल पदकों में 50 फीसदी हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। अगर इससे 4 साल पहले लौटें तो रियो ओलंपिक में भारत को 2 पदक हासिल हुए, जिनमें से एक कांस्य पदक हरियाणा की पहलवानी साक्षी मलिक ने जीता। लंदन ओलंपिक्स में देश को 06 मेडल मिले थे, जिनमें 4 का संबंध हरियाणा से रहा। हालांकि सायना नेहवाल रहती जो हैदराबाद में हैं और प्रैक्टिस भी वहीं करती हैं लेकिन उनके माता-पिता हरियाणा से हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक कांस्य जीता और देश में बैडमिंटन के लिए नया उत्साह पैदा कर दिया। तो कुश्ती में योगेश्वर दत्त ने कांस्य और सुशील कुमार को रजत पदक मिला। शूटिंग में इसी ओलंपिक में कांस्य जीतने वाले गगन नारंग भी इसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले विजेंद्र कुमार तो अब पेशेवर बॉक्सर बनकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा रहे हैं।

यकीनन अगर देश के दिग्गज खिलाड़ियों की बात करेंगे तो सबसे पहले दो नाम आएंगे जो आज़ादी के आसपास हमारे सबसे बड़े आयकन थे। यूपी के ध्यानचंद और पंजाब के मिल्खा सिंह। 60 के दशक के आखिर से मिल्खा यूरोप की तमाम दौड़ प्रतियोगिताओं में परचम लहराने लगे थे।

महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद को तो देश कभी भूल ही नहीं सकता, जिन्होंने देश को तब गर्व से भर दिया था जब हम ब्रिटिश राज में थे। झांसी के रहने वाले ध्यानचंद की मौजूदगी में भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड हासिल किया। ध्यानचंद का खेल ऐसा था कि वो जीतीजागती किवंदती बन गए। उनकी

हॉकी ड्रिबलिंग को लेकर ना जाने कितनी ही कहानियां कही जाती हैं। किस तरह क्वीन एलिजाबेथ से लेकर हिटलर तक उनकी हॉकी के दीवाने हो गए थे। हिटलर ने तो उन्हें बड़ा ओहदा देकर अपने देश आने का न्योता दिया लेकिन देशभक्त ध्यानचंद ने विनम्रता से उनके आमंत्रण को ठुकराया। उनके नाम पर हम 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। जब ध्यानचंद ने आज़ादी से पहले 1928 के ओलंपिक में जाते हुए ब्रिटेन में उनकी टीम पर जबरदस्त तरीके से गोलों की बारिश करते हुए उन्हें हराया तो देश पर राज करने वाले ब्रिटिश हुक्मरानों के लिए ये एक भारतीय द्वारा खेल मैदान पर दिया गया बहुत बड़ा झटका था, जिसने उनके घमंड को चूर-चूर किया था।

उत्तर प्रदेश मुख्यतौर पर हॉकी का एक बड़ा गढ़ रहा है, हालांकि वो चमक इधर खो सी रही है, वैसे यह वही राज्य है जिसने ध्यानचंद के बाद अपनी ड्रिबलिंग से चमत्कृत कर देने वाला मोहम्मद शाहिद जैसा खिलाड़ी दिया। वह उस भारतीय टीम के सदस्य थे, जिसने आखिरी बार मास्को ओलंपिक में गोल्ड जीता था। भारतीय हॉकी टीम की समय-समय पर अगुवाई करने वाले दिग्गज हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू, जफर इकबाल, एमपी सिंह और जगबीर सिंह इसी प्रदेश की देन थे।

हिटलर ने तो उन्हें बड़े ओहदा देकर अपने देश आने का न्योता दिया लेकिन देशभक्त ध्यानचंद ने विनम्रता से उनके आमंत्रण को ठुकराया। उनके नाम पर हम 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। जब ध्यानचंद ने आज़ादी से पहले 1928 के ओलंपिक में जाते हुए ब्रिटेन में उनकी टीम पर जबरदस्त तरीके से गोलों की बारिश करते हुए उन्हें हराया तो देश पर राज करने वाले ब्रिटिश हुक्मरानों के लिए ये एक भारतीय द्वारा खेल मैदान पर दिया गया बहुत बड़ा झटका था, जिसने उनके घमंड को चूर-चूर किया था।

महाराष्ट्र के खेलों की बात करते हैं तो अक्सर उस बड़ी खेल हस्ती को भूल जाते हैं जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में देश को पहली बार कुश्ती का कांस्य पदक दिलाया था, वो केशुभाई जाधव थे। हालांकि जाधव को वो सम्मान और हक कभी नहीं मिला जो एक ओलंपिक पदक विजेता को मिलता है। वो हमेशा गुमनामी में रहे। बाद में एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। देश के ज्यादातर बड़े क्रिकेटर इसी राज्य से ज्यादा निकले, वो चाहे सुनील गावस्कर हों या अजीत वाडेकर या फिर दिलीप वेंगसरकर। सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर और गॉड कहा जाने वाला खिलाड़ी मुंबई की धरती पर जन्मा। उसने अपने खेल के बूते कम उम्र से लेकर रिटायर होने तक जितनी जीतगाथाएं लिखीं वो अलौकिक हैं। वह हमारे देश के सबसे बड़े क्रिकेट लीजेंड हैं।

महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात ने भी हमेशा से क्रिकेट की नर्सरी के तौर पर काम किया। यहां के रजवाड़ों ने क्रिकेट का संरक्षण किया। जब भारतीय टीम 30 के दशक में ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाली थी तो पटियाला के साथ गुजरात के ही रजवाड़ों ने आर्थिक तौर पर उसकी मदद की थी। वीनू मांकड़ जैसा शानदार ऑलराउंडर क्रिकेटर सौराष्ट्र की देन था, जिसकी बॉलिंग और बैटिंग से हमेशा प्रतिद्वंद्वी टीमें भयभीत रहती थीं। इसके बाद गुजरात से एक नहीं कई दिग्गज क्रिकेटर निकले जिसमें करसन घावरी से लेकर अंशुमान गायकवाड़ और किरण मोरे तक रहे। फिलहाल यहां के दो स्टार क्रिकेटर नेशनल टीम में हैं, जो हैं हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह।

कर्नाटक का नाम लेते ही कई महान क्रिकेटरों की तस्वीर सामने घूमती है। ये राज्य नहीं होता तो देश की क्रिकेट टीम कैसे इतनी ताकतवर बन पाती। यहां के शानदार क्रिकेटर 40 के दशक से ही भारतीय क्रिकेट टीम का अभिन्न अंग ही नहीं रहे बल्कि उन्होंने अपने खेल से लंबे समय तक देश के दिल पर राज भी किया। इस राज्य ने भी देश को शानदार क्रिकेट कप्तान दिए। भारतीय टीम के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ यहीं के हैं, वह भारतीय टीम के शानदार कप्तान तो थे ही, इसके अलावा गजब के बल्लेबाज थे इतने उम्दा कि गेंदबाज थक जाते थे लेकिन उनके डिफेंस की दीवार को

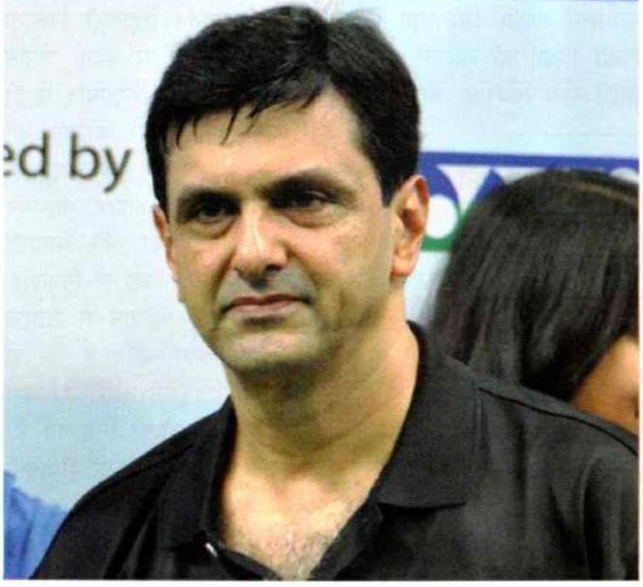

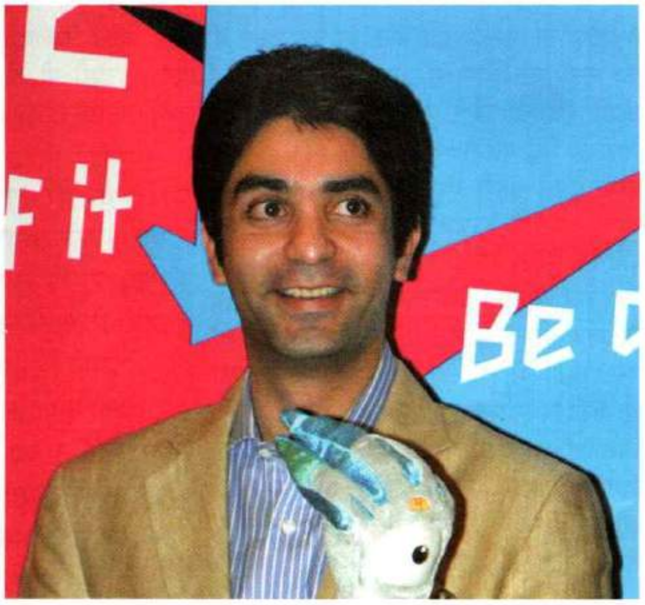

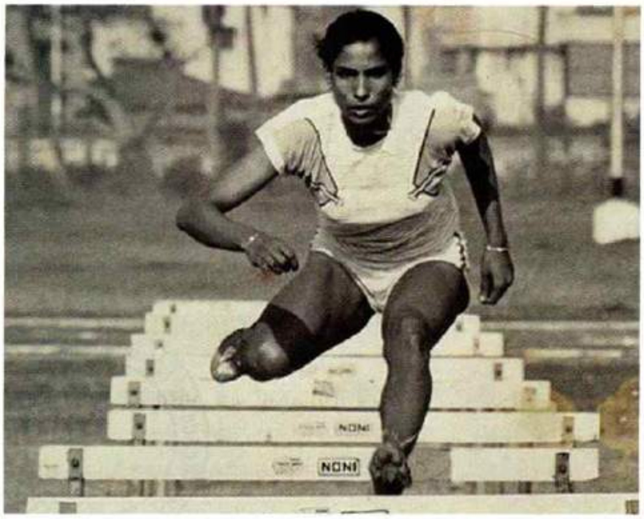

तोड़ नहीं पाते थे, इसीलिए उन्हें 'द वॉल' कहा गया। गुंडप्पा जैसा दाएँ हाथ की कलाई का जादूगर क्रिकेटर इसी राज्य से निकलकर क्रिकेट मैदान और किस्सों में छा गया। भारतीय स्पिन गेंदबाजी की गोल्डेन तिकड़ी में तीन क्रिकेटर थे - प्रसन्ना, चंद्रशेखर और बेदी। इसमें बेदी को छोड़कर बाकी दोनों कर्नाटक की मिट्टी से ही उठे। अनिल कुंबले, श्रीनाथ, वेंकटेश कुमार, रोजर बिन्नी, रोबिन उथप्पा यहीं से निकले।

बैडमिंटन के लीजेंड खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का समय जिसने देखा है, उसको मालूम है कि 70 के दशक के आखिर से 80 के दशक के बीच वह किस तरह दुनिया के सबसे बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए। जब वह ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर लौटे तो पूरे मुंबई ने जुलूस बनाकर उनकी शानदार आगवानी की। फिर ऐसा ही बेंगुलुरु में हुआ। अब वह यहां बैडमिंटन की एकेडमी चलाते हैं। टेनिस स्टार महेश भूपति और रोहन बोपन्ना इसी राज्य के स्टार खिलाड़ी हैं तो एथलेटिक्स में इसने वीमन पावर को साकार किया। अश्विनी नाचप्पा से लेकर रीथ अब्राहम तक। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन पंकज आडवाणी भी यहीं से हैं।

खूबसूरत समुद्र का किनारा, नारियल और मसालों की खेती, रबर के पेड़ और खूबसूरत नजारे वाला राज्य है केरल। ये ऐसा राज्य है, खेल के बारे में इस प्रांत का नाम आते ही जिस महान खिलाड़ी का नाम तुरंत जेहन में आता है तो वो हैं एशियन उड़नपरी पी टी ऊषा। देश के खेल जगत की सबसे बड़ी हस्तियों में एक। कहा जाता है कि महिलाओं को खेल में आने के लिए सबसे पहले जिस महिला एथलीट का असर रहा और जिसने वीमन पावर का जलवा इंडियन स्पोर्ट्स में दिखाया, वो ऊषा ही थीं। वह अब भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। जब वह 80 और 90 के दशक में ट्रैक पर दौड़ती थीं तो लोगों को हमेशा लगता था कि पदक पक्का है। वैसे ये केरल ही है जिसने विश्व स्तरीय महिला एथलीट देश को दिए। शाइनी विल्सन, बीनामोल, टिंकू लुक्का, अंजु बॉबी जार्ज, प्रीजा श्रीधरन के नाम उनमें सबसे आगे हैं। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान पीआर श्रीजेश इस हरे भरे और खूबसूरत प्रदेश से हैं, जिन्होंने देशभर के लोगों का दिल भी जीता है और युवाओं का अपना रोल मॉडल भी बनाया है।

केरल के पड़ोसी तमिलनाडु भी खेलों में बहुत गजब का रहा है। वर्ल्ड शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को ही देख लीजिए। वह जीनियस हैं, विनम्र हैं और दुनिया के शतरंज में उनकी बादशाहत चलती है। कम उम्र में उन्होंने चेस खेलना शुरू किया। हर भारतीय उन पर फख्र करता है। तमिलनाडु ऐसा राज्य है, जिसने टेनिस से लेकर मोटर रेसिंग तक गजब के खिलाड़ी दिए। बड़े कद वाले खिलाड़ी। टेनिस में रामनाथन कृष्णन तब दुनिया में अपनी टेनिस का जलवा दिखाया जब भारत में बहुत कम लोग इस खेल के बारे में जानते रहे होंगे। 80 और 90 के दशक में उनके बेटे रमेश कृष्णन दुनिया के बड़े टेनिस खिलाड़ियों में शुमार हुए। विजय अमृतराज एक बार नहीं बल्कि ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं में 04 बार क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे। रैकेट स्पोर्ट्स में तमिलनाडु ने वास्तव में दमदार खिलाड़ी दिए हैं। मास्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मेडल दिलाने वाले कप्तान वासुदेव भास्करन यहीं से ताल्लुक रखते हैं। दिग्गज क्रिकेटर आर वेंकटराघवन से लेकर एल शिवरामाकृष्णन यहीं से निकले तो धुआंधार बैट्समैन कृष्णामचारी श्रीकांत को कोई कैसे भूल सकता है। तमिलनाडु की क्रिकेट टीम हमेशा से देश की मज़बूत टीमों में रही है। मोटर रेसिंग में बड़ा नाम नारायण कार्तिकेयन की बड़ी फॉलोइंग है।

आंध्र प्रदेश में भी खेलों की समृद्ध परंपरा रही है। सिडनी में वर्ष 2000 के ओलंपिक में भारोत्तोलन की 69 किलो कैटेगरी में भारत को महिला वर्ग का पहला स्वर्ण दिलाने वाली करनम मल्लेश्वरी इसी राज्य से हैं। वैसे ये राज्य बैडमिंटन की नर्सरी कहा जाता है। हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन एकेडमी दुनिया में अनोखी है। पुलेला ने पहले जबरदस्त बैडमिंटन शटलर के तौर पर रंग जमाया। वह प्रकाश पादुकोण के बाद देश के दूसरे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन बने। वह असल मायने में ऐसे रोल मॉडल हैं, जिन्होंने पेप्सी, कोक या विज्ञापन करने से इसलिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये पेय युवाओं के ठीक नहीं। मोटा पैसा तक ठुकरा दिया, जो कम लोग कर पाते हैं। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद में बैडमिंटन एकेडमी खोली और यहां से कई विश्व चैंपियन खिलाड़ी निकाल दिखा दिया, वो वास्तव में लीजेंड हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली दोनों खिलाड़ी सायना नेहवाल और पीवी सिंधू हैदराबाद में ही रहती हैं और दोनों पुलेला की कोचिंग की देन हैं। वैसे ये राज्य एक से एक बैडमिंटन सितारों से भरा है। इसके अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमएल जयसिम्हा और मिताली राज जैसे जबरदस्त क्रिकेटर यहां से निकले।

वैसे आंध्र प्रदेश की पहचान से शतरंज भी जुड़ा है। ये भी कहा जाता है कि ये राज्य शतरंज की भी बेहतरीन नर्सरी है। यहां से शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी निकलते हैं। खासकर गुंटूर जिले में शतरंज किसी दीवानगी की तरह है। इस शहर ने कई विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी दिए जो बहुत कम उम्र में ग्रैंड

भारत के हर राज्य और हिस्से की खेलों की अपनी खासियतें रही हैं। हर राज्य ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को नई मिसाल दी। खेलों में आने की ललक दी। वैसे खेलों में रोल मॉडल का हमेशा महत्व रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं।

मास्टर बने। सानिया मिर्जा हैदराबाद से किस तरह दुनिया में डबल टेनिस की टॉप टेनिस प्लेयर बन गईं, ये किससे छिपा है। महिलाओं और लड़कियों के लिए वह एक बड़ी मिसाल हैं, जिन्होंने ये दिखाया कि लड़की होने के बाद भी वह ऐसे खेल में किस तरह चोटी पर पहुँच सकती हैं, जिसकी बहुत ज्यादा सुविधाएं इस देश में नहीं हैं। अब वह भी हैदराबाद में टेनिस एकेडमी चलाती हैं और देशभर की लड़कियां इसमें शामिल होना चाहती हैं।

बंगाल ऐसा राज्य है जहां फुटबॉल की जबरदस्त दीवानगी है। मोहन बागान, मोहम्मडन स्पोर्टिंग और ईस्ट बंगाल जैसे क्लब यहां हमेशा से फुटबॉल दीवानों के प्रिय रहे हैं। बंगाल ही नहीं बल्कि देशभर में फुटबॉल के महान खिलाड़ी पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी के किस्से सुने जाते हैं। वैसे ये राज्य भी खेलों के मामले में विविधता वाला राज्य है। इसने एक जमाने में बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी दिए तो उम्दा गोल्फर भी। वैसे अब यहां की पहचान सौरव गांगुली से ज्यादा है, जिन्होंने भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर टीम को सफलता के उस शिखर तक पहुँचाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि बंगाल ने पंकज राय जैसा बेहतरीन सलामी बल्लेबाजी भी दिया, जिसने पहले विकेट के लिए वीनू मांकड़ के साथ मिलकर रिकॉर्ड बनाया था। महिला क्रिकेट को इस राज्य ने एक से एक क्रिकेटर दिए। झूलन गोस्वामी यहीं की देन हैं। साथ ही टेनिस खेल भी यहां की परंपराओं में रचा बसा है। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने पुरुष टेनिस में कांस्य पदक जीता। ये व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक में पदक सफलता की शुरुआत कही जाएगी। पेस ने अपने लंबे करियर में ना जाने कितनी सफलताएं हासिल कीं। डेविस कप में भारत को विजेता बनाया।

महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद को तो देश कभी भूल ही नहीं सकता, जिन्होंने देश को तब गर्व से भर दिया था जब हम ब्रिटिश राज में थे। झांसी के रहने वाले ध्यानचंद की मौजूदगी में भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड हासिल किया। ध्यानचंद का खेल ऐसा था कि वो जीतीजागती किवंदती बन गए।

बंगाल का पड़ोसी राज्य झारखंड भी खेलों में जबरदस्त नाम कमाने वाले राज्यों में शामिल कहा जाना चाहिए। ये राज्य देश को बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी लगातार देता रहा है। वर्ष 1928 में जब भारत ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था, तो उस टीम के कप्तान जयपाल सिंह इसी राज्य के थे। जो अब यहां एक बड़ी हस्ती के तौर पर याद किए जाते हैं। झारखंड का नाम लेते ही जिस बेहतरीन क्रिकेटर का नाम तुरंत सामने आता है, वो महेंद्र सिंह धोनी हैं। रांची के धोनी ने कप्तान के तौर पर भारत को जो दिया, वो शायद अब तक किसी कप्तान के हिस्से में आया हो। झारखंड तीरंदाजों का भी राज्य है। दीपिका कुमारी ने अपनी तीरंदाजी से राज्य को पहचान दी है। यहां टाटा ने तीरंदाजी की एकेडमी स्थापित की है, जो आदिवासी इलाके के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान दे रही है।

दिल्ली की बात आमतौर पर क्रिकेट के लिए ज्यादा होती है। ये शहर देश को ना जाने कितने स्टार क्रिकेटर्स देने वाला शहर रहा है। विराट कोहली से लेकर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे शानदार क्रिकेटर इस शहर की देन हैं। जब से देश में क्रिकेट शुरू हुई। देश की राजधानी से हमेशा बेहतरीन खिलाड़ी निकलकर टीम तक पहुँचे।

भारत की आबादी में केवल 0.24 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला मणिपुर राज्य साल 1984 से अभी तक लगभग 19 ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को तैयार कर चुका है, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अकेले टोक्यो ओलंपिक की बात करें, तो छह खिलाड़ी इस बार मणिपुर से ही चुने गए। ये हैं- मेरी कॉम (बॉक्सिंग), सुशीला चानू (महिला हॉकी खिलाड़ी), एस नीलकांता (पुरुष हॉकी), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), देवेंद्रो सिंह (बॉक्सिंग) और एल सुशीला देवी (जूडो)। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि मेरी कॉम और मीराबाई ना केवल ओलंपिक में पदक जीत चुकी हैं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स आयकन हैं। इन दोनों का संघर्ष लंबा रहा और दोनों ही उस पृष्ठभूमि से खेल जगत में ऊंचाई पर पहुँची, जो बहुत अभावों वाला था। उनकी कहानी वास्तव में हर किसी के लिए बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। हालांकि इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा दीवानगी फुटबॉल को लेकर है। उनके लिए बाइचंग भूटिया ऐसे फुटबॉलर हैं, जिनकी छाप पूरे नॉर्थईस्ट के राज्यों में दिखती है। यहां का हर किशोर उनके जैसा खिलाड़ी बनना चाहता है।

कहना चाहिए कि भारत के हर राज्य और हिस्से की खेलों की अपनी खासियतें रही हैं। हर राज्य ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को नई मिसाल दी। खेलों में आने की ललक दी। वैसे खेलों में रोल मॉडल का हमेशा महत्व रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। ■

हमारी पत्रिकाएँ

योजना YOJANA

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अँग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अँग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएँ मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है–
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... ज़िला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

खेलों के बुनियादी ढांचे का विकास

भारत सरकार ने जमीनी स्तर पर खेलों के विकास, पहचानी गई प्रतिभाओं के प्रशिक्षण, विशिष्ट जनप्रतिभाओं के प्रशिक्षण, कोच विकास, खेल विज्ञान सहायता, उन्नत प्रशिक्षण और अन्य पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया है।

राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) की स्थापना 1998 में धर्मार्थ दान अधिनियम 1890 के तहत की गई थी और भारत सरकार ने इसे नवंबर 1998 में अधिसूचित किया था। इस निधि का उद्देश्य भारत में खेलों को गति और लचीलापन प्रदान कर सहायता करना है। यह खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराकर उत्कृष्टता हासिल करने और बुनियादी ढांचे के विकास तथा खेलों को बढ़ावा देने वाली अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देता है।

सरकार ने नवोदित खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचने के लिए विदेशों में कोचिंग शिविरों सहित खेल की बुनियादी और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की है।

अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम

24 फरवरी 2021 को, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जो 1.32 लाख दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। श्री राम नाथ कोविंद ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव की आधारशिला भी रखी। यह स्टेडियम न केवल दुनिया में सबसे बड़ा है बल्कि विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं भी प्रदान करता है। ग्रीन-बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग के साथ, यह पर्यावरण के अनुकूल विकास का भी एक अच्छा उदाहरण है। स्टेडियम नए भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है जिसने विश्व मंच पर एक मजबूत छाप छोड़ी है।

स्टेडियम में 11 पिच हैं, जो दुनिया के किसी भी स्टेडियम से बेजोड़ हैं। चार ड्रेसिंग रूम हैं, इसके अलावा भारी बारिश के बाद भी आधे घंटे के भीतर यहां बिना किसी बाधा के फिर से मैच शुरू हो सकता है। एलईडी लाइटें लगी हैं, जिससे पिच पर खिलाड़ी की परछाई नहीं पड़ेगी और 40 से 50 प्रतिशत बिजली की भी बचत होगी। एक हाई-टेक मीडिया रूम भी बनाया गया है जो यहां आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का दुनिया भर में प्रसारण करेगा।

यह एक ऐतिहासिक स्टेडियम है और यहां कई रिकॉर्ड बने हैं। कपिल देव ने इस मैदान पर रिचर्ड हेडली के 431 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ा था। सुनील गावस्कर ने इस मैदान पर अपने 10,000 रन पूरे किए और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 18,000 रन और अपने क्रिकेट करियर के बीस साल इसी स्टेडियम में पूरे किए।

देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एन्क्लेव 233 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इस एन्क्लेव में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं होंगी। इसमें नारायणपुरा में 18 एकड़ का एक नया खेल परिसर भी शामिल है। इसमें 250 कोचों के लिए आवास होंगे और 3,000 बच्चे एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे।

अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग ज़िले के चायंगताजो में आउटडोर स्टेडियम

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों को विकसित करने तथा बढ़ावा देने के लिए और क्षेत्र के अत्यधिक प्रतिभाशाली युवाओं को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग ज़िले के चायंगताजो में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी है।

392.34 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना को 2015 में मंजूरी दी गई थी। इसमें परियोजना लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर परिषद का था और शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। परियोजना का कार्यान्वयन अरुणाचल प्रदेश सरकार के खेल और युवा मामलों के निदेशालय ने किया था। परियोजना अप्रैल, 2021 में पूरी की गई थी।

लेह, लद्दाख में 12 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न खेल सुविधाओं का शिलान्यास

लद्दाख को जल्द ही एक प्रभावशाली ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम से नवाजा जाएगा। यह स्टेडियम 10 हजार फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बन रहा है और जल्द ही इसका निर्माण पूरा होने वाला है। यह लद्दाख का सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा, जहां 30 हजार दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। लद्दाख के इस आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम में 8 लेन वाला सिंथेटिक ट्रैक होगा। इसके अलावा एक हजार बिस्तरों वाला छात्रावास भी होगा। इस स्टेडियम को फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने प्रमाणित किया है। इतना बड़ा खेल ढांचा देश के युवाओं के लिए बड़े अवसर लाता है। इससे देश भर से लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और पर्यटन तथा रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा और सृजन होगा। स्टेडियम का फायदा लद्दाख के युवाओं को भी मिलेगा। ■

स्रोत: पसूका